₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जून 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO.:- PT.-35

पुल ध्वस्त-जनता पस्त

अधिकारी-मंत्री मस्त

GSTIN : 10KEPD0123PIZP

उत्तर भारत का COOKIE MAKER, सीवान में पहली बार
आपके लिए लेकर आया है
Cookie का बेहतर श्रृंखला

PRATIK ENTERPRISES

राजपुर (रघुनाथपुर) में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रस्क, बिस्कुट, बर्गर, मीठा ब्रेड, वंद, क्रीम रोल, पेटीज और बर्ड डे केक, पार्टी केक ग्राहकों के मनपसंद तैयार किया जाता है।

शुद्धता एवं स्वाद की 100% गारंटी

किसी भी अवसर पर
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

प्रतीक फुड कंपनी

प्रतीक इंटरप्राइजेज, प्रतीक पतंजलि
राजपुर, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

-: सौजन्य से :-

ब्रजेश कुमार दुबे

Mob.-9065583882, 9801380138

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

दिनेश कार्तिक
01 जून 1985

सोनाक्षी सिन्हा
02 जून 1987

स्व०जॉर्ज फर्नांडीस
03 जून 1930

अनिल अंबानी
04 जून 1959

मुकेश भट्ट
05 जून 1952

महेश भूपति
07 जून 1974

शिल्पा शेट्टी
08 जून 1975

किरण बेदी
9 जून 1949

सोनम कपूर
9 जून 1985

सुबोधकांत सहाय
11 जून 1951

किरण खेर
14 जून 1955

शेखर सुमन
14 जून 1960

मिथुन चक्रवर्ती
16 जून 1950

लियंडर पेस
17 जून 1973

राहुल गांधी
19 जून 1970

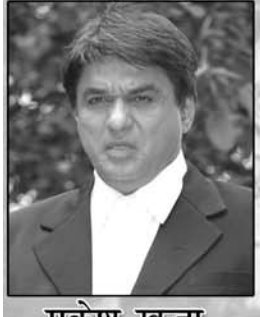

मुकेश खन्ना
19 जून 1958

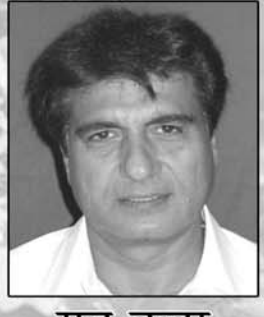

राज बब्बर
23 जून 1952

वीरभद्र सिंह
23 जून 1934

करिश्मा कपूर
25 जून 1974

धर्मेन्द्र प्रधान
26 जून 1969

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

खूंटा ठोक

मोदी ने किया काम

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

गुजरात के **गोधरा कांड** से चर्चित तात्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जब 2014 में लोकसभा के प्रधानमंत्री बने तो उनका हर कार्य को 56 इंच से जोड़ा जाता है। नये संसद भवन का उद्घाटन की तिथि को भी जोड़कर 56 दिखाया गया। भारत देश के भीतर 56" का क्या मतलब होता है यह बात राजनीति में कई बार प्रधानमंत्री **नरेन्द्र दामोदर दास मोदी** ने सीना ठोक कर साबित किया है तथा खूंटा ठोक कर देशहित में कई काम किये हैं जिसकी वजह से विपक्ष के लिए वह हमेशा नासूर बना रहेगा। कई दशकों पुराना जम्मू - कश्मीर विवाद धारा - **370 को हटाना**, मुस्लिम महिलाओं के लिए **तीन तलाक को समाप्त** करना, 500 वर्ष पुराना भगवान श्रीराम जन्मभूमि विवाद समाप्त एवं **राम मंदिर का निर्माण पूर्ण**, घुसपैठिये के विरूद्ध **एनआरसी - सीएए**, काशी विश्वनाथ मंदिर को विकसित करने तथा मथुरा को भी मस्जिद से आजाद कराने की कूटनीति भी उत्तरप्रदेश में हावि हो चुका है। आजादी के बाद 2024 में पहला ऐसा मौका होगा जहां ताल ठोक कर लोकसभा का चुनाव होगा और अब इस राजनीति में नेताओं के साथ-साथ देश के नामचीन कथावाचक एवं संत भी खुलकर इसका मोर्चा खोल चुके हैं। भारत देश के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का 56" का प्रभाव साफ- साफ दिखता। मोदी ने जो भी ठाना उसको सीना ठोक कर पूर्ण करते हैं जिसकी वजह से सनातन धर्म को मानने वाले मोदी की महंगाई एवं एससी/एसटी एक्ट को भी दरकिनार कर देते हैं और कहत हैं कि मोदी है तो सबकुछ मुमकिन है।

चुनौती का सामना करना और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसपर खरा उतरना वास्तव में अजूबा ही कहालेगा। कट्टर हिन्दूवादी छवि के कारण 2014 में एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र दामोदर दास मोदी को उम्मीदवार बनाकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गयी तथा ताल ठोककर **56 इंच** का एहसास देशवासियों को कराया कि जो कहूंगा वह करूंगा। पूरे देश में भगवा रंग का परचम छाने लगा और ''अबकी बार-मोदी सरकार'' के नारे ने कई राज्यों में भाजपा की एवं उसके गठबंधन की सरकारें बनने लगी। **जय श्रीराम** का जयघोष और मंदिर निर्माण की तारिख पूछने वाले पत्रकार एवं विपक्षी दलों को तिथि नहीं बतायेंगे का खूंटा ठोक कर जवाब दिया की लो मंदिर निर्माण की तिथि। कैंसर की बिमारी की तरह कभी न समाप्त होने वाला **धारा- 370** को 05 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया और तमाम तरह की चुनौतियों के बाद पाकिस्तान की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए खूंटा ठोकर समाप्त कर दिया। मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कश्मीर के **लाल चौक** पर भारतीय तिरंगा को फहराना और **वंदे मातरम्** की जयघोष ने हर भारतीय के सीने में मोदी की प्रति समर्पित बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा को जड़ से उखाड़ फेंकने एवं उनके अस्तित्व को बचाने को के लिए 30 जुलाई 2019 को **तीन तलाक** के मुद्दे को एक ही झटके में समाप्त करके जहां मुस्लिम महिलाओं को वास्तविक आजादी से परिचय कराया तो विपक्षों की छाती पर मुस्लिम महिलाओं के वोट के खेल का ताला बंद कर दिया। भारत कहने के लिए तो धर्मनिरेपक्ष है पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के बीच हिन्दू और मुस्लिम के अलावा अन्य धर्म सिर्फ भाईचारे का प्रतीक बनाकर कोई हिन्दू तो कोई मुस्लिम की राजनीति करके देश को अलग-अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास करने वाले सूरमाओं को तब झटका लगा जब मोदी गुजरात के बजाय बनारस को अपना संसदीय क्षेत्र बनाकर **काशी विश्वनाथ मंदिर की समस्या** को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया और मथुरा का मुद्दा को भी कूटनीति से समाप्त करने की पुरजोर कोशिश को भारत के सनातन धर्म को मानने वाले का विश्वास जीत लिया है। भारत के भीतर घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए भी खूंटा ठोकर **सीएए एवं एनआरसी** जैसा कानून को लागू कर दिया जिससे यह मामला भी प्रकाश में आया है कि पश्चिम बंगाल में बांगलादेशी विधायक बन गयी। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए उसके बाद देश के भीतर आतंकवादी हमला पर भी अंकुश लगा तथा 18 सितंबर 2016 के **पुलवामा अटैक** का बदला **सर्जीकल स्ट्राइक** 28-29 सितम्बर 2016 को ही पाकिस्तान में 3 किलोमीटर भीतर घूंस कर ले लिया। इस स्ट्राइक ने न सिर्फ देशवासियों का विश्वास जीता बल्कि पाकिस्तान की औकात खूंटा ठोकते हुए नाप दी, भले ही विपक्षी दल सर्जीकल स्ट्राईक का भी प्रमाण मांगते रहे। सबसे अधिक इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरबिन्द केजरीवाल ने सबूत मांगे थे लेकिन एक आम आदमी का नेता अपने मकान के सजावट में करोड़ों रूपये बहा दिये इसका सबूत देने पर केजरीवाल चुप हो जाते हैं। मोदी का **स्वच्छ भारत अभियान** हो या फिर हर घर शौचालय एवं उज्जवला योजना को देश के कोने कोने पहुंचा कर आम आदमी को उचित सम्मान दिलाया। भ्रष्टाचार एवं कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए खूंटा ठोक कर 08 नवंबर 2016 को 500 एवं 1000 का नोट को रात के 12 बजे से बंद कर दिया। तमाम प्रकार के टैक्स से परेशान देश की जनता को बचाने के लिए खूंटा ठोकते हुए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया भले ही विपक्षी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की गयी लेकिन जब मोदी एक बार ताल ठोक देते हैं तो उसको खूंटा ठोकर देश के भीतर लागू करवा देते हैं। मोदी ने अपने 9 साल के प्रधानमंत्री के काल में खूंटा ठोकते हुए नोटबंदी, जीएसटी, तीन तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा-370 समाप्त करना, रेल बजट का आम बजट में विलय, उज्जवला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत सहित डीजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, मेक पद इंडिया, वंदे मातरम सहित देश को आजाद भारत में बना संसद भवन दिया। मोदी ने जो भी ठाना उसको खूंटा ठोकर लागू भी करवा लिया जिसमें नये संसद भवन का उद्घाटन भी मोदी ने अपनी तय तिथि 28 मई 2023 को तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद कर दिया और विपक्ष सिर्फ मुंह ताकता रहा तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी उदघाटन का याचिका खारिज कर दिया। तमाम जांच एजेसिंया मोदी के ईशारे पर विपक्षी दलों पर कार्रवाई करती है के आरोप के बाद भी एक के बाद एक विपक्षी जांच के रडार पर हैं क्योंकि मोदी कहते हैं कि न खाउंगा और न खाने दूंगा। आजाद भारत में खूंटा ठोक कर काम करने वाला प्रधानमंत्री देश को मिला जो खुंद को हिन्दू भी घोषित करता है।

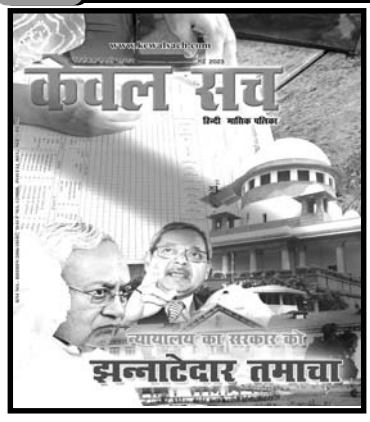

मई 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :- **द्वारा:- ब्रजेश मिश्र**

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

वोटकटवा

संपादक जी,

मई 2023 अंक में केवल सच, पत्रिका में अमित कुमार की खबर ''**चिराग के लिए अहम होगा अगला चुनाव, क्या वोटकटवा ही बने रहेंगे?**'' में बिहार के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी का सही मूल्यांकन किया गया है। चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बिहार में लाचार पार्टी बनाकर छोड़ दिया था तथा भाजपा के हनुमान की भूमिका में हैं का आरोप भी चिराग झेल चुके हैं। मुझे इस अंक का सभी खबर एक पर एक लगा।

✦ मुंशीलाल सिन्हा, मानपुर, गया (बिहार)

रामायण-महाभारत

ब्रजेश जी,

डॉ० छाया मंगल मिश्र ने मई 2023 अंक में पृष्ठ संख्या-94-95 में रामायण बनाम महाभारत के दो ग्रंथों की भिन्नता और समानताएं पर सटीक व्याख्या की है तथा धार्मिक जटिलता को समझाने का सार्थक व सराहनीय प्रयास किया है। कुछ लोग रामायण को पूजते हैं तो कुछ लोग महाभारत ग्रंथ को घर में रखना तक पसंद नहीं करते क्योंकि दोनों ही धार्मिक ग्रंथ का अपना-अपना महत्व है। एक मर्यादा का स्मरण कराता है तो दूसरा भूमिका पर प्रकाश डालता है। मुझे यह खबर काफी आत्मीय लगा। लेखक को हार्दिक बधाई।

✦ सुरेश अग्रवाल, अपर बाजार, राँची, झा०

आओ खेंले

मिश्रा जी,

बेबाक लेखनी और निष्पक्षता के साथ आपका प्रत्येक माह का संपादकीय रहता है। मई 2023 अंक में ''आओ खेंले, हिन्दू-मुस्लिम'' संपादकीय में आपने राजनीतिक पार्टियों का सच को सबके सामने रखा है तथा यह उचित लिखा है कि मुस्लिम वोट के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है चाहे वह दल कोई भी हो। भारत देश में हिन्दू - मुस्लिम की कूटनीति से दोंनों धर्मो के बीच तनाव का वातावरण है और राजनेता इसको भरपूर फायदा उठाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी संपादकीय में फोकस किया गया है। मुझे काफी सटीक व दमदार आलेख लगा।

✦ मो शमशाद, टावर चौक, मुंगेर

झन्नाटेदार तमाचा

मिश्रा जी,

''न्यायालय का सरकार को झन्नाटेदार तमाचा'' आलेख में पत्रकार शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला ने बिहार सरकार के द्वारा कराये जा रहे जातिगत जनगणना को माननीय सर्वोच्च एवं पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया जिससे बिहार के मुख्यमंत्री की स्वार्थ का पर्दाफास हुआ है। केन्द्र सरकार के विशेषाधिकार में घुसकर अपनी मजबूत पकड़ का एहसास की कोशीश में नीतीश कुमार विफल हो गये। बिहार के खजाने को बर्बाद करने की कोशिश में मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए है। पूर्ण विस्तार लिखा गया आलेख जनहित के लिए है।

✦पंकज शर्मा, साकेत बिहार कॉलोनी, नई दिल्ली

लूट का अड्डा

संपादक जी,

आज की पत्रकारिता जी हजूरी की बन चुकी है वैसे में केवल सच पत्रिका के पत्रकार शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला ने राजधानी पटना के राजीव नगर थाना प्रभारी एवं दीघा थाना प्रभारी के काली-करतूत को पूर्ण बेबाकी से बिना डरे हुए उजाकर किया है। शराबबंदी के बाद वास्तव में किसी थाना प्रभारी की कमाई किसी भी विभाग के मंत्री से कहीं ज्यादा हो रहा है। भगवान ऐसे पत्रकारों की रक्षा करे जो जनहित में पुलिस की सच्चाई को आवाम एवं सरकार के बीच लाने का प्रयास कर रहा है। ''लूट का अड्डा बना राजीव नगर थाना'' एकदम सही है।

✦ किशोर पासवान, राजा बाजार, जहानाबाद

महागठबंधन

संपादक जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और मई 2023 अंक में बिहार की राजनीतिक खबर पर अमित कुमार की सटीक समीक्षा ''महागठबंधन के खेवनहार नीतीश खूब बहा रहे हैं पसीना'' में बिहार की राजनीति देश की राजनीति पर कैसे प्रभावकारी बनेगी और नरेन्द्र मोदी को कैसे पछाड़ेंगे की कूटनीति पर भी फोकस करता हुआ खबर है। महागठबंधन नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकार करेगा या नहीं या फिर महागठबंधन चुनाव के पहले 2019 की तरह बिखर जायेगा पर भी कारगर जानकारी दी गयी है। केवल सच की यह खबर वर्त्तमान समय पर सटीक है।

✦ महन्द्र यादव, सुल्तानपुर बाजार, भागलपुर

अन्दर के पन्नों में

10

27

36

बाल श्रम : मजबूरी या जरूरी...71

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18, | अंक:- 205, | माह:- जून 2023, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505/8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उपसंपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-	निलेश कुमार	9113384406
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636-9631490205

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 7654122344-7979769647

अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

संयुक्त संपादक

राजीव कुमार9431369995, 7280999339

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

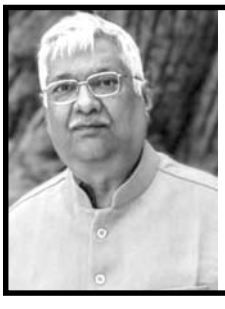

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000, 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

विपक्षी एकजुटता महज एक दिखावा!

सीएम नीतीश द्वारा आयोजित बैठक तीसरी बार भी फेल

● **अमित कुमार**

विपक्षी दलों की 12 जून को होने वाली बैठक टाल दी गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की रणनीति पर चर्चा के लिए पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर ग्रहण लग गया है। दिगर बात है कि देशभर में होने वाले आम चुनाव से पहले विपक्ष दलों को एक करने की कवायद जितनी तेजी के साथ शुरू हुई, उसी स्पीड से हर कोशिश दरकती भी चली गई। विपक्षी एकता की राह में लगता है अभी कई रोड़े हैं। सनद् रहे कि सितंबर 2022 से नीतीश कुमार दलों को जोड़ने के लिए यात्राएं कर रहे थे। अभी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उनकी इस मुहिम में और तेजी आई है। वह मई में ही दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करके लौटे थे। इसके बाद 12 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक का ऐलान किया गया। बता दें कि कांग्रेस और डीएमके के अनुरोध पर यह बैठक स्थगित की गई। राहुल गांधी अभी विदेश यात्रा पर हैं जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने-अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते 12 जून की बैठक में शरीक होने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस तरह से विपक्षी दलों के मुखियाओं की डेट्स नहीं मिलने के चलते नीतीश की महाजुटान का मुहूर्त एक बार फिर टल गया है। राजनीतिक विश्लेषक बैठक टलने के पीछे की वजह दूसरी मान रहे हैं।

गौरतलब है कि बैठक का टलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी विपक्षी एकता की बैठक तीसरी बार टली है। पहली बैठक 19 मई को होनी थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव और वहां पर कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के चलते विपक्षी दलों की बैठक टाल दी गई। इसके बाद मई के आखिरी सप्ताह में बैठक होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद 12 जून को पटना में बैठक की रूप रेखा बनी थी। 12 तारीख को लेकर सभी विपक्षी दलों ने सहमति भी जता दी थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एमके स्टालिन उस तारीख को पटना आने में असमर्थ थे। तमिलनाडू सरकार डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि की शतवार्षिकी पर साल भर के लिए समारोह का आयोजन कर रही है। 12 जून को इसी से संबंधित एक बड़े समारोह में स्टालिन को अपने राज्य में ही रहना है। वही राहुल गांधी के अमेरिका में होने के चलते कांग्रेस की ओर उनके बदले कोई राष्ट्रीय महासचिव शामिल होने

का आग्रह किया गया था, जिसको नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया और बैठक को स्थागित कर आगे बढ़ा दिया है। संभवत: 23 जून को पुन: बैठक की संभावना बन सकती है, ऐसी खबर सुनने को मिल रही है।

बहरहाल, मिशन-2024 में विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल के लिए स्थागित कर दी गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों के प्रमुखों इसमें शामिल हों। ये सही नहीं होगा कि बैठक में पार्टी के अध्यक्ष के बजाय उनका कोई प्रतिनिधि शामिल हो। हमने कांग्रेस को भी कहा है कि आपस में बात कर तय कर लीजिए, उसके बाद जो भी तारीख तय होगी, उस दिन बैठक होगी, लेकिन सभी पार्टियों के प्रमुख शामिल हों। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी के ज्यादातर दलों के प्रमुखों ने 12 जून की बैठक में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन दो से तीन दल की कुछ दिक्कतें थी, इसीलिए 12 की बैठक को स्थागित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी हाल में इस बैठक को करना चाहते हैं। सभी पार्टियों की सहमति भी है, लेकिन एक-दो अड़चन की वजह से लगातार यह बैठक स्थगित होती रही है। राहुल गांधी अमेरिका में हैं जबकि एम.के. स्टालिन पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त हैं। नीतीश ने साफ तौरपर कहा कि सभी विपक्षी दलों के मुखिया बैठक में शामिल हों। वही विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को शामिल करने में सफल रहे हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ

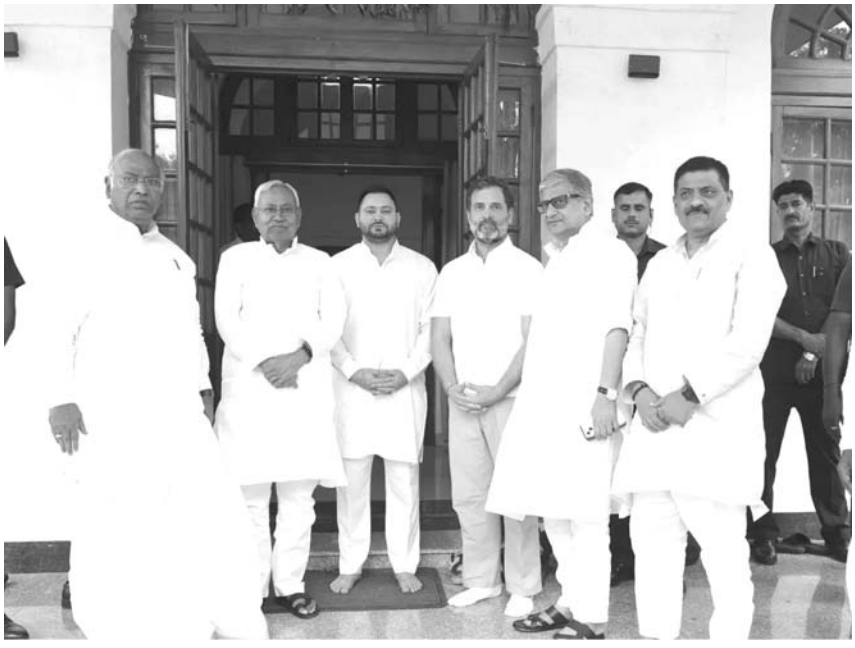

आक्रामक रहे हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा था कि उन्हें कांग्रेस के होने पर कोई एतराज नहीं है तो सपा अखिलेश यादव के भी सुर बदले हैं। संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार में विपक्षी एकता की झलक दिखी है, जहां कुछ विपक्षी दलों को छोड़कर बाकी दलों के नेता शामिल नहीं हुए थे। विपक्ष के ज्यादातर दल इस बात पर सहमत हैं कि मजबूत क्षेत्रीय दल 2024 में अपने अपने इलाकों में बीजेपी का मुकाबला करेंगे और बदले में, वे 200 से अधिक सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी से सीधे मुकाबले में उतरने देंगे। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और केसीआर इसी फॉर्मूले पर बात करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीते महीने से जारी अपने दौरों में नीतीश कुमार 12 अप्रैल को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिले थे। 13 अप्रैल को लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से भी मिले। 24 अप्रैल को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिले, तो 31 अप्रैल को तेलंगाना के सीएम केसीआर से नीतीश ने मुलाकात किया था। 9 मई को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, 10 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 11 मई को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश

चौटाला,आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर 2024 में एकजुट होने की रणनीति पर चर्चा की थी।

बताते चले कि विपक्षी एकता में सिर्फ नवीन पटनायक की बीजेडी और मायावती की बसपा ही दूर हैं। दोनों ने बहुत पहले ही कह दिया है कि वे विपक्षी एकता की किसी भी मुहिम में शामिल नहीं होंगे। बसपा प्रमुख मायावती की अपनी मजबूरियां हैं लेकिन बाकी विपक्ष नवीन पटनायक के रवैए पर हैरान है। नवीन पटनायक नीति आयोग की बैठक से दूर रहे लेकिन वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। बताते चले कि नवीन पटनायक ने नीतीश से मुलाकात के बाद ही अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो किसी भी विपक्षी एकता में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद को किसी भी गठबंधन के साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए जबकि बाकी जो दल नीतीश के साथ है, उनकी तारीख तय नहीं हो पा रही है। वही नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी की बात मानते हुए पटना में विपक्षी दलों की बैठक तो बुला ली है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और राहुल गांधी के बैठक में शामिल होने से पीछे हट गए। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल अपनी स्वीकृति दे दी थी। ममता ने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि पटना में होने वाली विपक्ष की एकता की बैठक से हिंदी बेल्ट में बेहतर असर होगा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। अब सवाल है कि विपक्षी एकता की बैठक क्यों टाली गई है और यह कब होगी, इसे लेकर कोई जानकारी को सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह एक बार फिर नीतीश कुमार के अरमान पर धुंध छाती नजर आ रही है। नीतीश कुमार बीते साल से जबसे बीजेपी और एनडीए से अलग होकर दोबारा सीएम बने हुए हैं, वह केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए हैं। इसका हल उन्हें सिर्फ विपक्षी दलों की एकता में दिख रहा है। सीएम नीतीश अभी जिस एजेंडे पर चल रहे हैं, उसके मुताबिक अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। बता दें कि विपक्षी दलों की राष्ट्रीय स्तर की यह बैठक थी। देश भर से विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होना था। जाहिर है कि नीतीश ने यह तारीख अपने मन से तो तय नहीं की होगी। उन्होंने तारीख को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से जरूर विमर्श किया होगा। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता उस दिन उपलब्ध नहीं रहेंगे, यह स्थिति कांग्रेस में अचानक पैदा नहीं हुई होगी। राहुल गांधी का अमेरिका जाना बैठक की तारीख तय होने से पहले ही निश्चित हो गया था। खरगे को भी अपनी व्यस्तता का भान जरूर रहा होगा। अगर ऐसा था तो बैठक की तारीख तय करनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़ने के साथ इस पर भी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उन छोटे और क्षेत्रीय दलों को भी एकजुट किया जा सके, जो कांग्रेस के साथ जाने से कतरा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का इस मीटिंग से दूरी बनाने बैठक का असल उद्देश्य मुकम्मल नहीं होता दिखता है। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर कहा था कि, एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला लें।

दिगर बात है कि पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष

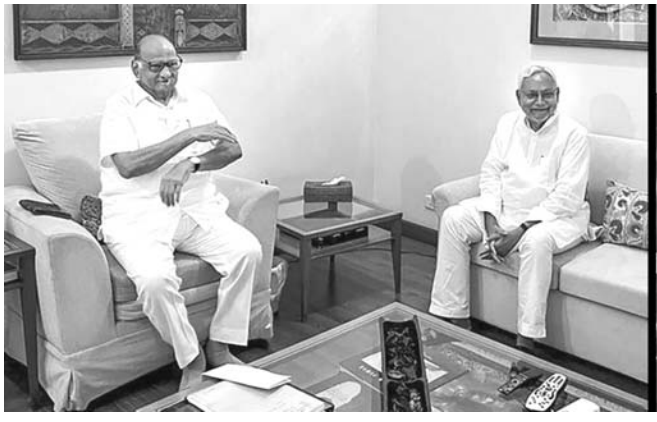

ममता बनर्जी ने यह शर्त रख दी थी कि जो दल जिस राज्य में मजबूत हैं, कांग्रेस को वहां उनकी मर्जी पर सीटें दी जाएंगी। उन्होंने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए दिल्ली, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों के नाम भी गिनाए थे। ममता कांग्रेस को बिदकाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहतीं। हाल ही में उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के एकमात्र विधायक बायरन विश्वास को टीएमसी में शामिल करा लिया। यह तब हुआ, जब विपक्षी एकता की बैठक परवान चढ़ रही थी। कांग्रेस को ममता का यह आचरण यकीनन अच्छा नहीं लगा होगा। यूपी में विधान परिषद के उपचुनाव में भी सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस की खींचतान सामने आई थी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार किया तो सपा अकेले मैदान में डटी रही। हालांकि उसे इसका कोई फायदा नहीं मिला। सपा के उम्मीदवार हार गए और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। हालांकि विपक्षी दलों की आपस में ही खींचतान, लोकसभा चुनाव में 200 से 250 सीटों पर लड़ने का कांग्रेस पर दबाव और सभी विपक्षी दलों का एक मंच पर नहीं आना, विपक्षी दलों की बैठक टलने के मुख्य कारण हैं। राहुल और खरगे को यह पता है कि विपक्ष में आज कांग्रेस सबसे ताकतवर है। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सरकारों का हिस्सा है। ऐसे में वह किसी दबाव में नहीं रहना चाहती है। शायद यही वजह रही हो कि कांग्रेस ने पहले बैठक में राहुल गांधी और खरगे के भाग न लेने की बात कही और अब उनके इंतजार में बैठक की तारीख टरका दी गई। नीतीश कुमार को भी अपनी फजीहत का एहसास जरूर हुआ होगा।

इसलिए उन्होंने बैठक की तारीख टाल दी हो। वही आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का लफड़ा तो अब जगजाहिर है। नीतीश से पहली बार की मुलाकात में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता में साथ रहने का भरोसा दिया। हफ्ते भर के अंदर आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि वह किसी दल या गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। कई और राज्यों में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। नतीजतन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। आप का यह अंदाज भी चौंकाने वाला था। हालांकि इस बीच केंद्र ने सेवा अध्यादेश लाकर आप को परेशानी में डाल दिया। अब उसे खुद विपक्ष के साथ की जरूरत महसूस होने लगी। केजरीवाल घूम- घूमकर विपक्षी दलों से मिलने लगे। नीतीश से दिल्ली में ही उन्होंने अध्यादेश पर साथ का वचन ले लिया था। बाद में वे बंगाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी इसी

मकसद से मिले। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का दरवाजा भी खटखटाया। सबने हां कह दी। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी रही, जिसने केजरीवाल को मिलने का वक्त नहीं दिया। उल्टे पंजाब, दिल्ली और गोवा के अपने नेताओं के दबाव में खरगे ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ आप को नहीं मिलेगा।

हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी एकता से परहेज नहीं है, लेकिन वह विपक्ष की 200-250 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह से असहमत है। किसी भी हाल में कांग्रेस 350 सीटों से कम पर लड़ने को राजी नहीं है। कांग्रेस ने साल 2004 में 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 145 सीटें मिली थीं। 2009 में 440 पर लड़ कर कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थीं। 2014 में पार्टी ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा तो कामयाबी 44 सीटों पर ही मिली। साल 2019 में भी कांग्रेस ने लोकसभा में 421 उम्मीदवार उतारे थे और 52 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 2009 को बेंच मार्क मान कर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी वह समझौते में किसी भी तरह 350 से 400 सीटें विपक्षी दलों से चाहती है। इधर विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस ममता की शर्त अगर मान ले तो उसे शेयर में अधिकतम 200 से 250 सीटें ही मिल पाएंगी। कांग्रेस इसे कत्तई पसंद नहीं करेगी। इसलिए बैठक टलने की वजह राहुल व खरगे की अनुपलब्धता नहीं, बल्कि सच यह है कि कांग्रेस ने ही बैठक से पैर पीछे खींच लिया है। कांग्रेस को भी लगा होगा कि विपक्षी दलों की बैठक में जाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि वही राग क्षेत्रीय दल बैठक में भी अलापेंगे, जो बातें संकेतों में अभी कह रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपनी फजीहत से बचने के लिए राहुल और खरगे की अनुपलब्धता को कारण बता रहे हैं। हालांकि, नीतीश कुमार बार-बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि उन्हें बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए उन्हें सिर्फ 100 सीटों पर बीजेपी को हराना है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, वहां महागठबंधन बनाया जाए और बीजेपी के खिलाफ बस एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। इसमें मुख्य रूप से यूपी की 80, बिहार की 40, बंगाल की 42, महाराष्ट्र की 48, दिल्ली 7, पंजाब की 13 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं।

बहरहाल, नीतीश कुमार साफ तौरपर कह चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता कतई संभव नहीं है। बिहार का उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि जिस तरह बिहार में सभी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं, उसी तरह से देश में भी विपक्षी एकता बननी चाहिए। इस कड़ी में उन्होंने देशभर के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर विपक्षी एकता का तानाबाना बुन रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पटना में बैठक बुलाई थी ताकि एक बड़ा सियासी संदेश दिया जा सके, लेकिन कई विपक्षी के प्रमुखों के कदम पीछे खींच लेने और खुद की जगह अपना प्रतिनिधि भेजने के प्रस्ताव को नीतीश ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में देखना है कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कवायद क्या सियासी रंग लाती है?●

पुल निर्माण पर 1710 करोड़ का भ्रष्टाचार

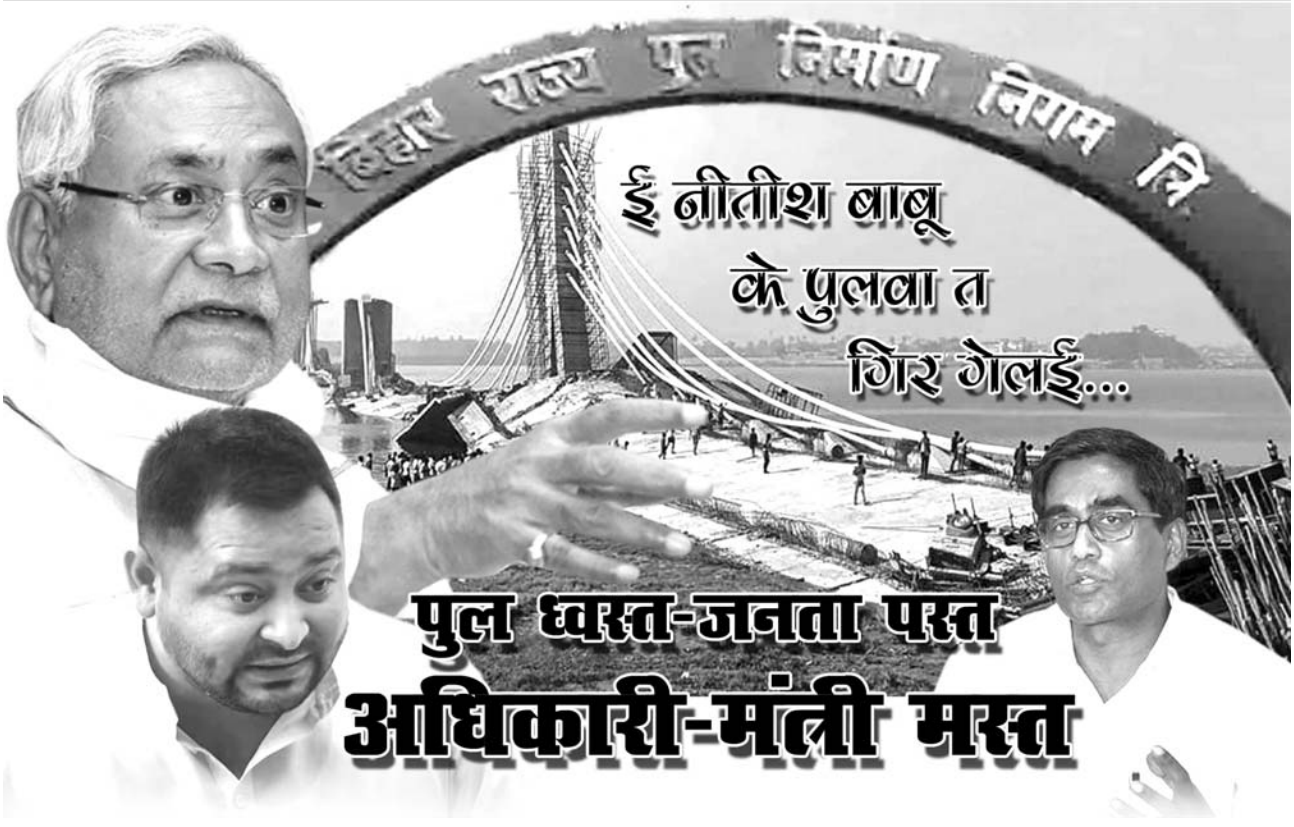

सुल्तानगंज-अगुवानी पुल के ध्वस्त होने का जिम्मेदार कौन?
रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड या एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी?

● **शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला**

कभी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई ने भरी सांसद में कहा था कि सत्ता आती जाती रहेगी लेकिन यह देश सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन बिहार में भाजपा, जदयू, राजद ने इसे नया नारा दिया है- 'सत्ता आएगी जाएगी लेकिन भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिए'। भागलपुर में स्थित सुल्तानगंज-अगुवानी पुल में यह फार्मूला बिल्कुल फिट बैठता है। राजद-भाजपा के शासन में शुरू हुआ पुल निर्माण भाजपा-जदयू शासन में चलता रहा फिर राजद-जदयू कार्यकाल में भी चल रहा है। संयोग देखिए, भाजपा-जदयू कार्यकाल में भी पुल का हिस्सा पानी में गिर गया और राजद जदयू कार्यकाल में भी पुल का हिस्सा पानी में समा गया। अभी तक सभी लोग पूर्ण निर्माण कंपनी को ही दोषी मान रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, प्रथम दृष्टा घटिया निर्माण करने वाली कंपनी ही दोषी होती है।

पुल निर्माण में डिजाइनर कंपनी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कई तकनीकी विशेषज्ञ इसके डिजाइन पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुल्तानगंज-अगुवानी पुल का डिजाइन रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड बिहार के अधिकारी से मित्रता कौन नहीं जानता है। रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड, बिहार राज्य सड़क निगम लिमिटेड सहित कई विभागों का डिजाइनर कंसलटेंट है। बिहार के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी जिस-जिस विभाग में गए वहां या तो नियमों को शिथिल कर दिया या नियमों को बदलकर रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आवंटित किए गए हैं। सुल्तानगंज-अगुवानी पुल के ही तरह विक्रमशिला के समानांतर बन रहे सिक्स लेन पुल का भी डिजाइन रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। पटना के मरीन ड्राइव का भी डिजाइन रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह तो एक चर्चित डिजाइन है बाकी राज्य के कई पुलों और सड़कों

का डिजाइन रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजकुमार और मनोज कुमार से उक्त अधिकारियों को देश से दूर अमेरिका में खूब जमती है। कुल मिलाकर रोडिक कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड और एसपी सिंघला ने मिलकर बिहार के जनता के सीने पर सीने में खंजर मारा है।

बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। हुआ यूं कि भागलपुर में सुलतानगंज-अगुवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन फोरलेन पुल एक बार फिर से जमींदोज हो गया। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया और पुल के चार पिलर भी नदी में समा गए। बता दें कि पुल का करीब 400 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। पुल का बड़ा स्ट्रक्चर गंगा में गिरने से 50 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठीं। इससे नाव से सफर कर रहे लोग दहशत में आ गए। किसी तरह से नावों को किनारे लाकर लोगों को निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ब्रिज गिरने से करीब दो किलोमीटर दूर तक आवाज आई। इतना ही नहीं इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठीं। गंगा में करीब 500 मीटर में मलबा बिखर गया था। पुल गिरने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हो रहा पुल जमींदोज हो गया। ब्रिज देखते ही देखते ताश के महल की तरह गिर गया। पहले निर्माणाधीन पुल का ये छोटा सा हिस्सा गिरता है, इसके चंद सेकेंड के भीतर 200 फीट का लंबा स्लैब गंगा नदी में समा जाता है। गंगा में पुल का हिस्सा समाते ही धड़ाम की आवाज आती है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को खगड़िया जिले के परबत्ता में पुल निर्माण की आधारशिला रखी थी। बीच में मांझी सीएम बने तो उसके बाद काम रुक गया था। हालांकि, नीतीश के दोबारा सीएम बनने के बाद 9 मार्च 2015 को पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था। पहले इसे मार्च 2019 में पूरा होना था, लेकिन बाद में सेकेंड डेडलाइन मार्च 2020 की गई। फिर कोरोना के चलते डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2022 की गई। मार्च में भी काम पूरा नहीं हुआ, तो डेडलाइन दिसंबर 2022 की गई। लेकिन तब भी पुल पूरा नहीं बन सका, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हुआ। इसके बाद पुल को मार्च 2023 तक पूरा करने की डेडलाइन रऽी गई। इसके बाद जून 2023 में छठी डेडलाइन भी फेल हो गई। इसके बाद पुल को दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब पुल का बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया है। इस पुल की लंबाई 3-16 किलोमीटर है। गंगा नदी पर बन रहा ये फोर लेन पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। यह पुल अगुवानी और सुल्तानगंज घाट के बीच बन रहा है। यह बरौनी-खगड़िया एनएच 31 और दक्षिण बिहार के मोकामा, लखीसराय, भागलपुर, मिर्जाचौकी एनएच 80 को जोड़ेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर बिहार के खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से चार किलोमीटर लंबी एप्रोच रोड के जरिए उत्तर बिहार सीधे मिर्जा चौकी के रास्ते झारखंड से जुड़ जाएगा। पुल बनने के बाद खगड़िया से भागलपुर आने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाएगी। सनद् रहे कि अगवानी घाट पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऽबरों के मुताबिक पुल का स्ट्रक्चर गिरने के दौरान कई लोगों की जान बाल-बाल बच गई। वही भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि अगुवानी-सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल के 4-5 खंभे गिर गए हैं। प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है।

बिडम्बना है कि यह दूसरी बार है जब यह पुल गिरा है। इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर पिछले साल 27 अप्रैल को नदी में गिर गया था। तीन पिलर्स के 36 स्लैब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभराकर ढह गया था। रात में काम बंद था, इसलिए जानहानि नहीं हुई थी। उस समय पुल निगम के एमडी के साथ एक टीम ने वहां जाकर जांच भी की थी। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर शुरू हुआ। इस बार करीब 80 प्रतिशत काम सुपर स्ट्रक्चर का पूरा हो गया था। इतना ही नहीं अप्रोच रोड का काम भी 45 फीसदी पूरा कर लिया गया है। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। 1711 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। ब्रिज गिरने के बाद कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। यहां तक कि बिहार में कंपनी को बैन करने की भी मांग उठ रही है- हालांकि,

राज कुमार

मनोज कुमार

कंपनी देश में कई नदियों पर पुल बना चुकी है। जबकि कई पुल कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं। एसपी सिंगला कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, कंपनी ने देशभर में अब तक 25 ब्रिज बना चुकी है, जबकि 8 ब्रिज पर काम जारी है। कंपनी ने बिहार में अरवल और सहरसा में भी पुल बनाए हैं।

बहरहाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पुल टूटने से मुझे काफी दुख हुआ है। एक दुखद घटना है। इससे जुड़े हर एक मामले में जांच करवाई जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैंने कल ही इसको लेकर अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मामले की विस्तृत जानकारी ली है। विस्तृत जांच करने के बाद दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो निर्माण एजेंसी को भी बदला जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर में जो हुआ है, कुछ समय पहले भी हुआ था। उसी समय हमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। जबकि इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 2012 में ही बोला था 2014 से काम शुरू हुआ। जिस भी एजेंसी को यह काम दिया गया है इतना देर क्यों हो रहा है? इससे पहले जब गिर गया था तो उस समय भी मैंने कहा था। अब यह वापस फिर से गिरा है कल ही हमको पता चला है। तो तुरंत हमने विभाग के सभी अधिकारियों से कहा कि जाकर देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। यह कोई तरीका नहीं है अब तक तो हो जाना चाहिए था पुल का निर्माण। बहुत-बहुत वत्तफ हो गया है, देर हो गया है। अगर समय पर हो गया रहता तो काहे के लिए ऐसा कोई खबर आता। हमको बहुत बड़ा तकलीफ हुआ है। सीएम ने कहा कि पुल ठीक से नहीं बना रहा है तभी ना गिर जा रहा है भाई। अगर ठीक से बनाया होता तो कैसे गिर जाता? इसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, जब पहली बार गिर गया था तो और अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। अगर समय पर तैयार हो जाता तो लोगों को कितनी खुशी होती है। हम कितना पहले जाकर एक-एक चीज को देखकर करवाए हुए हैं लेकिन अब तक नहीं हुआ। हमको कितना तकलीफ हुआ। अब विभाग इसको देख लेगा हमारे मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी है। इसके बाद सीएम से सवाल किया गया कि कार्रवाई होगा क्या तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम बोल दिए हैं कि एक्शन होगा। इसलिए इसको लेकर चिंता मत कीजिए।

वही प्रत्यय अमृत ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालेगी जिसे प्रोजेक्ट का ठेका दिया गया था। इसके साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी करेगी। महज एक साल के बाद अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का हिस्सा गिर जाने से लोगों ने पूल निर्माण के गुणवत्ता पर सवाल उठना शुरू कर दिया है। कोई एसपी सिंगला ग्रुप पर घटिया निर्माण करने का आरोप

लगा रहा है तो कोई बिहार में निर्माण योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। वहीं परबत्ता के विधायक डां- संजीव ने कहा गुणवत्ता पर पहले भी सवाल उठाया था और अब भी उठा रहा हू। यह पुल बगैर किसी कारण के कैसे गिर सकता है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।

गौरतलब है कि बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में अगवानी गंगा घाट पर बन रहा पुल भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर उभरा है। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला भ्रष्टाचार का सेतु 4 जून की शाम को भरभरा कर नदी में बह गया था। वही आरोप लग रहे हैं कि वहां गार्ड की डड्यूटी करने वाला शख्स हादसे के बाद से लापता है। पुल के आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मियों का कहना है कि इस घटना में उनके कई लोग लापता हैं, जिसकी जानकारी प्रशासन की ओर से छुपाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल, भ्रष्टाचार के इस पुल को लेकर अब तक कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। चर्चाएं यह है कि इस पुल के निर्माण में धांधली और भ्रष्टाचार का एक बड़ा हिस्सा स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अधिकारी के पास पहुंचा है। यह भी आरोप लग रहे हैं कि इस पुल में भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा सौंपने में भी धांधली हुई है। बताया जा रहा है की सिंगला नाम की कंपनी को इस पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त दिया गया जब यह कंपनी टेंडर लेने के लिए लिस्टेड ही नहीं थी। इतना ही नहीं यह कंपनी प्रतिबंधित थी, बावजूद एसपी सिंगला को पुल निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर या किसके दबाव में यह कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दी गई जो लिस्टेड ही नहीं थी। भ्रष्टाचार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 महीने पहले भी यह पुल हवा के झोंके से जमींदोज हो गई थी। मगर, भ्रष्ट अधिकारी एसपी सिंगला के टेंडर को बचाने में लगे हुए हैं। ताकि 600 करोड़ से शुरू हुआ यह पुल 1700 करोड़ से 2700 करोड़ तक पहुंच जाए और इसके एवज में उस अधिकारी को भ्रष्टाचार का हिस्सा मिलता रहे। दरअसल, सूत्रें की माने तो बिहार सरकार का वो अधिकारी लंबे समय से बिहार सरकार में बैठकर भ्रष्टाचार का पूरा धंधा चलाने का आरोप है। भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र इसी अधिकारी के आसपास से होकर गुजरता है, जिसमें कई सफेदपोश चेहरे भी शामिल हैं। वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिहार के मुख्यमंत्री और विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। यह आईएएस अधिकारी इन दिनों टेंडर बांटने का काम कर रहे हैं। टेंडर उन्हीं को दिए जा रहे हैं, जो उन्हें उनके भ्रष्ट होने की मुंह मांगी कीमत उन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जिस पुल को 2019 के नवंबर में ही पूरा हो जाना था वह अब तक क्यों पूरा नहीं हो सका? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में डूबा यह सुल्तानपुर-अगुवानी पुल 14 महीनों में दो बार नहीं टूटता। नियम तो यह कहते हैं कि पुल की गुणवत्ता खराब होने पर कंपनी को तुरंत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मगर यह सिंगला कंपनी अभी भी काम कर रही है। इससे पहले परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने विधानसभा में इस पुल में हो रहे भ्रष्टाचार को रख चुके हैं। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताते चलें कि इस पुल के उद्घघटन की तारीख 8 बार बदली जा चुकी है। अब पुल का 400 मीटर का हिस्सा टूटने के बाद 9वीं बार बदलना तय है। वही माना जा रहा था कि अब यह भ्रष्टाचार का पुल स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों का काला ग्रहण अभी भी इस पुल पर लगा हुआ था। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसमें चार साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। पुल का हर पाया और हर बुनियाद घटिया गुणवत्ता के बनाए गए हैं। अब इस भ्रष्ट अधिकारी के पास ही जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी भी है। सुरेंद्र का कहना है कि अब ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जब हत्यारे को ही जज बना दिया जाएगा तो वो क्या खुद को सजा देगा?

बहरहाल, सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक ने ही सरकारी जांच के आदेश की पोल ठोल दी है। जेडीयू के विधायक डॉ० संजीव कुमार ने कहा कि पुल गिरने के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार बिहार के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं, जो दोषी हैं। वहीं जांच करेगा तो क्या हकीकत सामने आयेगी। सरकार मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराये और प्रत्यय अमृत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराये। बता दें कि जेडीयू विधायक डॉ संजीव कुमार ने इस साल मार्च में ही बिहार विधानसभा में पुल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। डॉ संजीव कुमार ने विधानसभा में कहा था कि निर्माणाधीन पुल के पायों में दरारें आ रही हैं। पिछले साल पुल का सुपर स्ट्क्चर ध्वस्त हो चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 15 मार्च 2023 को डॉ संजीव कुमार के विधानसभा में ये सब कहने के बावजूद डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने किसी गड़बड़ी की बात मानने से इंकार कर दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे जान माल की कोई क्षति नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बाद पुल ही ध्वस्त हो गया। जेडीयू विधायक डॉ संजीव कुमार मीडिया के समक्ष कहा था कि सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल में

डॉ० संजीव सिंह

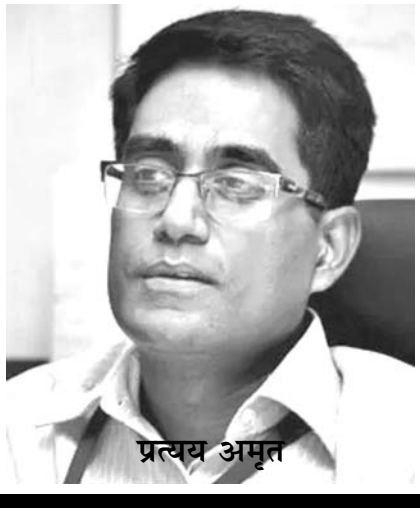
प्रत्यय अमृत

तेजस्वी यादव

सम्राट चौधरी

नित्यानंद राय

विजय सिन्हा

भ्रष्टाचार के सबूत के साथ उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से पहले ही मुलाकात की थी। उन्हें दिखाया था कि कैसे पुल के पायों में दरारें आ गयी हैं, लेकिन प्रत्यय अमृत बात मानने को तैयार नहीं हुए। वे किसी पाये का वीडियो दिखाकर कहने लगे कि जहां गड़बड़ी है वहां तोड़ कर नये सिरे से काम कराया जा रहा है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रत्यय अमृत को पुल के जिस पाये में दरार आने की जानकारी सबूत के साथ दी थी, वही पाया 4 जून 2023 को सबसे पहले ध्वस्त हुआ और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। डॉ संजीव कुमार ने कहा कि ये साफ दिखता है कि इस मामले में प्रत्यय अमृत खुद शामिल हैं। अब अगर सरकार उन्हें ही जांच का जिम्मा दे रही है तो इससे बडा मजाक क्या हो सकता है। जो खुद मुजरिम है वही जांच करेगा तो रिपोर्ट क्या आयेगी। सरकार इस मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराये, तभी सच्चाई सामने आ पायेगी। ये पता चल पायेगा कि कौन-कौन इस मामले में संलिप्त है। ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल है। विधायक डॉ० संजीव कुमार ने कहा कि सरकार को प्रत्यय अमृत जैसे अधिकारी को तुरंत पद से हटाना चाहिये। वे ऐसे अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं तो खुद को सबसे बड़ा डॉक्टर समझने लगते हैं। पथ निर्माण विभाग में आते ही खुद को सिविल इंजीनियर घोषित कर देते हैं। अगर उन्हें लॉ डिपार्टमेंट का सचिव बना दिया जाये तो वे खुद को जज समझने लगेंगे। ऐसे अधिकारी के कारण ही सरकार बदनाम हुई है। वही प्रत्यय अमृत कह रहे हैं कि सरकार वहां नया पुल बनायेगी। इससे पुराने पुल में भ्रष्टाचार का मामला खत्म नहीं हो जायेगा। ये तो वैसी ही बात हुई कि किसी आदमी की हत्या करने के उद्देश्य से गोली मार दी जाये। अगर वह आदमी इलाज के बाद बच जाये तो क्या गोली चलाने वाले का जुर्म खत्म हो जायेगा। डॉ० संजीव कुमार ने कहा कि एसपी सिंघला नाम की कंपनी ने पुल बनाने का काम लेते ही पूरे इलाके में नंगा नाच किया। कम से कम 24 लोगों की हत्या की जा चुकी है। लोकल पुलिस को मैनेज कर भ्रष्टाचार से लेकर रंगदारी का खेल खेला जा रहा था। इसकी जानकारी अधिकारी को दी गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल 30 अप्रैल को जब पुल का सुपर स्ट्रक्चर ढहा था तब कार्रवाई की गयी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। डॉ० संजीव ने कहा कि पिछले साल हुए हादसे को लेकर अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। साफ है इस मामले जो लोग दोषी थे, उन्हें बचाने के लिए विभाग के अधिकारी लगातार मामले को दबाकर रखना चाहते हैं। अब अगर पुल गिरने की जांच शुरू होती है, तो मेरी मांग है कि इस 15 दिन में पूरा किया जाए और जो भी दोषी हों उन्हें सख्त सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी को बचाने का प्रयास भी किया गया तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दाखिल करूंगा। वही पुल की गंगा में जल समाधि को लेकर डॉ० संजीव ने निर्माण कर रही एसके सिंघला कंपनी को भी जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पुल बनाने के दौरान दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। पुलिस के साथ मिलकर कंपनी ने सारा मामला रफा-दफा कर दिया। वही उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर नीतीश कुमार पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि नीतीश कुमार इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, हां, कुछ अधिकारियों के कारण उनकी साफ छवि पर करप्शन के धब्बे जरुर लगे हैं। वही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए डॉ० संजीव कुमार ने कहा कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। वह मंत्री हैं, सदन में वह जिन सवालों का जवाब देते हैं, वह उनके विभाग के सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर साफ कहा कि जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने तेजस्वी को कहा है कि विभागीय स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कराएं और जो अधिकारी इसके लिए दोषी हों उनके खिलाफ जांच कराएं। डॉक्टर संजीव यहां भी नहीं रुके उन्होंने कहा कि जितना निर्माणकर्ता कंपनी एसपी सिंघला जिम्मेदार है उससे ज्यादा डिजाइन बनाने वाली कंपनी रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड और राज्य के चर्चित अधिकारी से उनकी दोस्ती कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि अभी तक आ रही रिपोर्टों की बात करें तो फूल डिजाइन में ही त्रुटि है, उन्होंने मुख्यमंत्री से भागलपुर में विक्रमशिला के समानांतर बन रहे

सुधाकर सिंह

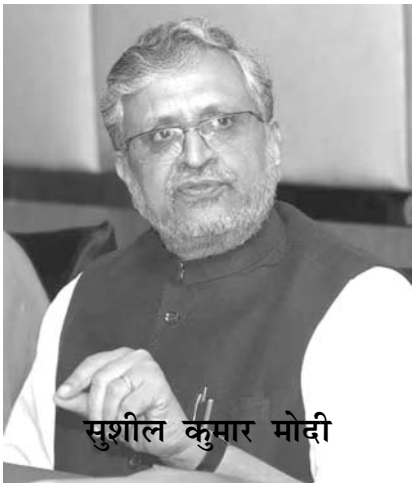
सुशील कुमार मोदी

पुल का डिजाइन की भी जांच आईआईटी रुड़की से कराने की मांग कर दी है, क्योंकि यह डिजाइन भी रोडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

वहीं दूसरी तरफ राजद के चर्चित विधायक सुधाकर सिंह कहते हैं कि अफसर राजा का बात मानता है और उसी की कहे भी करता है इसलिए पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। आज राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं तो विनाश का भी सेहरा उनके सर पर बंधना चाहिए।

बिडम्बना है कि पुल के ध्वस्त होने के बाद उपमुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव ने पुल गिरने के बाद कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 में भी यह निर्माणाधीन पुल गिरा था और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हमने इस पर सवाल भी उठाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पथ निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद हमने इस पुल की जांच आईआईटी रुड़की से कराई जिसके आधार पर पुल के स्ट्रक्चरल डिजाइन में फॉल्ट पाया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़कर फिर से उसे बनाने का काम शुरू किया गया। अभी इस पुलिस के पिलर नंबर पांच को लेकर आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट आनी है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने हमें सूचित किया था कि इसमें गंभीर खामियां हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पिछले साल इस पुल का एक हिस्सा आंधी में ढह गया था। यह एक ऐसी घटना थी, जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। मैंने विपक्ष के तत्कालीन नेता के रूप में इसे मजबूती से उठाया था। सत्ता में आने पर हमने जांच के आदेश दिए और एक्सपर्ट्स की राय मांगी। हमने पहले ही इस पुल को लेकर आशंका जताई थी। हमें शंका थी, इसलिए नवंबर 2022 में भी हमने निर्देश दिया था कि पूरी जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्ट्रक्चर टूटने का जो नुकसान आया है। वह सरकार पर नहीं ठेकेदार पर आएगा। बता दें कि भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ने वाले अगुवानी-सुल्तानगंज पुल के गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच राज्य सरकार के अधिकारियों ने दावा किया कि डिजाइन की खामियां थी इस वजह इसके कुछ हिस्सों को विशेषज्ञों की सलाह के तहत योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर ध्वस्त किया गया। कहा जाता है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,700 करोड़ रुपए हैं। ऽगड़िया में हुई इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। इसके बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्तफ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आनन-फानन में प्रेसवार्ता आयोजित की। अमृत ने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि हमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए इसलिए पुल के कुछ हिस्सों को गिराने का फैसला किया गया। यह घटना ऐसी ही एक कवायद का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार उस कंपनी को काली सूची में डालने और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेगी, जिसे परियोजना का ठेका दिया गया था। अमृत ने यह भी कहा कि घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया और दुर्घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

गौरतलब है कि बिहार के भागलपुर में बन रहे पुल के एक हिस्से के गंगा नदी में समाने के बाद अब उस पर जमकर राजनीति की जा रही है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा 1700 करोड़ के पुल के ध्वस्त होने के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इसी

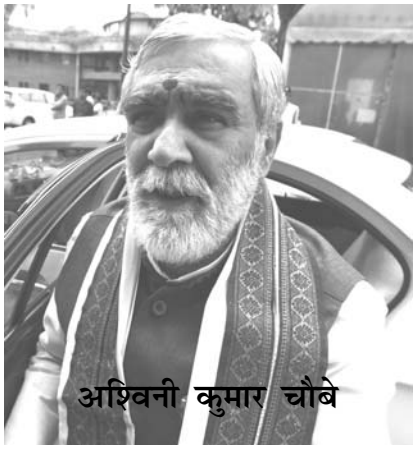
अश्विनी कुमार चौबे

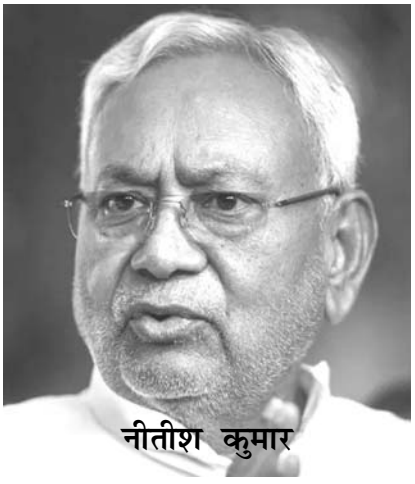
नीतीश कुमार

कड़ी में पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कई सवाल भी खड़े किए है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से बालासोर रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे थे। वे क्या बिहार में निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तानगंज महासेतु का एक हिस्सा फिर से ढह जाने की जिम्मेदारी लेंगे? क्या महासेतु मामले में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कोई कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा कि जो लोग गैसल रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की कथा सुना रहे थे, वे महासेतु के पाये ढहने पर चुप क्यों हैं? वहीं सुशील मोदी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से पांच सवाल पूछा है, जिनमें पहला सवाल है कि जब महासेतु का एक हिस्सा टूटा और आइआइटी रुड़की को इसकी जांच सौंपी गई, तब उसकी अंतरिम रिपोर्ट का इंतजार किये बिना निर्माण की गति क्यों बढ़ा दी गई? दूसरा सवाल जब विधानसभा में डॉ० संजीव ने पुल का पाया कमजोर होने का सवाल उठाया, तब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किस आधार पर क्लीनचिट दे दी? तीसरा सवाल अगर पुल का एक हिस्सा खुद नहीं टूटा, बल्कि डिजाइनिंग की गलती के कारण उसे तोड़ा जा रहा था, तो उस जगह से मजदूर लापता कैसे हो गए? चौथा सवाल कि साल भर पहले जब महासेतु का एक हिस्सा टूटा, तब निर्माण एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पंचवा सवाल प्रस्तावित महासेतु का शिलान्यास होने के 8 साल बाद भी निर्माण पूरा क्यों नहीं हुआ? मोदी ने कहा कि सरकार यदि कुछ छिपा नहीं रही है, तो उसे इन सवालों का तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय उत्तर देना चाहिए। बता दें कि भाजपा ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का

इस्तीफा मांगा है। भाजपा नेता एवं भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने घटना के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री को बिहार के विकास की जरा भी चिंता नहीं है, वह अपने दौरे पर व्यस्त हैं। इस घटना के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले साल नवंबर में नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था। भागलपुर में पुल गिरने की घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी उपस्थित थे। सम्राट चौधरी ने कहा- सुल्तानगंज में पुल ध्वस्त हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 2014 में पुल का जब शिलान्यास किया गया, उस समय तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे। ठेकेदार जब आवंटित हुआ, उस समय भी तेजस्वी मंत्री थे। एक साल पहले पुल का कुछ हिस्सा गिरा, उसकी जांच हुई। उसके बाद भी तेजस्वी ने काम शुरू करवाया। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। नीतीश कुमार पर मेरा सीधा आरोप है उनके देखरेख में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नीतीश कुमार का यही विकास मॉडल है, इस पर उन्हें जवाब देना होगा। नीतीश कुमार इसके जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। सरकार निष्पक्ष जांच कराना चाहती है तो पटना हाईकोर्ट के सीटिंग्स से जांच कराएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ठेकेदार किसने चयनित किया, टेक्नोलॉजी क्या कुछ उपयोग की गई, इस निर्माण कार्य के लिए उसकी भी जांच हो। गरीब जनता का जो पैसा खर्च हुआ, बर्बाद हो गया है। कौन-कौन देगा तेजस्वी और नीतीश कुमार अपने निजी फंड से देंगे क्या? भाजपा नेता नित्यानंद राय ने ट्वीट कर कहा कि आरजेडी-जेडीयू की पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान शिलान्यास हुआ लगभग 1750 करोड़ की लागत से बन रहा खगड़िया-भागलपुर पुल दोबारा भरभरा कर गिर गया। नीतीश-तेजस्वी के साझा भ्रष्टाचार के मिलावटी माल से बन रहा यह पुल इस महामिलावट की सरकार के आकंठ भ्रष्टाचार की कलई खेल रहा है।

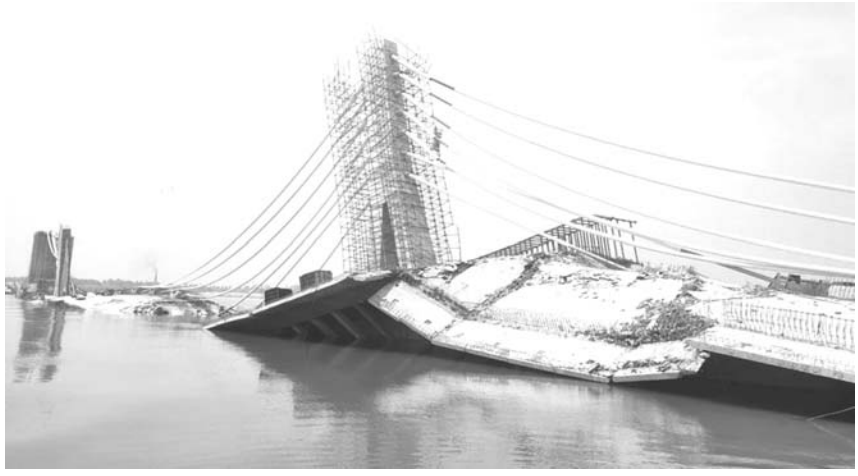

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य सराकर पर निशाना साधते हुए कहा कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चाचा-भतीजा (नीतीश-तेजस्वी) को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि कुछ ही महीनों के अंतराल पर दूसरी बार यह पुल गिरा है। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यह निर्माणाधीन पुल दो बार गिर चुका है। नीतीश तेजस्वी में नैतिकता बची हुई है तो वे तुरंत इस्तीफा दें। वही निर्माणाधीन पुल गिरने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस का एक और नया रूप सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में 600-700 करोड़ की लागत वाला पुल करीब 1700 करोड़ की लागत तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कमीशनखोरी के चक्कर में उच्च अधिकारियों के जरिए पैसे की वसूली की जा रही है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी।

बहरहाल, कई सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे हैं कि इस पुल का निर्माण जब शुरू हुआ था जब बिहार का पथ निर्माण विभाग बीजेपी के पास था। उस वक्त बिहार पथ निर्माण विभाग के मंत्री बीजेपी नेता नितिन नबीन थे। इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा इससे पहले 13 अप्रैल को 2022 को भी गिरा था। उस वक्त कहा गया था कि आंधी की वजह से पुल गिर गया। अब अगवानी घाट पर बन रहे पुल के गिरने की घटना पर उस वक्तफ के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में गलतियों को सुधारा नहीं गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले दिनों इस पुल को लेकर क्या मॉनिटरिंग हुई है, जो पिछली जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने विभाग से निकलवाया था। लेकिन जुलाई 2022 के बाद हमने इस मामले को देख नहीं। अभी जब यह घटना घटी है तो निश्चित रूप से जो विभाग के पदाधिकारी या मंत्री हैं उन्हें तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। पिछली बार की घटना में पिलर के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी पाई गई थी। इस बार चार पिलर गिरे हैं। इसलिए इसकी पिछली जांच रिपोर्ट और अभी जो जांच होगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो टेक्निकल लोग हैं उन्हें वर्कआउट करना चाहिए। पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसपर संज्ञान होना चाहिए। लेकिन पिछले सालभर में इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए आज इसकी पुनरावृति हुई। जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में तो वर्तमान के लोग ही बता पाएंगे। एक साल तक सरकार सोई रह गई। उस वत्तफ डिजाइन में गड़बड़ी की बात कही गई थी। दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हम लोग तो पुल बना रहे हैं, भाजपा वाले गिरा रहे हैं। भाजपा द्वारा नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बीच बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी वाला सब पुल गिराया है। हमलोग बनाते हैं और बीजेपी वाला सब गिराता है। नीतीश का कहना है कि पुल का निर्माण ठीक से नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि यह अप्रैल 2022 से दो बार गिर गया। यह एक गंभीर मामला है। संबंधित विभाग ने पहले ही इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि 2014 में शुरू हुआ पुल निर्माण कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। यह समय से पीछे क्यों चल रहा है? मैंने संबंधित

जागरण पटना, 16 जून, 2023

राजधानी जागरण

अगुवानी घाट पुल की डिजायन में गड़बड़ी की बात पर विशेषज्ञों ने भी लगाई मुहर

सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के बाद पुल सेक्टर के विशेषज्ञों ने अपनी जांच पूरी कर ली

राज्य ब्यूरो, पटना : अगुवानी घाट पुल का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के बाद पुल सेक्टर के विशेषज्ञों ने अपनी जांच पूरी कर ली है। कई स्तर पर अलग-अलग विशेषज्ञों की जांच में इस बात पर लगभग मुहर लग गई है कि पुल की डिजायन में तकनीकी तौर पर गड़बड़ी है। दिलचस्प बात है कि पुल की डिजायन में विशिष्टता रखने वाली कनाडा की कंपनी मैक्लेन ने इसे डिजायन किया और इस काम को अमेरिका के इंजीनियर ने अंजाम दिया। निर्माण कंपनी ने अपने अमेरिकी इंजीनियर को भी अपनी बात रखने के लिए यहां बुलाया था।

स्ट्रक्चर आडिट का काम पूरा, पंद्रह दिनों में रिपोर्ट संभावित: पुल के सुपर स्ट्रक्चर के दूसरी बार गिरने पर पथ निर्माण विभाग ने दो स्तर पर इसकी जांच कराई थी। आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञों ने पुल की संपूर्ण संरचना का स्ट्रक्चरल आडिट किया। चार-पांच दिनों तक रुड़की से आई टीम ने अपना काम किया। उनकी जांच में आरंभिक तौर पर यह बात सामने आ रही कि पुल की डिजायन में ही गड़बड़ी थी। इसी वजह से पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। स्ट्रक्चरल आडिट के बाद रुड़की से आई विशेषज्ञों की टीम वापस लौट गई है। अगले पंद्रह दिनों में रिपोर्ट संभावित है। आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञों की जांच के अलावा पुल निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी जांच करने वहां पहुंचे जहां पुल बन रहा था। आरंभिक तौर पर वहां भी डिजायन में गड़बड़ी की बात सामने आ रही।

रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई : पथ निर्माण विभाग ने मोटे तौर पर यह तय कर लिया है कि अगुवानी घाट के संपूर्ण सुपर स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर वहां नए सिरे से पुल बनाया जाएगा। आइआइटी रुड़की की टीम व पुल सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर पुल के नए सिरे से निर्माण का निर्णय लिया जाएगा। डिजायन आदि पर मामला आगे बढ़ेगा।

धराशायी हुआ सुल्तानगंज-अगुवानी महासेतु का पिलर संख्या 10। • फाइल फोटो

निर्माण कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है जवाब

जिस दिन अगुवानी घाट पुलका सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ उसके अगले ही दिन पथ निर्माण विभाग ने पुल के निर्माण मे लगी कंपनी को काली सूची मे डाले जाने को ले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह निर्देश दिया गया था कि पंद्रह दिनों के अंदर वह अपना जवाब दे। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कंपनी ने अपना जवाब अभी तक नही दिया है। वह डिजायन व निर्माण से जुड़े डाक्यूमेंट की व्यवस्था मे लगी है।

अब धीरे-धीरे बंद होगा परिमार्जन पोर्टल, फिलहाल सीमित उपयोग का आदेश

विभाग से इसकी भी जांच करने को कहा है। उपमुख्यमंत्री इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी की इस टिप्पणी के लिए आलोचना की कि पुल के 'कई संरचनात्मक दोषों' को विशेषज्ञों द्वारा इंगित किया गया है और राज्य सरकार ने पहले ही कई हिस्सों को गिरा दिया है जिन्हें विशेष रूप से कमजोर हिस्से के रूप में चिह्नित किया गया था। पुल के ढहने का वीडियो वायरल होने पर बिहार भाजपा ने एक बयान जारी कर नीतीश के इस्तीफे की मांग की है जिन्होंने पिछले साल अगस्त में भगवा पार्टी से नाता तोड़ लिया था। वर्ष 2014 से बन रहा 3-16 किलोमीटर लंबा यह पुल 14 महीने में दो बार टूटा। पहला अप्रैल 2022 में भागलपुर के सुल्तानगंज की तरफ और दूसरी बार 4 जून 2023 की शाम खगड़िया की तरफ से। चार लेन वाले सुल्तानगंज-अगुआनी घाट पुल के तीन खंभे पर रखे कम से कम 30 स्लैब नदी में गिर गए।

बहरहाल, सच्चाई जो भी हो किन्तु उक्त घटना को देखकर साफ-साफ भ्रष्टाचार का होना दिख रहा है। भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट+आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2005 में ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को उत्कोच दी थी। 2008 में, एक अन्य रिपोर्ट ने दिखाया कि लगभग 50% भारतीयों को उत्कोच देने या सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सम्पर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंस प्रणाली, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शत्तिफयों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का एकाधिकार, और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी शामिल हैं। भ्रष्टाचार के स्तर में और पूरे भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं। भारत जब गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आजादी के बाद अपना राज यानी स्वराज्य होगा, लेकिन आज जो हालत है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि अपना राज है कहां? उस लोक का तंत्र कहां नजर आता है, जिस लोक ने अपने ही तंत्र की स्थापना की? आज चतुर्दिक अफसरशाही का जाल है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर-चूर कर रही है। यह सर्वविदित है कि भारत में नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है। इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर, उनका शासक और स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है। देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अक्षुण्ण रखना और उसे मजबूत करना था। जनता के हित, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर-दूर तक उसके सरोकारों में नहीं थे। नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो अधिकांशत: अंग्रेज अफसर होते थे। भारतीय लोग मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती किए जाते थे, जिन्हें हर हाल में अपने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता था। लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किए गए शिक्षा के मॉडल का उद्देश्य ही अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में मजबूत करने और उसे चलाने के लिए ऐसे भारतीय बाबू तैयार करना था, जो खुद अपने देशवासियों का ही शोषण करके ब्रिटेन के हितों का पोषण कर सकें। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वह थी नौकरशाही की विरासत और उसका चरित्र। कड़े आंतरिक अनुशासन और असंदिग्ध स्वामीभत्तिफ से युत्तफ सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यत्तिफयों का संगठित तंत्र होने के कारण भारत के शीर्ष राजनेताओं ने औपनिवेशिक प्रशासनिक मॉडल को आजादी के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस बार अनुशासन के मानदंड को नौकरशाही का मूल आधार बनाया गया। यही वजह रही कि स्वतंत्र भारत में भले ही भारतीय सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाने लगा, लेकिन अपने चाल, चरित्र और स्वभाव में वह सेवा पहले की भांति ही बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तंत्र को आज भी 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' कहा जाता है। नौकरशाह मतलब तना हुआ एक पुतला। इसमें अधिकारों की अंतहीन हवा जो भरी है। हमारे लोगों ने ही इस पुतले को ताकतवर बना दिया है। वे इतने गुरूर में होते हैं कि मत पूछिए। वे ऐसा करने का साहस केवल इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास अधिकार हैं। भारत में अब तक हुए प्रशासनिक सुधार के प्रयासों का कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया है। वास्तव में नौकरशाहों की मानसिकता में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। हालांकि, नौकरशाही पर किताब लिख चुके पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के मुताबिक राजनीतिक नियंत्रण हावी होने के बाद ही नौकरशाही में भ्रष्टाचार आया, अब उनका अपना मत मायने नहीं रखता, सब मंत्रियों और नेताओं के इशारों पर होता है। हमारे राजनीतिज्ञ

करना चाहें, तो पांच साल में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उनके लिए अनुकूल है, इसलिए वो बदलाव नहीं करते। बहरहाल, अफसरशाही का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ही परिणाम है बिहार के भागलपुर में सुलतानगंज-अगुवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन फोरलेन पुल का जमींदोज हो जाना।

भागलपुर , सुल्तानगंज से -अगुआनी पुल परियोजना मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के चेहरे पर काले धब्बे दाग कि तरह है जिसे मिटा तो सकते है भुलाया नही जा सकता , इतिहास याद रखेगा , इतिहास इस मायने में पुल से ज्यादा अपने चहेते अधिकारी जो पथ निर्माण विभाग सहित कई विभगों के अपर मुख्य सचिव बने है जो माननीय मंत्री से भी अपने को ऊपर समझते है जिसके माथे ऐसी कई उपलब्धि है जिसमें हजारों करोड़ रूपये कि लाइजनिंग कर सरकार में बैठे भिखारी की भूखे पेट को भरता है साथ ही साथ काली-कमाई से आज कई कम्पनियो को तैयार कर अमेरिका से ऑपरेट करवाता है।

बिहार के राजनितिक गलियारे में सत्तासीन बड़े से छोटे नेताओं मे चर्चा आम-ए-खास है। भाई एगो त खासियत हईये न हई हो ,चलते चलते एक छोट भैया नेता ने कहा कि-मने कह रहे है की ई अधिकारी के बिहार से लेके दिल्ली तले पहुँच है हो भैया, इकरा डिप्टीओ सीएम कुछ नै बिगाड़ सकलथींन हे।

पुल निर्माण कंस्ट्रक्सन कंपनी को गुजरात से आयातित कर लाया गया है ,ऐसा कई कंस्ट्रक्सन कंपनी है जिसे टेंडर से अधिक दर पर यहाँ तक 19.99% अधिक दर पर काम का ठेका दिया है। समझ लीजिये ऊपर के पैसों का वसूली और काम दिलाने के अलग से कितने करोड़ मे जाती है द्य ऐसे करते-करते कई अधिकारी आज अपनी खुद कि कंपनी बना कर ठेका दिलवा रहे है वो भी पद पर रहते। है न आश्चर्य, किन्तु यह बिहार कि धरती है जहाँ से ज्ञान कि गठरी बांधकर विदेशो तक निर्यात किया जाता है। एक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी का कहा शायद सटीक बैठता है- 'पर उपदेश बहुत तेरे से मैने यह सीखा है, मैं नही छूता औरो को पहुंचा देता हाला'। नीतीश जी, कहने के लिए आप मिस्टर क्लीन बन जाइये किन्तु आप छुए नही छुए हाला तो पहुंचाया जा ही रहा है यदि ऐसा नही है तो क्यों नही करा लेते सीबीआई जांच, केंद्र की सीबीआई जांच से नही तो माननीय उच्च न्यायलय के सिटिंग जज से इसकी जांच करवा लीजिये, संकोच किस बात की।

आज बिहार की राजनिति मे साइड प्ले की भूमिका की भूमिका मे तेजस्वी प्रसाद यादव है जिनके पास पथ निर्माण से लेकर स्वास्थ्य विभाग जैसे भारी भरकम मंत्रालय है जिसके दम पर भवीष्य के चेहरों पर डेंटिंग-पेंटिंग करना चाहते है! आज तेजस्वी के लिए चुनौती है लेकिन लगता नही की इस चुनौती पूर्ण कार्य से अपने चेहरे को चमकायेंगे। पूरा बिहार जानता है तेजस्वी के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम की कुर्सी है, जिस कुर्सी बाबू के साथ याराना है।

बिहार की राजनीति मे विपक्ष के पास हौसला नही है की इस भ्रस्टाचार रूपी पुल की पैर कतरी जा सके, वो हिम्मत नही है की सीबीआई की जांच के सरकार से लड़े कारण स्पष्ट है समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इस मुद्दे पर मिस्टर क्लीन मजबूत है की चलो विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक लड़ नही सकता ,कमजोरी उन्हें पता है, अगर ऐसा नही तो कहा गए मंगल पांडे, कहा गए कानून विद रविशंकर प्रसाद, किस बिल मे घुसे है नवीन किशोर, चौधरी सम्राट को तो ताज चाहिए।आज शिक्षा के क्षेत्र मे भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी तह तक जानकारी विपक्षी को है किन्तु दिखावे के अलावे मुद्दों से हट और भटक रहा है विपक्ष।

सिघला जैसे चहेते निर्माण एजेंसी को लाने वाले शायद भूल रहे है की यह जो नुकसान किया जा रहा है सब पब्लिक का धन है न की आपके बाप का द्य भ्रस्टाचार की भेट चढ़े पुल, साक्ष्य, सत्य और पाप के बीच जंग में आखिरकार हार गया, पाप कि पोल खुल गई और पाप की सेतु गंगा में ध्वस्त में हो गईं। इशारे के लिए गंगा मईया ने पहले सुल्तानगंज को गिरया तब भी सरकार नही समझी तब अंत में अगुआनी में किये गये जा रहे घोर पाप को अपने आगोश में लेकर भविष्य में होने वाले बड़े हादसे को होने से पूर्व सांकेतिक तौर पर अर्थ दंड दिया है ताकि सरकार को समझ में आये। एस.पी. सिघला कंस्ट्रशन कंपनी जो गुजरात के समंदर में 5.50 किमी० ब्रिज का निर्माण कर रही है, जो 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और वही अन्य जगहों पर कार्य कराकर सफलता पूर्वक निकल चुकी है, किन्तु बिहार में इसके बुरा हाल देखकर समान्य तौरपर लोग कंस्ट्रक्सन कंपनी एस.पी. सिंगला को दोष दे रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार में बैठे विभगीय अधिकारी जिसकी वजह से पूरा निर्माण दोषपूर्ण है, जिसका असर आम नागरिको पड़ना स्वाभाविक है। जिसके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने की साहस भी जुटा नही सकती, कारण शेयर जो दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान विभाग में बैठे आला अधिकारी कि तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा, जिनके वजह से आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फिर गया। आज बिहार की पुरे देश में जग हंसाई हो रहा है। कभी यह पुल हवा में उड़ जाता है तो कभी नदी में गिर कर स्नान करने लगता है। देख लीजिये चुनाव आने वाला है कही पिचास पीछा नही करने लगे। वैसे धार्मिक दृष्टिकोण से इसे हम दंड समझते है हालाँकि तकनीकी रूप से विज्ञान कि दुनिया में इसके कोई मायने नही है, जिस पुल के कंस्ट्रक्सन में अनिमियतता कि गई है।

मिस्टर क्लीन आपको तो पुल निर्माण में किये गए गड़बड़ी की जाँच करने आये आईआईटी रुड़की के अधिकारीयों ने तो सभी पहलुओं पर सतर्क किया था, जिसे जानबूझकर अनदेखी कर दिया गया। जिस कार्य में घोटाला नही महाघोटाला किया गया। तत्क्षण हम भले ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के माथे नारियल फोड़ दे किन्तु सत्य यही है कि यह गुनाह किसी और ने किया है। जिसके प्रेरणा से ऐसा कृत करवाया गया है, जिस कंपनी से मोटी कमीशन लेकर बिहार को शर्मशार किया गया, जिसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाया जाना बिहार के हित में होंगी। कही ऐसा तो नही विभाग के आलाधिकारी के द्वारा समानांतर कोई कंपनी चलाया जा रहा है, जिसमें काली कमाई को लगाया जा रहा है, जिसकी पड़ताल जरूरी है।

एस.पी. सिघला कंस्ट्रक्सन कपंनी को बिहार में 9000/- करोड़ रूपये के ठेका दिया गया यह जानते हुये कि केंद्रीय सरकार कि योजना में दो-दो बार ब्लैकलिस्टेड किया गया था। बाबजूद सुल्तानगंज ब्रिज ध्वस्त होने के पश्चात् भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड नही किया जाना आंतरिक प्रबंधन को उजागर करता है। जिस कृत से आज 17 सौ करोड़ कि वसूली भले कर लिया जाये, यह अलग बात है किन्तु इस कार्य के लिए जो करवाया गया, जो असली दोषी है, उसको सजा अवशय दिया जाना चाहिए। कारण इतने दिनों के सैलेरी जो पथ निर्माण विभाग के अधिकारी/अभियंता को निरक्षण के नाम दिया गया। ऊपर से समय कि बर्बादी। इसके भरपाई कौन करेगा? उस मां के बेटों को कौन लौटाएगा? आज साथ सात निश्चय कि कसौटी पर सरकार खड़ी है, जिसे साबित करने का समय आ गया है। गुनहगार कोतवाल को खोजना ही कर्तव्य बनता है, क्योंकि गुनाह करने वालों से ज्यादा दोषी गुनाह करवाने वाले है, खोजिये साहब। ●

वरीय पुलिस अधीक्षक का दिया गया ब्यान सिर्फ दिखावा

दीघा थानाध्यक्ष राजकुमार पाण्डे को अपराधियों से तालमेल का आदेश प्राप्त है

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बिहार में जात सिर्फ राजनीति में ही नहीं चलती है, प्रशासनिक महकमे में भी पुरजोर तरीके से चल रही है, इसलिए दीघा थाना अध्यक्ष को अपराधियों के साथ जन्मदिन मनाने, उन्हें थाने में पोषित किए जाने और हर्ष फायरिंग में साथ होने की फोटो वायरल होने के बावजूद भी वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय पटना की कृपा से उन पर कोई बाल बांका नहीं हो पा रहा है।

पिछले बार केवल सच में आलेख आने के बाद दीघा थाना अध्यक्ष महोदय ने केवल सच को कानूनी नोटिस भी भेजा था जबकि उसी आलेख में सबूत चिल्ला-चिल्ला कर थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे को अपराधियों के साथ गठजोड़ को बता रहा है। थानाध्यक्ष थोड़ा तेज दिमाग के हैं इसलिए उनकी धन-सपत्ति दूसरों के नाम पर हैं लेकिन राज्य ही नहीं देश में कई बेनामी संपत्ति उजागर हुई है और देर-सवेर राजकुमार पांडे की भी काली संपत्ति बेपर्दा होगी। दीघा थाना अध्यक्ष महोदय खुलेआम केवल सच के स्रोत

और पत्रकारों को धमकी दिए फिर रहे हैं, लेकिन कलम की ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं है। दीघा थाना अध्यक्ष राज कुमार पांडे अपराधियों के साथ वायरल फोटो पर कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों से तालमेल जरूरी है और वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय पटना हमारे इस जवाब से संतुष्ट हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच की कड़ी हैं और थाना अध्यक्ष महोदय को जनता को भी बता देना चाहिए कि अपराधियों से तालमेल कर थाना को खाना बनाना चाहते हैं क्या?

दीघा थाना के कोतवाल राजकुमार पाण्डेय की हेकड़ी इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है, तानाशाही सात आसमान छू रहा है, ठीक उसी रफ्तार से क्षेत्र में गली - मोहल्ले में शराब की होम डीलेभरी की जा रही है, वही हर चौक-चौराहे पर गांजा तस्करो की बल्ले-बल्ले है, बाजार के हर पान गुमटी पर में गांजा, ऑटो टेम्पू में गांजा, चाय दुकान पर गांजा मानो खाजा के समान बिक रहा है और बिके भी क्यों नही, क्योंकि यहां के राजा राजकुमार पाण्डेय जो ठहरे। इस बात की तबतीस करने पर

पता चला की सेटिंग से सब कुछ सम्भव हो जाता है साहब। उसने कहा की क्या आपको पता है की हर महीने शराब तथा गांजा के बिक्रताओ से दीघा थाना को कमाई कितनी है, पूछने पर नाम नही बताने पर कहा की इसे तसिलने के लिए कुछ पुलिस कर्मी को ड्यूटी बांटा गया है। कुछ जमादार साहब तो, कुछ दरोगा जी स्वयं चार चक्का से वसूली करने आते हैं। नाम नही छापने के शर्त पर उसने जो बताया आँखे फटी की फटी रह गई। सुनकर दिमाग की हिल गया। सोचा क्यों न सरकार इसे फ्री कर देती। नाहक लोग धन को बर्बाद कर रहे है। राहगीर ने जो बताया उसके अनुसार दीघा थानाक्षेत्र अंतर्गत एक दर्जन दो दर्जन बल्कि पुरे एक सौ जगहों जिस में चौक-चौराहे, गली-मुहल्ले में गांजा तथा शराब के तस्कर महीने पर नवयुको को रखकर गलत कारोबार में धकेले हुये है जिसका शेयर एक साधारण शराब के बिक्रेता से बीस हजार महीने फिक्स है तथा एक गजेड़ी से दस हजार प्रति ब्यक्ति फिक्स किया गया इसी से जोड़ लीजिये ऊपर से यदि कोई मामले में पुलिस पकड़ लिया तो पचास हजार नजराना ऊपर से देना है।

मरीन ड्राइव इन दिनों अपराधियों खाासकर के गंजेरियो के लिए अभयदान है। लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। शैर सपाटे के बहाने पढ़ने वाले नवयुवक ड्रग्स के शिकार हैं, गांजा पिने की लत से खुद के भविष्य को खराब करते जा रहे हैं और यह सब पुलिस की जानकारी में,

आधी रात बाद मौत से रेस बीच सड़क पर काट रहे केक

जासं, पटना : जेपी गंगा पथ, अटल पथ और दीघा-एम्स फ्लाइओवर पर आधी रात बाद मौत से रेस और बीच सड़क पर केक काटकर युवा खुद के साथ औरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। तीनों सड़कों पर कोई कार के बोनट पर तो कोई डिवाइडर पर बर्थडे सेलिब्रेट करता है। कई ग्रुप बनाकर बाइकर्स रेस लड़ाते रहते हैं। स्टंटबाजी और लहरिया कट आम है। रही बात कार्रवाई की तो ट्रैफिक पुलिस दो घंटे का अभियान चलाकर इतिश्री कर ले रही है। रविवार की रात दो छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इसमें एक छात्र बर्थडे मनाने दोस्तों के साथ पहुंचा था।

तीनों मार्गों पर शाम सात से नौ बजे तक ट्रैफिक पुलिस तीनों जगहों पर जांच करती है। इस ईच बाइकर्स कम नजर आते हैं, लेकिन सुबह के पांच से सात बजे और रात नौ बजे के बाद तीनों मार्गों पर बाइकर्स खुद के साथ ही दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। अटल पथ पर ओवरस्पीड के कारण दर्जन भर हादसे हो चुके हैं। इनमें बाइक

एक दिन में वसूला गया 6,24,000 हजार जुर्माना

मंगलवार को विशेष जांच अभियान चलाकर यातयात नियमों का उल्लघंन करने वाले 403 वाहन चालकों का चालान काटा गया। इनसे छह लाख 24 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, जेपी गंगा और अटल पथ पर शाम में दो घंटे चले विशेष जांच अभियान में 46 वाहन चालकों से 82 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।

सवार युवकें और युवतियों की भी जान जा चुकी है। यही हाल जेपी गंगा पथ का है। यहां भी कई हादसे हो चुके हैं। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ऐसे बाइकर्स और चार पहिया वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए कैमरे की मदद से भी चालान काट रही है। ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच अभियान के समय का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। ओवरस्पीड, स्टंट और रेस लगाने वालों से जुर्माना के साथ केस दर्ज होगा।

जगह जानकारी में ही होता है। झुंड के झुंड लडके बैठकर चिल्लम लहराते हैं और बगल से पुलिस की गस्ती गुजरती है, किन्तु कुछ मतलब नही। पुलिस के सामने आप चाहे जितने अपराध कर लो, सही है। सिर्फ शिकायत नही आनी चाहिए, यही ड्यूटी है पुलिस का। मरीन ड्राइव पर यदि आप शैर सपाटे के लिए बच्चों के साथ जाने की इच्छा रखते हैं तो सम्भल कर जाना होगा, क्योंकि हो सकता है बाइकर्स गैंग आपको कही शिकार न बना दे। पिछले महीनो से कई अपराध हुये हैं। दो बच्चियों की लाश बरामद हुयी है, कई अन्य वारदाते भी हुयी जो थाना के रजिस्टर में नहीं। हर रोज मारपीट और दहशत का माहौल बना रहता है मौरीन ड्राइव पर। अब यहां जाना भयावह सा लगता है। ऐसा महौल बन रहा है कुछ दिनों बाद चिलम नही चाकू बाज दिखेगा। फुटपाथ दुकादारों से रंगदारी वसूलने का प्रयास शुरू हो चुका है, किन्तु अपने राजकुमार तो वसूली में लगे हैं। फुर्सत कहा जो सामाजिक कार्यकर्त्ता से चर्चा करे। विधि-व्यस्था जाए भांड में। बस इन्हें पाटलिपुत्र स्टेशन के पास राम अयोध्या नगर में पांच कठ्ठे जमीन पर फ्री का बालू भरा जाए। रूपसपुर, बेलीरोड में चार मंजिला भवन फिनिश हो जाए। जमीन दलाल से दोस्ती इनकी अच्छी जमती है। शराब की देर रात चुस्की के साथ होटल में बैठकर ड्यूटी का इतिश्री करने के साथ कल सुबह के लिए ड्यूटी के बदले लाखों रूपये का गणना शुरू हो जाता है, जिनके रहते कार्यकाल में अबतक कई जगहों पर आवास बोर्ड के जमीन पर मकान बनवा दिया गया। अवैध कैप्चर करवा दिया गया। यहाँ तक बगल का थाना राजीव नगर में लाइजनिंग कर खूब कमाए। विदित हो कि जब से पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रभार में राजीव कुमार मिश्रा कमान संभाले हैं, तब से राजकुमार पाण्डेय का जलवा चढ़ कर बोल रहा है। इनके द्वारा निर्दोष बच्चों तथा कई निर्दोष लोगों पर प्रायोजित रूप से प्राथमिकी दर्ज कराया गया, जो बाद मे सभी केस फाल्स हो गए। आखिर जब केस फाल्स हो गए, तब तो जिम्मेदारी थानाध्यक्ष पर आना चाहिए। क्यों नही इनके विरुद्ध आईपीसी एक्ट 211 लगाई जाए। नाम सार्वजनिक नही करने के शर्त पर एक गंजेरी बताया की रात दस बजे के बाद तो खुलेआम शराब तस्करो की गाड़िया अपने रफ्तार में होता है। भूलकर भी मुँह लगाने पर मुश्किल हो जाएगा। इनलोगों के द्वारा संगठित गिरोह को संचालित किया जाता है जिसकी सूची एक गुप्त तरह से थानध्यक्ष के पास रहता है जो कोडिंग भी डाला गया है। संचालित गिरोह के द्वारा नया बाईक भी दिया गया है। गाडी की पिकअप और आवाज आपको घोलटा देंगा। उसने आगे चलते हुये इशारों-इशारों में बताया की फलां आदमी का घर है, देख लीजिये। एक साल के अंदर में चार तल्ला, ये फलां आदमी को देख लीजिये गांजा और शराब

घर बनवाने को मांगे थे 5 लाख, इनकार करने पर ले गए थे थाना

लेफ्टिनेंट कर्नल से 90 हजार घूस लेने के आरोप में राजीवनगर थानेदार निलंबित

क्राइम रिपोर्टर | पटना

राजीवनगर थानेदार नीरज कुमार को एसएसपी राजीव मिश्रा ने निलंबित कर दिया। नीरज पर लेफ्टिनेंट कर्नल अमित रंजन और उनका मकान बना रहे मुंशी चंदन कुमार को थाना में लाकर चार घंटे बैठाने, स्टेशन डायरी देर से करने और फिर नीलेश यादव मुखिया के जरिये 90 हजार रुपए लेने का आरोप लगा था। एसएसपी ने विधि- व्यवस्था डीएसपी नुरूल हक को जांच का आदेश दिया। डीएसपी ने जांच करने बाद रिपोर्ट एसएसपी को दी। उसके बाद नीरज को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया। फिलहाल इस थाना में नए थानेदार की तैनाती नहीं हुई है।

घटना के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के भाई ने की थी शिकायत

लेफ्टिनेंट कर्नल अमित रंजन और उनके भाई प्रेमित रंजन राजीवनगर रोड नंबर तीन में अपनी जमीन पर पूर्व में बने मकान के ऊपर निर्माण करा रहे थे। प्रेमित रंजन थानेदार से मकान बनाने के लिए मिले तो उनसे 5 लाख मांग की गई। उन्होंने देने से इनकार कर दिया। 23 अप्रैल 2023 को मकान बनाने के दौरान थानेदार ने एसआई शंकर सिंह को वहां भेजा। अमित और चंदन को एसआई पकड़कर थाना ले आए और दोनों को करीब 4-5 घंटे तक थाने में बैठा दिया। दोनों के ऊपर केस दर्ज किया गया। फिर नीलेश मुखिया भी थाना पहुंचे। उनके जरिये 90 हजार लेने के बाद दोनों से बांड लिखवाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद प्रेमित ने इसकी लिखित शिकायत डीएसपी से की थी।

3 माह में एसएसपी ने 5 थानेदार को किया निलंबित, एक को लाइन हाजिर

पिछले तीन माह में एसएसपी ने पांच थानेदार को निलंबित कर दिया जबकि एक को लाइन हाजिर कर दिया। इससे पहले रानी तालाब के थानेदार विमलेश पासवान और नौबतपुर थानेदार रफीकुर रहमान को बालू लदे वाहनों को पार कराने के आरोप में निलंबित किया गया था। वहीं बाइपास के थानेदार अमित कुमार को शराब मामले में जांच में हुई लापरवाही में सस्पेंड किया गया था। बिहटा के थानेदार सनोबर खान को बिहटा में शिक्षक के इकलौते बेटे के अपहरण और हत्या में हुई लापरवाही में लाइन हाजिर कर दिया था। इसी थाना के थानेदार प्रमोद कुमार को इसलिए निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हाजत में बंद कर दिया पर स्टेशन डायरी नहीं की और फिर छोड़ दिया। हाल में ही पत्रकारनगर के थानेदार मनोरंजन भारती को एक बाइक चोरी का प्राथमिकी नहीं करने पर एसएसपी ने निलंबित कर दिया। फिलहाल पत्रकारनगर, बिहटा और राजीवनगर थाना प्रभार में चल रहा है।

ले. कर्नल से 90 हजार वसूलने के आरोप में थानेदार निलंबित

जागरण संवाददाता, पटना : भयादोहन कर लेफ्टिनेंट कर्नल अमित रंजन और उनके मुंशी चंदन कुमार से 90 हजार रुपये वसूलने के आरोप में मंगलवार को राजीव नगर थाने के थानेदार नीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया।

डीएसपी (विधि-व्यवस्था) नुरुल हक की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में डीएसपी ने थानेदार पर कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण और भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी होने का परिचायक बताया है। बताया जाता है कि प्रेमित रंजन का मकान राजीव नगर रोड नंबर तीन में है। 23 अप्रैल को उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अमित रंजन मकान में काम करवा रहे थे। इस बीच राजीव नगर थाने के दारोगा शंभू शंकर सिंह पहुंचे और अमित एवं निर्माण कार्य करा रहे मुंशी चंदन को थाने लेकर चले गए। बिना कारण उन्हें चार-पांच घंटे तक बैठाने के बाद थानेदार ने पुलिस के बयान पर प्राथमिकी की। इसके बाद वार्ड पार्षद पति निलेश यादव रात में थाने पर आए। प्रेमित ने उनके माध्यम से थानेदार को 90 हजार रुपये दिलवाए, जिसके तुरंत बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और मुंशी को बांड भरा छोड़ दिया गया। रुपयों की लेन-देन थानेदार ने थाने के पोर्टिको में खड़ी सरकारी बोलेरो में की थी। शिकायत मिलने पर डीएसपी ने दारोगा और सिपाही का बयान लिया।

की तस्करी से पांच तल्ला के साथ इम्पॉटेंट लक्जरी गाड़ी, बुलेट बाईक, कई जगहों पर जमीन, यानि सबकुछ जो एक अच्छे इंसान पढ़-लिखकर कुछ नही कर सकता, सिवाय भोजन की व्यवस्था, मकान के किराये और दो बच्चों को पेट पोषने के अलावे, जिंदगी झंड के समान रहता है।

वैसे हर्ष फायरिंग के मुजरिम को पकड़ने मे थानाध्यक्ष नकाम रहे है, जो सर्विदित है। इनके रहते हर्ष फायरिंग के अपरधी न तो पकड़े जाएंगे और ना ही जिस रिवाल्वर से फायरिंग किया गया, उसको जब्त किया जाएगा। यदि बहुत दबाव बना तो नकली तमंचा दिखाने की भी व्यस्था कर लिया गया है। सोर्स कि जानकारी हम नही बता सकते। पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था, पटना से बात करने पर पता चला कि अपराधी को पकड़ने के किसी भी प्रकार कि एसआईटी गठित नही कि गई है, जबकि इस संबंध मे वरीय पुलिस अधीक्षक के बयान तो हवा मे तैरने लगी। सिर्फ इस तरह के बयान आई वास के लिए दिया गया प्रतीत हुआ। हां, मामले मे पुलिस जरूर ततपर है कि फटाफट अपरधी के पुलिस डायरी कोर्ट चला जाए, जिससे कि वेल मिल सके, किन्तु सवाल उठता है राजा राजकुमार के संबंध उन अपराधियों के साथ पूर्व से ही था, जिसने जमीन दिलवाया। जिनके साथ वोटिंग कि गई, उनके विरुद्ध जांच और कार्रवाई आखिर कब होंगी एस.एस.पी. साहब। नकटा दियारा के वर्तमान उप मुखिया को धमकी दिया जा रहा है तथा राजा राजकुमार पाण्डेय के द्वारा उस सोर्स को अपने गुर्गे से पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह बात लोगों तक पहुंचा कैसे? लेकिन एक बात जान लीजिये एस.एस.पी. साहब, कुछ भी घटना घटित होती है तो समझ लीजिये इसमें राजकुमार पांडे संलिप्त हैं और उनके पीछे केवल सच होगा।

हमने पिछले आलेख में "यहां के थाना अध्यक्ष लुटेरा नहीं चोर है" लिखा तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई तो फिर राजीव नगर थाना के पूरी टीम द्वारा एक मोबाइल दुकान में लूट और चोरी के आरोप पर न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभी तक वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय ने जांच क्यों नहीं पूर्ण की? राजीव नगर थाना अध्यक्ष पर केवल सच का प्रमाण खुद ही हो गया और वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय ने राजीवनगर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया, लेकिन अभी भी मोबाइल चोरी के आरोप के घेरे में आए तमाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होना बाकी है। राजीव नगर आवास बोर्ड की जमीन पर पैसों का खेल किसी से छुपा नहीं है। यहां क्विक मोबाइल से लेकर, थाना अध्यक्ष और आवास बोर्ड के अधिकारियों की जब तक जेब गर्म नहीं हो जाती है, तब तक लोग अपनी ही जमीन पर आशियाना नहीं बना पाते हैं।

पुलिस को वर्दी वाला गुंडा भी कहा जाता है, आज वही हाल हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन यह कलम तब तक नहीं रुकेगा, जब तक अपराधियों से तालमेल रखने वाले दीघा थाना अध्यक्ष राज कुमार पांडे पर कार्यवाही नहीं हो जाती है।●

गंगा देवी महाविद्यालय में महालूट

पार्ट-2 और पार्ट-3 के नामांकन के नाम पर छात्राओं से लिया जा रहा था अवैध रुपया

● **सागर कुमार/के.के. सिंह**

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गंगा देवी महाविद्यालय में जब स्नातक पार्ट-2 और पार्ट - 3 के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तब कुछ छात्राओं ने केवल सच से संपर्क किया और कहा कि नामांकन के नाम पर कॉलेज में अवैध वसूली हो रही। केवल सच की टीम बिहार और देश में हो रही भ्रष्टाचार की पोल लगातार खोलते आ रहा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक जिम्मेवार मीडिया संस्थान होने के नाते हम अपना दायित्व समझते हैं कि आम छात्राओं से हो रहे इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब करें। उक्त विषय के बारे में पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हम गंगा देवी महाविद्यालय के प्राचार्या कक्ष के पास पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि प्राचार्या किसी कार्य से बाहर गई हुई है तब हमने कॉलेज के बर्शर दिलीप वर्मा से मुलाकात की। पहले तो बर्शर दिलीप वर्मा हमसे मिलने में काफी आनाकानी की और जब उन्होंने हमारे आईडी कार्ड और हमारे संस्थान के बारे में सारी जानकारी लिखित रूप से ले ली तब हमने उनसे सवाल पूछा कि आपके कॉलेज के स्नातक पार्ट-2 और पार्ट-3 के नामांकन में कितना रुपया लग रहा है तो उन्होंने कहा कि 300 रू० मात्र लिया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिया जाता है बाकी तो सभी फीस छात्राओं का माफ है। हमने पुनः उनसे सवाल किया की छात्राएं तो कह रही है कि उनका 1200 से 1300 रू० तक लग जा रहा है

गंगा देवी महिला महाविद्यालय
लोहिया नगर (कंकड़बाग) पटना-20
B.A. Part-II
1371
300
कुल योग 300

फॉर्म भरने में, तब उन्होंने झुंझलाते हुए कहा की 100 या 200 रू० फॉर्म का लग रहा होगा बस और कुछ नहीं। हमने फिर तीखे सवाल दागे कि 'आप कॉलेज के कैसे बर्शर हैंः की आपको नामांकन कि ना तो पूरी प्रक्रिया मालूम है और ना ही नामांकन में कितना पैसा लिया जा रहा है, वो ही पता है।' इतने पर उनका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया और वह हम पर बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए। बर्शर दिलीप वर्मा ने हम से अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि उन्हें अत्यधिक काम है परंतु हम भी लोकतंत्र के चौथे सिपाही थे हार कहां मानते, हमने उनसे विनम्र लफ्जों में कहा कि हम भी यहां आपके ही कॉलेज के छात्राओं के हित के लिए सवाल पूछ रहे हैं और यह भी एक काम ही है कृपया इसे गंभीरता से लेवें परंतु माननीय बर्शर दिलीप वर्मा महोदय को इतना समय कहां कि वह छात्राओं की समस्याओं पर ध्यान दे सकें, क्योंकि नियम के विरुद्ध कॉलेज में कुल 3 से 4 पदों का दायित्व संभाल रहे बर्शर महोदय अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसके बाद जब हमने उनसे यह जानकारी देनी चाहिए कि कॉलेज में नामांकन प्रभारी कौन है और उनसे कैसे मुलाकात होगी तब बर्शर महोदय ने यह कह कर अपना

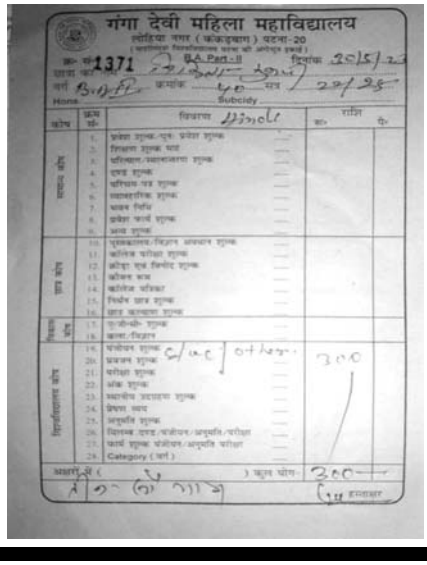

पल्ला झाड़ लिया कि जाइए कॉलेज में पता कर लिजीए।

सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिली कि कॉलेज कैंपस में सभी छात्राओं को यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी मीडिया के लोगों को कोई भी जानकारी नहीं देनी है लेकिन कहते हैं ना 'सांच को आंच क्या'। गंगा देवी महाविद्यालय की छात्राओं ने ष्केवल सचष के कैमरे पर ऐसी सच्चाई बता दी जिसे सुनकर हर कोई हतप्रभ रह जाए, हर कोई चौकं जाए। छात्राओं ने एक-एक कर कॉलेज प्रशासन की सारी पोल खोल कर रख दी। गंगा देवी महाविद्यालय की छात्राओं ने बताया कि स्नातक पार्ट-2 और पार्ट-3 के नामांकन में उनके कुल 1300 रुपए तक लग जा रहे हैं, तब हम भी चौंक गए। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज के ही बर्शर दिलीप वर्मा ने बताया था की 300 रू० इलेक्ट्रिसिटी का और 200 रू० फॉर्म अर्थात कुल 500 रू० लग रहे हैं लेकिन छात्राओं का कहना है कि 1300 रुपए लग रहे हैं तो यह कैसे संभव है और तब ही हमें इसमें एक बड़े भ्रष्टाचार की बू आने लगी। इसको समझने के लिए हमने और भी कई छात्राओं से बात की तथा हमने कई साइबर कैफे में भी जा कर यह जानने और समझने का प्रयास करने लगे कि आखिर छात्राओं से कब-कब और कितना-कितना रुपए किन-किन चीजों के लिए लिया जा रहा है। और अंतत: हम नतीजे पर पहुंचे नतीजा काफी चौंकाने वाला था। अब हम आपको नामांकन की इस व्यवस्था को समझाते हैं। सबसे पहले स्नातक पार्ट-2 और पार्ट-3 की छात्राओं को किसी साइबर कैफे में जाकर अपने पार्ट-वन के आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके एक फॉर्म भरना था और फॉर्म भरने के अंतिम प्रोसेस के रूप में 520 रू० प्लस 88 रू० आईटी चार्जेस मतलब कुल मिलाकर 608 रू० ऑनलाइन कॉलेज को पेमेंट करना पड़ता था और अगर आप फॉर्म साइबर कैफे से भरवाया है तो उसको भी 112 रू० देने पड़ते थे। एक ध्यान देने वाली बात यह है की पेमेंट कॉलेज को होता है 608 रू० लेकिन दिखता है 520 रू० ही अर्थात आईटी चार्ज 88 रू० वह कहीं दिखता नहीं है लेकिन पेमेंट करते समय वह 88 रू० अलग से कट जाता है। तो यहां तक कॉलेज को कुल गए 608 रुपए और साइबर कैफे वाले का 112 रुपए मिलाकर छात्राओं के पैकेट से कुल 720 रू० निकल गए। अब छात्राएं कॉलेज पहुंचती हैं और लाइन में लगकर नामांकन हेतु एक फॉर्म लेती है जिसके एवज में काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति छात्राओं से 300 रू० लेता है और ना ही उसकी कोई रसीद देता है ना ही उस फॉर्म पर फॉर्म की कीमत 300 रू० लिखा हुआ है। खेल यही नहीं समाप्त हुआ अभी और आगे भी है इसके बाद जब छात्राएं उस फॉर्म को भर कर वापस जमा करती हैं तो उससे पहले उन्हें एक 300 रू० का चालान बैंक में जमा करके उसकी रसीद भी उस फॉर्म के साथ अटैच करके देना पड़ता है। तो अब कॉलेज आने पर छात्रा के पैकेट से लग गए कुल मिलाकर 300+300 = 600 रू० और ऑनलाइन छात्रा के लग चुके थे 720 रुपए अगर एक छात्रा के नामांकन के पूरे रुपए को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर एक छात्रा से कुल 720+600 =1320 रुपया ले लिया जाता है, जिसमें कुल 1208 रुपए डायरेक्ट कॉलेज प्रशासन को जाते हैं और 112 रू० साइबर कैफे वाले को। अब सबसे रोचक बात यह है कि इस पूरे नामांकन प्रक्रिया की और नामांकन में कितने पैसे लग रहे हैं उसकी जानकारी ना कॉलेज के बर्शर दिलीप वर्मा को है ना नामांकन प्रभारी विनीता मिश्रा को और ना ही कॉलेज के प्राचार्या को। अब सोचिए कि यह सब पैसा आखिर जा कहां

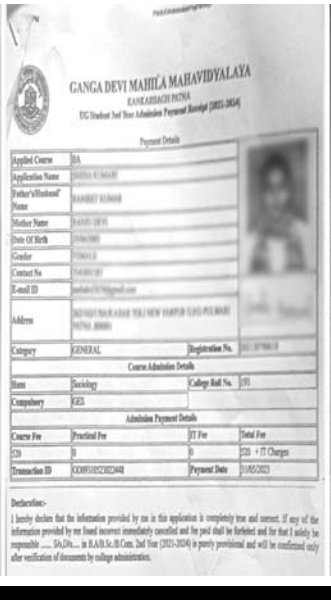

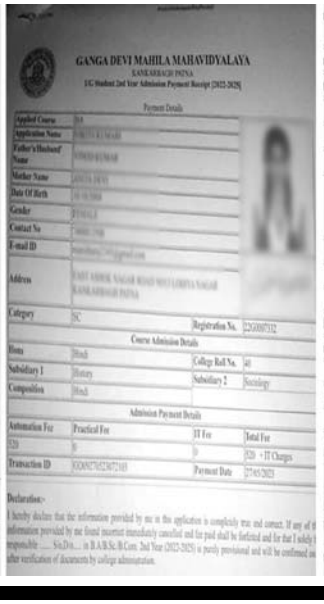

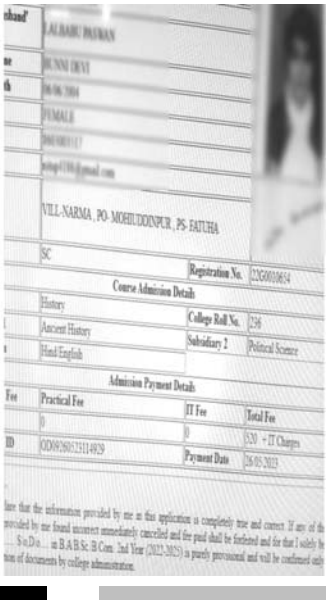

प्रोफेसर डॉक्टर मनी बाला

रहा है। एक चौंकाने वाली बात और है कि इन सब प्रक्रियाओं से विश्वविद्यालय भी अवगत नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय के भी किसी अधिकारी या पदाधिकारी को कॉलेज में इस प्रकार का नामांकन हो रहा है इसकी भी सूचना नहीं है। यहां पर कॉलेज के बर्शर दिलीप वर्मा का झूठ साफ-साफ पकड़ा गया तब हम फिर दोबारा से उनके चेंबर में जाकर ऑन रिकॉर्ड उनसे बात की और उनसे यह बताया कि छात्राएं तो कह रही हैं कि उनका 1320 रुपया लग रहा है और आप बोल रहे हैं कि मात्र 500 रू० लग रहा है तो आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं , इतने पर ही वह काफी आक्रामक हो गए और उनके इशारे पर कुछ और भी गुंडे प्रवृत्ति के कर्मचारी थे जिसमें नरेश शर्मा और उसके अन्य साथी गण मिलकर हमारा कैमरा (मोबाइल) छीन कर जमीन पर फेंक दिया जिस कारण हमारा मोबाइल टूट गया और फिर कॉलेज के उन गुंडों के द्वारा हमें धक्का-मुक्की करके कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो एक-एक छात्राओं से ऑनलाइन 608 रू० और बिना रसीद दिए 300 रू० फार्म का लिया जा रहा है वह आखिर कहां जा रहा है , किस मद में जा रहा है और किस लिए जा रहा है इसकी जानकारी अभी तक हमें किसी ने भी नहीं दिया। इसी से हमें संदेह हो रहा है कि अब पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है और इसलिए केवल सच ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन सहित राजभवन को भी लिखित रूप से दिया है।

☞ **खबर दिखाने पर गंगा देवी महाविद्यालय के बर्शर दिलीप वर्मा और कॉलेज के कुछ गुंडों ने केवल सच की टीम का छीना कैमरा और की धक्का-मुक्की :-** केवल सच ने जब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गंगा देवी महाविद्यालय में पार्ट-2 और पार्ट-3 में हो रहे अवैध नामांकन और उस नामांकन में अवैध वसूली को लेकर खबर दिखाया तब वहां के कर्मचारी और बर्शर दिलीप वर्मा, नरेश शर्मा, अनिल सहित कॉलेज के कुछ गुंडों ने केवल सच की टीम का मोबाइल छीनने का प्रयास किया और धक्का-मुक्की किया, परंतु फिर भी हमने हार नहीं माना हमने खबर चलाया, खबर दिखाया गंगा देवी में हो रहे इस महा भ्रष्टाचार की पोल खोली और यहीं तक नहीं उसके बाद जाकर हम लोगों ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को उक्त घटना की जानकारी दी। माननीय कुलपति महोदय ने त्वरित हमारे बातों पर संज्ञान लेते हुए गंगा देवी महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर डॉक्टर मनी बाला को नामांकन पर तुरंत रोक लगाने को कहा। साथ ही हमने अपने साथ हुए इस प्रकार के व्यवहार के लिए कंकड़बाग थाने में उक्त बर्शर दिलीप कुमार और उनके अन्य साथियों के खिलाफ लिखित शिकायत भी की।

☞ **पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन की नई व्यवस्था बहाल :-** 'केवल सच' केवल खबर नहीं दिखाती बल्कि हम आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं । आपके हित के लिए सवाल पूछना और आपके समस्या के निवारण के लिए वरीय अधिकारियों और नेताओं तक आपकी बात को पहुंचाना भी हमारा परम दायित्व है। और इसलिए हमने ना केवल खबर दिखाया बल्कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह महोदय से यह भी गुहार लगाई की पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया काफी जटिल है। वर्तमान में पीपीयू में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे बच्चियों को पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और ऑनलाइन ही पैसा भी देना पड़ता है और फिर उसके बाद दोबारा कॉलेज जाकर फॉर्म खरीद कर चालान कटा कर नामांकन

पत्रांक 15/एम 1-226/2009 – 1007 .
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

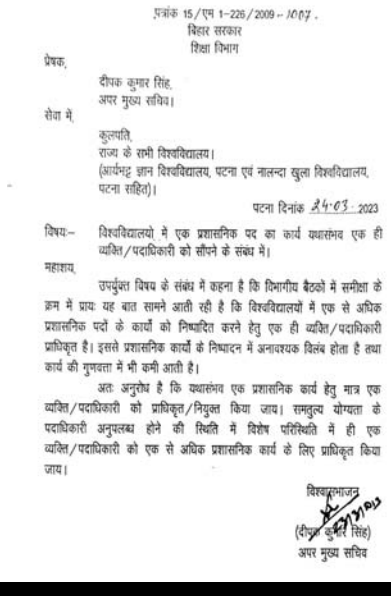

प्रेषक,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
कुलपति,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।
(आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना सहित)।

पटना दिनांक 24.03.2023

विषयः- विश्वविद्यालयो में एक प्रशासनिक पद का कार्य यथासंभव एक ही व्यक्ति/पदाधिकारी को सौंपने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय बैठकों में समीक्षा के क्रम में प्रायः यह बात सामने आती रही है कि विश्वविद्यालयों में एक से अधिक प्रशासनिक पदों के कार्यों को निष्पादित करने हेतु एक ही व्यक्ति/पदाधिकारी प्राधिकृत है। इससे प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है तथा कार्य की गुणवत्ता में भी कमी आती है।

अतः अनुरोध है कि यथासंभव एक प्रशासनिक कार्य हेतु मात्र एक व्यक्ति/पदाधिकारी को प्राधिकृत/नियुक्त किया जाय। समतुल्य योग्यता के पदाधिकारी अनुपलब्ध होने की स्थिति में विशेष परिस्थिति में ही एक व्यक्ति/पदाधिकारी को एक से अधिक प्रशासनिक कार्य के लिए प्राधिकृत किया जाय।

विश्वासभाजन
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

प्रोफेसर दिलीप वर्मा

कराना पड़ता है। इस प्रकार दोनों जगह अलग-अलग तरीके से नामांकन कराने में काफी छात्र - छात्राएं हराश होते हैं, परेशान होते हैं , और इस व्यवस्था में समय भी अत्यधिक लगता है साथ ही कॉलेजों के द्वारा छात्राओं से अवैध पैसा भी वसूला जाता है। हमने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को यथास्थिति बधाई और आग्रह किया कि नामांकन की प्रक्रिया केवल एक ही बार होनी चाहिए या तो नामांकन ऑनलाइन एक बार हो या फिर कॉलेज में बुलाकर ही एक बार नामांकन हो , तो हमारी बातों पर मुहर लगाते हुए कुलपति महोदय ने नामांकन की नई व्यवस्था बहाल की। नामांकन की इस नई व्यवस्था के अनुसार अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को साइबर कैफे नहीं जाना होगा। नामांकन की सारी प्रक्रिया कॉलेज से ही होगी और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो उसकी सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की होगी। इस प्रकार की व्यवस्था से नामांकन की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी, जिसके लिए 'केवल सच' माननीय कुलपति आर के सिंह महोदय को हृदय से धन्यवाद देती है।

☞ **गंगा देवी महाविद्यालय के कई पदों को सुशोभित करते हैं दिलीप वर्मा :-** दिनांक 24/03 /2023 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 15/ड-1-226/2009-1007 में स्पष्ट रूप से सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रशासनिक पदों का कार्य यथासंभव एक ही व्यक्ति या पदाधि कारी को सौंपा जाए अर्थात एक पदाधिकारी को एक ही प्रशासनिक कार्य सौंपा जाए और दूसरे पदाधिकारियों को दूसरा कार्य परंतु गंगा देवी महाविद्यालय में सभी नियमों को ताक पर रखकर दबंग प्रोफेसर दिलीप वर्मा को कॉलेज के तीन प्रशासनिक पदों पर रखा गया है :-

1. बितेक्षक (बर्शर), गंगा देवी महाविद्यालय

आवश्यक सूचना

B.A/B.Sc Part II एवं **Part III** के छात्राओं को सूचित किया जाता है कि **B.A/B.Sc Part II** सत्र 2022 –2025 एवं **B.A/B.Sc III** सत्र 2021–2024 का नामांकन, परीक्षाफल प्रकाशन के बाद लिया जायेगा।

नामांकन प्रभारी
गंगा देवी महिला कॉलेज
पटना–20

केवल सच के खबर दिखाने के बाद कॉलेज में लगाई गई सूचना, परंतु इसमें हस्ताक्षर ही गायब है।

2. परीक्षा नियंत्रक , गंगा देवी महाविद्यालय
3. समन्वयक , बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन

इसके साथ साथ विशेष परिस्थिति में इन्हें नोडल पदाधिकारी भी बनाया जाता है और कॉलेज में इनकी हनक और रुतबा इसी से समझी जा सकती है कि नामांकन प्रभारी नहीं रहने के बावजूद भी नामांकन की सारी प्रक्रिया को भी डील प्रोफेसर दिलीप वर्मा ही करते हैं। कॉलेज कैंपस में ऑफ द रिकॉर्ड दबी जुबान में लोग यह भी कहते हैं कि गंगा देवी महाविद्यालय में प्राचार्या प्रोफेसर डॉक्टर मनी बाला की भी मर्जी नहीं चलती है क्योंकि कॉलेज के दबंग और सत्ता तक पहुंच रखने वाले प्रोफेसर दिलीप वर्मा पूरे कॉलेज को अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं और अपने इशारे पर ही कॉलेज का पूरा तंत्र चलाते हैं। और कॉलेज से जो भी अवैध कमाई होती है उसको अपने और सहयोगीयों के बीच बांट देते हैं।

☞ **निष्कर्ष :-** हमारा प्रश्न बस इतना ही है की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गंगा देवी महाविद्यालय में जो छात्राओं से अवैध रुपए लिए जाते हैं वह किस खाते में जाते हैं ? वह पैसे किस मद में लिए जा रहे हैं ? आखिर उन पैसों को कहां और किस प्रकार से कब-कब ,कितना कितना खर्च किया जा रहा है? और कॉलेज के प्रोफेसर दिलीप वर्मा को नियम के विरुद्ध आखिर कैसे 3-3 और कभी-कभी 3 से भी ज्यादा प्रशासनिक पदों का दायित्व दिया जा रहा है? क्या गंगा देवी महाविद्यालय में प्रोफेसर दिलीप वर्मा से काबिल कोई और प्रोफेसर नहीं है? केवल सच के खबर दिखाए जाने के बाद फिलहाल उक्त नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि अभी तक के हुए नामांकन में जो पैसे छात्राओं से अवैध रूप से लिए गए हैं छात्राओं के उन पैसों को कब तक उन्हें वापस लौटाया जाएगा और कैसे लौटाया जाएगा ? हमने उपरोक्त विषय के संबंध में राजभवन को भी लिखित रूप से जानकारी दी है और राजभवन ने भी उक्त विषय पर संज्ञान लिया है। अंत में हम केवल सच के माध्यम से सरकार से और राजभवन से यह मांग करते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों विशेष कर गंगा देवी महाविद्यालय की तत्काल ऑडिट की जाए और यह पता लगाया जाए छात्राओं से लिया जाने वाला पैसा आखिर सरकार तक नहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है और कॉलेज प्रशासन उससे का क्या कर रही है । इस प्रक्रिया में कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि यह केवल छात्राओं के साथ दगाबाजी नहीं है बल्कि बिहार सरकार के साथ भी इन कॉलेजों के द्वारा बड़ी ठगी किया जा रहा है और सरकार की छवि को धूमिल करने का भी प्रयास इन कॉलेज में बैठे हुए मठाधीश ओं के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि जब सरकार ने छात्राओं की पढ़ाई निःशुल्क कर दिया है, सरकार ने छात्राओं को पढ़ाने के लिए फंड दे दिया है फिर भी यह कॉलेज प्रशासन आखिर क्यों छात्राओं का पैसा ले रहे हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है ? इन सब की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी के निर्माण करके निष्पक्ष जांच किया जाए। हम सरकार और राजभवन से अभी आग्रह करेंगे कि गंगा देवी महाविद्यालय के तात्कालिक बर्शर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर, बीसीए प्रोफेसर दिलीप वर्मा की संपत्ति की भी जांच की जाए क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका इनकी ही प्रतीत हो रही है परंतु फिर भी हम अपनी तरफ से किसी को दोषी नहीं मानते हैं। क्योंकि दोषी को ढूंढना सरकार का काम है और सजा देना न्यायालय का काम है हमने तो बस जनता की ,समाज की और छात्राओं की आवाज उठाई है , उनकी समस्याओं को प्रमुखता से दिखाया है और हम समस्त बिहार के छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपके साथ भी कॉलेज या विश्वविद्यालय के द्वारा कोई ठगी की जा रही है कोई अवैध पैसा लिया जा रहा है या आपके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है तो आपको भी उठानी है अपनी कलम और लिख देना है केवल सच के नाम एक संदेश क्योंकि हम आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं सर पर कफन बांध के हम बिहार के आम आवाम के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक सिपाही के रूप में अग्रसर हैं।

अंत में हम आपके पास एक सवाल छोड़कर जाते हैं फैसला आपको करना है कि क्या किसी कॉलेज कैंपस में किसी विश्वविद्यालय कैंपस में या किसी भी प्रांगण में अगर कोई पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही के रूप में जाकर जनता की आवाज उठाता है ,सत्ता के दलालों से आंखों में आंखें डाल कर सवाल पूछने का काम करता है, अपने जान की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर 'सच' ढूंढ कर लाता हो तो क्या उसके कैमरे को छीन लेना उचित कार्य है? क्या उसके साथ गाली गलौज करना ठीक काम है? क्या उसे धक्का-मुक्की करके कैंपस से बाहर निकालना सही कार्य है? इन सवालों के जवाब मैं समाज के नाम छोड़ता हूं, छात्रा बहनों पर छोड़ता हूं। फैसला आपको करना है कौन सही है, कौन गलत? ●

कॉलेजों के प्राचार्य को कहा गया है कि वे छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन नामांकन में उनकी मदद करें। साइबर कैफे में छात्र नामांकन लेते हैं जिससे कई तरह की परेशानी होती है। कॉलेज स्वयं ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करें और सेलेक्शन होने के बाद की प्रक्रिया को पूरा करें।

प्रोफेसर आर के सिंह
कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय

मनेर थाना प्रभारी राजीव रंजन का गजबे कमाल

घटना के डेढ़ महीने बाद लिखी एफ.आई.आर., कार्रवाई अभी तक नहीं

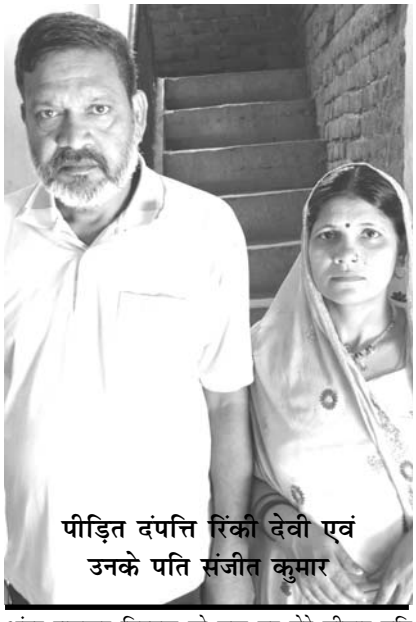
पीड़ित दंपत्ति रिंकी देवी एवं उनके पति संजीत कुमार

● सागर कुमार/के.के. सिंह

बिहार की राजधानी पटना की प्रशासनिक कमान जबसे वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के हाथ में आई है ,सारी पुलिस महकमा में खलबली मची हुई है। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव मिश्रा पटना आते ही अपने कई फैसलों और काम करने के तरीकों के वजह से चर्चा में हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सभी थानों में अनिवार्य रूप से रिसीविंग अर्थात पावती देने की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत करवाया और उसके बाद सही लगातार थानों में प्राथमिकी दर्ज होने की संख्या बढ़ रही है और पटना के अधिकांश थानों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में लोगों की प्राथमिकी दर्ज हो रही है परंतु अभी भी पटना जिले में कुछ ऐसे थाने हैं जो कि एसएसपी पटना के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी भी पटना जिले में ऐसे कुछ थानेदार हैं जो अपने आपको अपने थाने का भगवान समझते हैं और अपने आगे किसी भी पीड़ित का दु:ख दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता है। हम बात कर रहे हैं मनेर थाना की और उनके प्रभारी राजीव रंजन की। यहां पर आपको बताते चलें कि मनेर थाना आए दिन ट्रैक्टरों पर अवैध और ओवरलोडेड बालू का पासिंग करवाने, मनेर चौक पर पैसे लेकर अवैध ऑटो स्टैंड लगवाने , थाना में दलालों की पैरवी चलवाने और थाना की गाड़ी एक प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) से चलवाने सहित कई प्रकार के आरोप लग चुके हैं और आम जनता ऑफ द रिकॉर्ड इन सभी बातों को लगातार दोहराते रहती है और केवल सच ने भी कई बार इन खबरों को दिखाया है।

अब बात करते हैं उस काली रात का जब मनेर थाना के अंतर्गत एक पीड़िता के घर में आधी रात को दो बदमाश हथियार के बल पर घुस गए और पीड़िता के बीमार पति के साथ मारपीट की साथ ही पीड़िता के साथ छेड़खानी की , और हथियार के बल पर दोनों अपराधी पीड़ित महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दोनों पति-पत्नी और पहले से अपहृत उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे देता है और वहां से भाग जाता है । मौके पर ही 112 नंबर पुलिस को सूचना दी जाती है , पुलिस आती है परंतु तब तक अपराधी भाग गए होते हैं।

इतना सब कुछ होता है और इतना सब कुछ होने के बाद जब वह पीड़ित महिला अपने बीमार पति के साथ सुबह में मनेर थाना पर जाकर घटना की प्राथमिकी दर्ज कराना चाहती है तो मनेर थाना प्रभारी राजीव रंजन पीड़ित दंपत्ति को अपशब्द कह के थाने से भगा देते हैं। उसके बाद पीड़ित महिला अपने बेटी और अपने बीमार पति के जान की सलामती की गुहार लगाने के लिए पटना के तमाम पुलिस के बड़े पदाधिकारियों सहित नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के पास भी पहुंचती है और तब जाकर घटना से लगभग 45 दिन बाद थाना प्रभारी नींद से जगते हैं और तब घटना की प्राथमिकी दर्ज होती है। हमने उक्त मामले में पीड़ित दंपत्ति रिंकी देवी जी से बात की हम यहां पर उनके शब्द उन्हीं की जुबानी में अक्षरश: लिख रहे हैं :-

☞ **पीड़िता रिंकी देवी के अनुसार** :-मैं रिंकी देवी पति संजीत कुमार, जमुनीपुर चर्च, थाना+पोस्ट मनेर जिला पटना की स्थाई निवासी हूं। दिनांक 16 अप्रैल 2023 और दिनांक 17 अप्रैल 2023 के बीच रात्रि करीब 1:30 बजे मेरे घर में एक युवक मोहम्मद अमन अपने एक साथी के साथ अंदर घुसकर पिस्टल के बल पर मेरे बीमार पति के साथ मारपीट किया और साथ में मेरी इज्जत पर भी हाथ डालकर फरार हो गया। उक्त घटना की पृष्ठभूमि यह है कि मेरी बेटी आकांक्षा शादीशुदा है और उसके पति राहुल कुमार, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान में तैनात हैं। विगत फरवरी माह में राजस्थान से गया आने के क्रम में मेरी बेटी आकांक्षा दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही गुम हो गई थी जिस संबंध में मेरे दामाद द्वारा गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। दिनांक 26 फरवरी 2023 को मनेर थाना में मैंने लिखित सनहा दर्ज कराया था जिसमें मैंने साफ-साफ आशंका जताई थी कि मेरी बेटी के अपहरण में मोहम्मद अमन पिता मोहम्मद सरवर , मलिक मंजिल, शाहगंज , थाना - सुल्तानगंज , महेंद्रु जिला पटना, का हाथ है। उक्त घटना के पीछे मोहम्मद अमन की गहरी और भयानक साजिश है। दिनांक 16 अप्रैल 2023 को मध्य रात्रि के लगभग 12:00 से 1:00 दो नकाबपोश बदमाश जमुनीपुर मनेर चर्च स्थित मेरे घर के अंदर घुस कर पिस्टल के बल पर मेरे और मेरे पति के साथ मारपीट की। फिर पिस्टल द्वारा जान से मारने का भय दिखाते हुए कहने लगा कि, ''तुम्हारी लड़की आकांक्षा मेरे ही कब्जे में है और अगर तुम पुलिस के पास जाओगी या उसे खोजने की अन्य प्रयास करोगी, मुझ पर और मेरे पिता पर सामाजिक दबाव डालने का प्रयास करोगी तो तुम्हारी लड़की को तो जान से मार ही

देंगे उसके बाद तुम्हारे पति को भी गोली मारकर सारा कहानी ही खत्म कर देंगे''। बदमाशों के भागने के साथ ही मैं काफी तेज आवाज में चिल्लाई और अपने घर के बाकी सदस्यों तथा आस-पड़ोस के लोगों से गुहार लगाई कि वे लोग उस बदमाश को पकड़ ले नहीं तो उनकी बेटी की हत्या हो जाएगी। काफी शोरगुल की आवाज सुनकर मेरे आस पड़ोस के सभी लोग एकत्रित हो गए मैंने त्वरित प्रशासन को 112 नंबर पर फोन करके बिहार पुलिस को घटना की सूचना दी। थोड़ी देर में घटनास्थल पर 112 नंबर की पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी मुझसे और बाकी लोगों से लिया और मुझे सुबह 8:00 बजे मनेर थाना में आकर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। दूसरे दिन 17 अप्रैल 2023 को सुबह मैं मनेर थाना जाकर उक्त घटना की लिखित शिकायत थाना प्रभारी राजीव रंजन को दी। परंतु थाना प्रभारी मनेर राजीव रंजन ने संवेदनहीनता को पार करते हुए ,अपने महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करके बोले कि तुम और तुम्हारी लड़की दोनों बदचलन हो और यह सब उसी का परिणाम है, मैं तुम्हारी प्राथमिकी दर्ज नहीं करूंगा तुम्हें जहां और जिसके पास जाना है जाओ लेकिन यहां से भाग जाओ। अगले दिन दिनांक 18 अप्रैल 2023 को सहायक पुलिस अधीक्षक दानापुर को भी उक्त घटना की लिखित जानकारी दी. दिनांक 18 अप्रैल 2023 को ही अपने एक परिचित के सलाह पर नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर जाकर न्याय की गुहार लगाई घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने थाना प्रभारी मनेर से फोन पर पूछा तो थाना प्रभारी ने उन्हें भी गुमराह करने का प्रयास किया परंतु जब उन्होंने मेरे घर में आधी रात को दो नकाबपोश बदमाशों द्वारा पिस्टल के बल पर मेरे पति के साथ मारपीट

एवं मेरे बीमार पति और अपहृत पुत्री आकांक्षा को जान से मार देने की धमकी संबंधित घटना के बारे में बताया तो थाना प्रभारी ने उनसे कहा कि रिंकी देवी को थाना भेज दीजिए मैं इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करता हूं। उसी दिन जब मैं पुन: मनेर थाना प्रभारी राजीव रंजन के पास जाकर घटना की लिखित आवेदन दी तो उन्होंने मुझे एक पावती देकर घर वापस भेज दिया फिर उस दिन के बाद से लगातार कई दिनों तक अपने बीमार पति को लेकर मनेर थाने का कई चक्कर काटने एवं थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी आज तक और अभी तक मनेर थाने में न ही उक्त घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है और ना ही मेरी अपहृत बच्ची की जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी मनेर राजीव रंजन के अमानवीय संवेदनहीन और महिला विरोध ी सोच एवं व्यवहार से त्रस्त होकर दिनांक 8 मई 2023 दिन सोमवार को मैं अपने पति एवं बेटी की जान की सलामती हेतु न्याय की गुहार लगाने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा जी के कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और तब उसके बाद 30 मई 2023 को मेरी प्राथमिकी दर्ज की गई जिसकी संख्या 400/2023 है। प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक जांच के नाम पर मेरे घर या आसपास कोई भी पुलिस के पदाधिकारी नहीं आए हैं मुझे संदेह है कि मनेर थाना अपराधियों से मिल गई है क्योंकि अपराधी काफी पैसे वाले और अत्यधिक पहुंच वाले हैं अत: आने वाले समय में अगर मेरे पति और मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार मनेर थाना के प्रभारी राजीव रंजन जी होंगे।

☞ **मनेर थाना ने एफ. आई. आर. में दी गलत जानकारी** :- उपरोक्त घटना 16 अप्रैल और 17 अप्रैल के मध्य रात्रि लगभग 1:30 बजे घटित हुई और पीड़िता रिंकी देवी दिनांक 17 अप्रैल 2023 को सुबह 8:00 से 9:00 के बीच मनेर थाना को उक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदन देती है, जिसका की उसी दिन रिसीविंग देकर रिंकी देवी को थाने से भगा दिया जाता है। उसके बाद रिंकी देवी द्वारा लगातार पुलिस पदाधिकारियों और कई नेताओं से मिलकर न्याय की गुहार लगाने के बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा के आदेश पर दिनांक 30 मई 2023 को मनेर थाना उक्त घटना के संबंध में एफ आई आर 400/2023 दर्ज करती है परंतु उसमें थाना में प्राप्त सूचना की तिथि गलत लिख देती है। अब आप देखिए कि किस तरह मनेर थाना गुमराह

सेवा मे,

श्रीमान थाना ध्यक्ष महोदय,

मनेर थाना पटना

महाशय,

सादर सूचित करना है कि रिंकी देवी पति–संजीत कुमार, ग्राम–जमुनीपुर चर्च, थाना– मनेर, जिला– पटना की निवासी हूँ। आज दिनांक 16.04.2023 को करीब 1: 30 बजे रात्रि को मे अपने कमरे मे सोयी हूई थी। कि अचानक दो व्यक्ति मेरे दरवाजे के ग्रील का गेट को धक्का देकर मेरे घर के ऑगन मे घूस आए और मेरे कमरे का दरवाजा पीटकर खोलवाए। जब मे कमरे के बाहर आई तो देखी की दो व्यक्ति गमछा से अपना मुहँ बॉधकर छिपाए हुए है और गंदी–गंदी गालियॉ दे रहे है आवाज सुनकर मेरे बीमार पति जब ऑगन मे आए तो वे दोनो लात–मुक्का से मेरे पति के पेट मे मारने लगे यह कहते हुए कि तुम थाना पुलिस मे मेरे खिलाफ सुचना क्यो दे रहे है। कि मेरी बिवाहित बेटी आकांक्षा कुमारी का अमन पिता मो0 सरबर द्वारा अपहरण कर कही अज्ञात जगह पे छिपाकर रखा गया है। उसने धमकी देते हुए मुझे कहा कि यह सब करना बंद करो नही तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैने जब इसका विरोध किया तो मो0 अमन पिता– मो0 सरवर सा0 मल्लिक मंजिल शाहगंज, थाना सुलतान गंज महेन्द्रु जिला– पटना का रहने वाला है। अपने कमर से पिस्टल निकालकर मेरे कनपटी मे सटा कर बोला कि यदि इसकी सुचना कही भी या किसी थाना मे दी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मे सबसे पहले तुम्हारी बेटी को आकाक्षा को जो मेरे कब्जे मे है को गोली मार कर हत्या कर दूँगा और उसके बाद तुम्हारे पुरे परिवार को बरबाद कर दूँगा। इतने मे काफी हल्ला गुल्ला की आवाज सुनकर आस पडोस के बहुत से लोग इक्टठा होने लगे तबतक वह धमकी देते हुए भाग निकला। मुझे अत पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी बेटी आकाक्षा जो कि विगत कुछ दिनो से लापता है। को मो0 अमन के द्वारा हो अपहरण कर बंदी बनाकर किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। मो0 अमन ने मेरी बेटी आकाक्षा से दानापुर कोचिंग मे पढ़ने के दौरान परिचय सन 2019 मे ही हुआ था और वह [illegible] कदा मेरे घर पर कुछ कुछ बहाना बनाकर आया जाया करता था।

अत:– श्रीमान से सा[illegible] अनुरोध है कि इस संबंध मे उचित कानूनी कारवाई करने की कृपा करे। इस संबंध मे मैने 1[illegible] नम्बर डायल कर तत्काल घटना की सुचना भी दी थी जिस संबध मे112 नम्बर को पुलिस सुचना पाकर [illegible]त घटना की जॉच भी की है।

आपकी विश्वासी

रिंकी देवी

नाम– रिंकी देवी

पति– संजीत कुमार

सा0– जमुनीपुर चर्च

थाना– मनेर जिला पटना

मो0 न0– 9576598372

17 अप्रैल 2023 को रिंकी देवी थाना अध्यक्ष मनेर को जो आवेदन दी है, उसे खुद थाना प्रभारी ने रिसीव किया है।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118 — संख्या

आ० ह० प्रपत्र सं०-26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F.I.R.) 027700

(दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

1. *जिला पटना *अनुमंडल दानापुर *थाना मनेर *वर्ष 2023 *प्राथमिकी सं० 400/23 *तिथि 30/05/2023
(Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

2. (I) *अधिनियम (Act.) भा. द. वि. *धाराएँ (Sections) 457/341/506/504/
(II) *अधिनियम (Act.) संशोधन *धाराएँ (Sections) 323/341 –
(III) *अधिनियम (Act.) × *धाराएँ (Sections) ×
(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections)

3. (क) *अपराध घटना *दिन *तिथि 16/04/23 तिथि तक
(Occurrance of offence) (Day) (Date from) (Date to)

*समयावधि (पहर) प्रथम पहर *बजे से 1:30 *बजे तक
(Time Period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 30/05/2023 समय 22:45 बजे
(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 30/05/2023 समय 22:45 बजे
(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं० समय 22:45 बजे

सूचना का प्रकार (Type of Information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral)

5. घटना स्थल-(क) थाना से दिशा एवं दूरी पश्चिम – 0.5 km करीब बीट सं०
(ख) *पता (Address) जमुनीपुर चर्च – ग्राम [illegible] थाना मनेर जिला : पटना,
(ग) थाना [illegible] दशा में थाना का नाम × जिला ×

6. परिवादी/सूचना दाता :
(क) नाम रिंकी देवी
(ख) पिता/पति का नाम संजीत कुमार
(ग) जन्म-तिथि × (घ) राष्ट्रीयता भारतीय
(ङ) पारपत्र सं० × निर्गम तिथि × निर्गम स्थान ×
(च) पेशा
(छ) पता सा० – जमुनीपुर चर्च, थाना – मनेर, जिला – पटना।
Mo:- 9576598372

PAT/2022

करने का काम कर रही है। पीड़िता के पास 17 अप्रैल 2023 को थाने के द्वारा दिया गया रिसिविंग है उसके बावजूद भी मनेर थाना ने एफ. आई. आर. दर्ज करते समय थाना में प्राप्त सूचना की तिथि 30 मई 2023 समय 22:45 पर दिया है जो कि पूरी तरह से गलत है और झूठी है। थाना मनेर के इस गंभीर संवेदनहीन कृत्य पर त्वरित संज्ञान लेते हुए वरीय पदाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह एक मिसाल बन सके और भविष्य में इस प्रकार की गलती को दोहराने के लिए पुलिस को 1000 बार सोचना पड़े । जिससे समाज में प्रशासन के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना बढ़ सके और कानून का राज स्थापित हो सके।

☞ **निष्कर्ष** :- उपरोक्त घटनाक्रम के अनुसार यह तो तय है कि थाना प्रभारी मनेर राजीव रंजन की सोच महिला विरोधी है , और साथ ही वह एक गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं। क्योंकि एक बड़ी और संगीन घटना की जानकारी मिलने के बाद भी घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं करना और पीड़िता को थाने से डांट कर अपशब्द का कर भगा देना यह सब उनके चाल चरित्र और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करती है और सबसे मजेदार बात यह है कि उपरोक्त सभी बातों की जानकारी पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी अभी भी थाना प्रभारी मनेर राजीव रंजन अपने पद पर यथावत बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है यह तो एक मामला है ऐसे एक दो मामले चार मामले उजागर होते हैं लेकिन ना जाने पटना के और ना जाने बिहार के कितने थानों में रिंकी देवी जैसी पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए थानों दर थानों का चक्कर काट रहीं हैं और ना जाने पटना और बिहार के कितने थानेदार राजीव रंजन जैसे गैर जिम्मेवार, अमानवीय और महिला विरोधी सोच के साथ पीड़ित परिवारों का दोहन कर रहे हैं , और उनको न्याय से वंचित रखकर समस्त समाज को अपने अधिकारियों को और भारत के संविधान को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं 2-4 थाने प्रभारियों/ अधिकारियों के वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है, समाज में कई तरह की नकारात्मक बातें पुलिस के बारे में फैलती है और लोगों का विश्वास प्रशासन पर से उठ जाता है। परंतु केवल सच यह मानती है कि बिहार के 95% से अधिक पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारी ईमानदार हैं अच्छे हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं परंतु जो 5% ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनको भी ठीक काम करवाने की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, समाज की है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रखर सिपाही पत्रकार की है । क्योंकि एक ईमानदार स्वच्छ छवि वाला पत्रकार ही समाज को नई दशा और दिशा दे सकता है और हमने अपने दायित्व को समझा है इसलिए हम कहते हैं कि हम बिहार के आम आवाम के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम बिहार से भ्रष्टाचारियों को ,बेईमानों को और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को बेनकाब करके छोड़ेंगे। अंत में हमारा यही प्रश्न है कि आखिर कब तक रिंकी देवी जैसी पीड़ित दंपत्ति न्याय के लिए, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दर-दर भटकती रहेंगीं और कब तक राजीव रंजन जैसे थाना प्रभारियों की मनमर्जीयों के आगे आम जनता बेहाल होती रहेगी? हम यह पूछना चाहते हैं कि भगवान ना करे लेकिन रिंकी देवी के परिवार और उनकी बेटी के साथ कल के दिन कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? हम पूछना चाहते हैं कि घटना के लगभग 2 महीने होने वाले हैं अब तक थाना प्रभारी मनेर और उपरोक्त केस के प्रभारी सुनील कुमार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पीड़ित परिवार अभी भी सदमे में है और हर रात को घटना वाली रात दोबारा ना हो यह सोच कर आधी नींद में ही सोने को विवश है आखिर उनकी यह चिंता कब खत्म होगी? कब उन्हें न्याय मिलेगा? आखिर अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे ? आखिर उनकी अपहृत बेटी कहां है ? किस हालात में है? और कैसी है? उसकी जानकारी कब तक मिल पाएगी? सभी प्रश्नों पर मंथन करने की आवश्यकता है।●

वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग नहीं करें : ट्रैफिक एस.पी.

जिसके इरादे बुलन्द हो,जिसके कार्य में ईमानदारी झलकता हो,जो अपराधियों के लिए काल हो,जो आवाम की सुरक्षा के लिए 24 घण्टे सजग हो वैसे ही पुलिस अफसर समाज में विशिष्ट स्थान पाने में सफल होते है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक आईपीएस की,जिन्होंने अपने सेवा के अल्प समय मे ही कम्यूनिटी पुलिसिंग के बदौलत समाज में विशिष्ट स्थान बनाने में सफल तो गलत करने वाले में खौफ कायम करने में सफलता हासिल की है वह है 2018 बैच के आईपीएस बिहार कैडर पूरन कुमार झा का। मुलरूप से बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखने वाले श्री झा का बचपन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में बीता। पिताजी यही रेलवे में कार्यरत थे। यही से 12जी की पढ़ाई करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। घर में हमेशा से एजुकेशन का माहौल रहा है,छोटा भाई बैंक ऑफ बड़ौदा है वहीँ छोटी बहन ने जस्ट इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की हैं। नित्य नए प्रयोग से राजधानी को जाम से मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत पटना के ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा से हमारे पत्रिका के विशेष प्रतिनिधि श्रीधर पाण्डेय ने खास मुलाकात की जिसके संपादित कुछ अंशः-

★ बतौर ट्रैफिक एसपी आपकी प्राथमिकता क्या हैं?

सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी की पटना को जितना अधिक हो सके जाम से मुक्ति दिलाए और ट्रैफिक संचालन स्मूथ रहे।

★ बतौर आईपीएस कहाँ कहाँ योगदान दिया है और कैसा अनुभव रहा आपकी?

मुजफ्फरपुर में व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए 3 महीने बोचहा थाना में था उसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक भागलपुर नगर के रूप में एक साल कार्य किया। BSAP भीमनगर सुपौल में 1 साल 6 महीने कार्य किया और फिलवक्त ट्रैफिक एसपी पटना के रूप में योगदान दे रहा हूँ। बिहार में मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। पुलिसिंग के लिए यह काफी अच्छा स्टेट है। यहाँ की पब्लिक काफी फ्रेंडली है और कानून को मानने वाली है।

★ वर्तमान समय में बढ़ती घटना के लिए मोबाइल का प्रयोग कितना कसूरवार है?

ट्रैफिक एसपी के रूप में यही कहना चाहूँगा कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो मोबाईल फोन का प्रयोग किसी भी सुरत में नहीं करे। मोबाइल का प्रयोग करने से ध्यान डायवर्ट होता है जिससे एक्सीडेंट की चांसेज ज्यादा बढ़ जाते हैं।

★ राजधानी पटना में बढ़ते जाम के लिए मेट्रो का कार्य भी एक बाधा है, इससे निजात दिलाने ले लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?

मेट्रो का काम आने वाले समय मे मुक्ति दिलाने वाला ही होगा इससे लोगों को एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। वैकल्पिक रूप से भी हमलोग जिन रूट पर मेट्रो का कार्य चल रहा है उनसे सम्पर्क में है और मार्ग डाइवर्ट करते हैं।

★ पटना आने वाले सभी सड़कों पर खड़ी वाहन की वजह से जाम की समस्या काफी बढ़ रहीं है जबकि बाइपास इलाके में इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना भी देखने को मिलती है, इसके निजात के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहीं है?

बाइपास इलाके मे हमलोग रेग्युलेशन चेक करते हैं। रात मे भी कई बार गश्त किया जा रहा है। बाइपास थाने को दो क्रेन दिया गया है। अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होकर रोड के बीच मे खड़ी हो गई हो तो उसको हमलोग तत्काल उसको हटा देते है। बाइपास के किनारे खड़ी गाडियों से यदि ट्रैफिक संचालन में कोई परेशानी नहीं है तो उसे अभी छोड़ दिया जा रहा है।

★ बाइकर्स गैंग ट्रैफिक पुलिस को रोज चुनौती दे रहा है और इसपर नकेल कसने में पुलिस विफल हो जा रहीं है इसका कारण क्या है और निवारण के लिए क्या किया जा रहा है?

इसके लिए एसआईटी गठित की गई है जिसमें तीनों डीएसपी और तीनों Sarjent major सड़क पर उतर रहे है। लगातर चेकिंग अभियान जारी है और लोगों पर करवाई हो रहीं है।

★ राजधानी में यातायात को सुगम बनाने के लिए कितने जगहों पर चेकिंग प्वाइंट निर्धारित किए गए है?

पटना में 150 से ऊपर सेक्टर है। सभी सेक्टर पर चेकिंग जारी है इसके अलावा 15 रेग्युलेशन मोबाइल लगातार चेकिंग करते है उसके बाद गठित एसआईटी गंगा मरीन ड्राइव और अटल पथ पर काफी सजग है।

★ क्या आपको नहीं लगता राजधानी पटना की प्रमुख समस्या जाम हो गई है, इसका तत्काल निवारण कैसे सम्भव है?

पटना शहर का ट्रैफिक काफी ज्यादा है लेकिन इसको सुगम बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में पटना को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय मे ऑटोमोटिक सिग्नल,पी आर सिस्टम जिसके माध्यम से हमलोग एक सेंटर से पूरे शहर के ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते है।

★ बतौर एसपी आपके नए प्रयोग से कुछ राहत तो मिली लेकिन यह सफल नहीं हो सका?

आने वाले समय मे इसमें हमलोगों को और अधिक सफलता मिलेगी।

★ राजधानी पटना का जंक्शन के दोनों भाग का जाम यथावत है कैसे सुधरेगी यह स्थिति?

पटना जंक्शन को फ्री वेडिंग जोन बना दिया गया है। जो कबाड़ी मार्केट था उसको हमलोगों ने वेडर जोन चिन्हित किया है। वहाँ स्मार्ट सिटी के अंदर एक मल्टीप्लेक्स माडल हब बनाया जा रहा है जिसके अंदर वेडिंग जोन के साथ आपको एक बड़ा गाड़ी पार्क जोन भी मिलेगा। वर्तमान समय में चिरैयाटांड फ्लाइओवर जो है उसके नीचे पूरी तरह से खाली करा दी गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से बैरिकेडिंग करके उसको ग्रीन एरिया के रूप में चिन्हित कर रहे है।

★ कोई खास प्रयोग जिसके वजह से आप पटना को जाम से मुक्ति के साथ राजधानी वासियों के दिल मे सदैव स्थान बना सके?

सबसे पहले हमलोग ने दो एरिया को चिन्हित किया है। रेलवे स्टेशन पर हमलोग प्रथम चरण मे कबाड़ी मार्केट खाली करवाए गए। रेलवे ने हमे 350×25 मीटर का एक जगह चिन्हित करके दिया है जिसको उन्होंने हमे आने वाले 1 से डेढ़ महीने के अंदर हमे सौप देंगे। इसके माध्यम से हमलोग सभी ऑटो को वही पर लगवाया करेंगे,दूसरी चीज की कंकड़बाग जाने वाले जितने भी ऑटो है उनको करबिगहिया होकर चलाना है जिसमें कुछ राहत होगी। उसके बाद हमलोग करगिल चौक की तरफ बढ़ेंगे।

★ केवल सच के माध्यम से बिहार को जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?

केवल सच के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ट्रैफिक के सभी नियम आपके सेफ्टी के लिए ही बने है। हमारा मुख्य काम यही होता है कि जितना कम हो एक्सीडेंट होने से रोक सके। आप ट्रैफिक सिग्नल को कभी न तोड़े, अगर बाइक से निकल रहे है तो बिना हेल्मेट के बाहर नहीं निकले, बिना सीट बेल्ट का गाड़ी में यात्रा न करे, रेड लाइट न तोड़े।

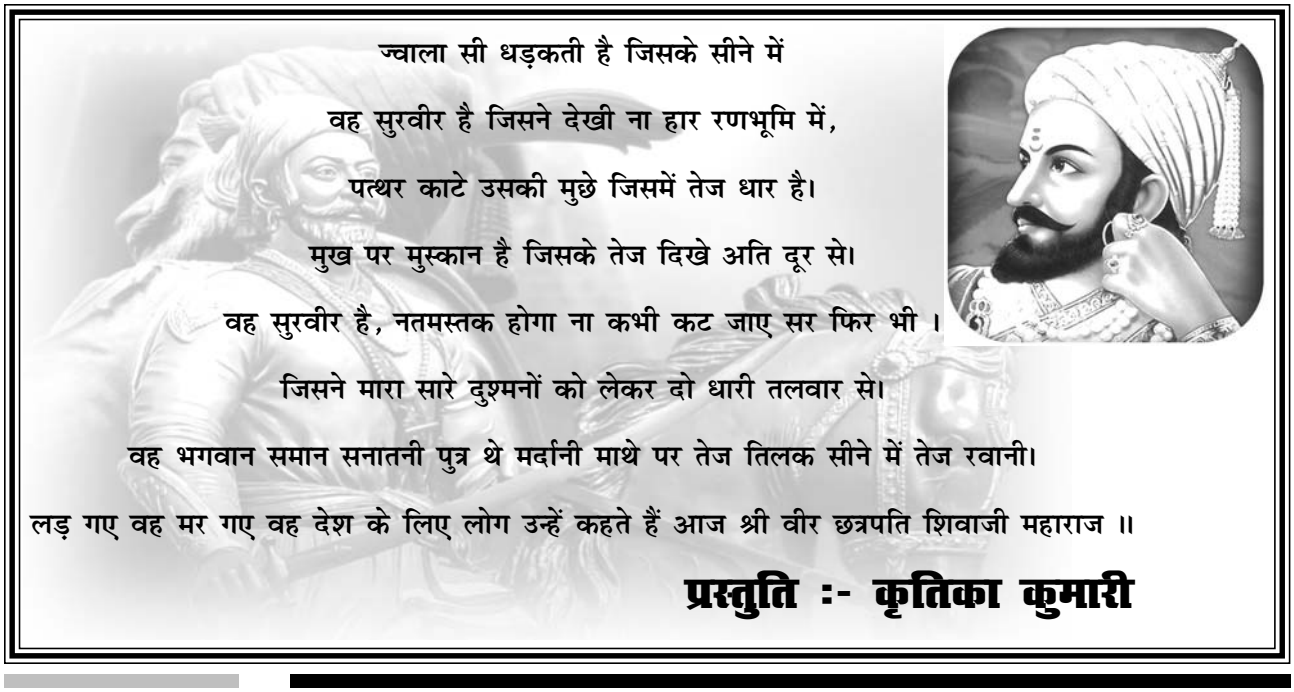

बढ़ती तकनीक और दिल दहलाते रेल हादसे

बेशक बालासोर रेल दुर्घटना देश क्या दुनिया के भीषणतम हादसों में एक है। इतना ही नहीं और याद भी नहीं कि देश में कभी एक साथ तीन रेलें इस तरह टकराई हों? दुर्घटना से जो एक सच सामने आया है वो बेहद दुखद और चौंकाने वाला है जिसमें रिजर्व बोगियों के अलावा मौतें जनरल बोगियों में सवारों की भी हुई। उससे भी बड़ी हमेशा की तरह सच्चाई ये कि यह दुर्घटना स्टेशन पहुंचने से थोड़ा पहले हुई। अप और डाउन दोनों ट्रैक किसी स्टेशन पर पहुंचने से पहले यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कई लूप ट्रैक में विभाजित होकर रुकने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म तक और माल व नॉन स्टाप गाड़ियों को आगे का सीधा ट्रैक पकड़ाते हैं। यहां आगे जा रही या पीछे से आ रही ट्रेनों की स्थिति और निगरानी में जरा सी चूक हादसों में बदल जाती है, यही हुआ। यकीनन ट्रेनों के परिचालन के लिए नित नई उन्नत और नवीनतम तकनीक विकसित होती जा रही है। बावजूद इसके हादसे उतने ही गहरे जख्म भी छोड़ जाते हैं।

दरअसल ये हादसा बहानागा रेलवे स्टेशन के पास शालीमार-चेन्नै कोरोमंडल एक्सप्रेस (12841) और सर एम.विश्वेश्वरैया टर्मिनल-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12864) तथा

मालगाड़ी एक-दूसरे से टकराने से हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर खड़ी मालगाड़ी से टकराई डिब्बे गिरे और लोग निकल जान बचाने इधर- उधर भगाने लगे। ठीक ऊसी समय दूसरे ट्रैक पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12864) आ गई और पहले गिरी दोनों ट्रेनों से टकरा गई। इसके चलते हादसे का रूप भयंकर वीभत्स और दिल दहला देने वाला हो गया। जान बचाकर भागते कई लोग भी शिकार हो गए। सुबह जब ड्रोन से तस्वीरें मिलने शुरू हुई तो रोंगटे खड़े कर देने वाले दर्दनाक मंजरों ने और डरा दिया। जबकि बोगियों के अन्दर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक थीं। किसी का सर धड़ से अलग था किसी के हाथ-पैर और क्षत-विक्षत शरीर। मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर सवारी गाड़ियों के डिब्बे जिग-जैग पोजीशन में एक-दूसरे ऊपर 50-55 फीट तक जा चढ़े। कई डिब्बे सैकड़ों मीटर दूर तक जा फिकाए। दोनों ही ट्रेन अपनी पूरी क्षमता से भरी थीं यानी 1750 यात्रियों को लेकर कुल 3500 यात्रियों की क्षमता के साथ अलग-अलग लेकिन पूरी रफ्तार से दौड़ रहीं थीं। सैकड़ों जाने चली गई और दुर्घटना का शिकार हो गए। पिछले 20 वर्षों में यह सबसे बड़ा हादसा है।

बीते बरस की ही बात है, जीरो रेल

एक्सीडेण्ड मिशन में ऑटो ब्रेक सिस्टम पर तेजी से काम की खूब बातें हुईं। ट्रेन प्रोटेक्शन एण्ड वार्निंग यानी टीपीडब्ल्यूएस तकनीक का ढिंढ़ोरा पिटा। वो प्रणाली बताई गई जिसमें गलती से भी कोई ट्रेन रेड सिग्नल जंप कर जो तो यह वार्निंग प्रणाली उसे रोक देगी। डिवाइस लोकोपायलट के उन क्रियाकलापों को मॉनीटर करेगा जिसमें ब्रेक, हार्न, थ्रोटल हैंडल शामिल हैं। यदि कोई लोको पायलट प्रतिक्रिया नहीं देगा या झपकी लग जाएगी तो ये सिस्टम खुद तुरंत ऐक्टिवेट होकर ब्रेक लगाएगा। यदि ट्रेनों की रफ्तार तय स्पीड से ज्यादा हुई और रेड सिग्नल दिखा तो भी सिस्टम लोको पायलट का रिस्पांस न मिलने पर खुद सक्रिय होगा तथा धीरे-धीरे ब्रेक लगाकर इंजन बंद कर देगा। इस हादसे पर इससे भी बड़ी विडंबना या मजाक ये कि महज एक दिन पहले 1 जून को ही रेल मंत्रालय ने ट्रेन सुरक्षा पर बड़ा चिंतन शिविर किया। नई तकनीकों पर जोरदार पक्ष रखा। रेल के सफर को सुरक्षित और आरामदेह बनाने पर फोकस किया और दावा कि कवच तकनीक से लैस ट्रेनों का आपस में एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। यहां तक कि यदि ये दो ट्रेन आमने-सामने आ भी जाएं तो यह तकनीक उन्हें खुद ही पीछे की तरफ धकेलने लगेगी मतलब ट्रेन का आगे बढ़ना रूक जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कवच की बात सामने आने के चंद घण्टों के भीतर ही यह बड़ा हादसा हो गया। रेलवे बोर्ड से पूरे देश में 34,000 किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाने की मंजूरी मिली है। साल 2024 तक सबसे व्यस्त रेल ट्रैक पर इसे लगाना है। इस कवच की तकनीक को रिसर्च डिजाइन एंड स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन यानी आरडीएओ की मदद से पूरे देश के रेलवे ट्रैक पर शुरू होना है।

हालांकि रेल मंत्री के राज्यसभा में दिए जवाब के मुताबिक यह तकनीक दक्षिण मध्य रेलवे के 1455 रूट पर लग चुकी है। इस पर वर्ष 2021-22 में 133 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि 2022-2023 में 272.30 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है। रेलवे ट्रेन में टीपीडब्ल्यूएस सिस्टम भी लागू कर रहा है जो ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली का वो सिस्टम है जिससे एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। इसमें हर रेलवे सिग्नल इंजन के कैब में लगी स्क्रीन पर दिखाई देगा। लोको पायलट घने कोहरे, बारिश या किसी अन्य कारण से खराब मौसम के बावजूद कोई सिग्नल मिस नहीं करेगा ट्रेन की सही गति भी मालूम होती रहेगी ताकि खराब मौसम में गति नियंत्रित कर सके। जब देश में इन दिनों वन्देभारत ट्रेन शुभारंभ की चमकदार तस्वीरें सामने होती हैं इसी बीच ऐसी दुर्घटनाओं का काला सच तमाचा तो मारता है। जाहिर है लोग सवाल तो पूछेंगे कि क्या देश में केवल लक्जरी ट्रेनों के संचालन को प्राथमिकता है और आम लोगों की रेलगाड़ियां और पटरी पर कोई ध्यान नहीं ? भले ही यह राजनीतिक बहस का विषय बने लेकिन देश में आम सवारी गाड़ियों की हालत ठीक नहीं है।

देश के आम यात्रिओं की सुविधाओं पर भी ध्यान जरूरी है। सबसे कमाऊ रेलवे जोन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का पूरा ध्यान केवल कोयला ढुलाई पर है। यात्री सेवा में यह जोन सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। शायद ही कोई गाड़ी यहां अपने सही पर चलती हो बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग यात्री सुविधाओं के लिए अभिशप्त कहलाने लगा है। तीसरी लाइन का ज्यादातर हिस्सा चालू हो जाने के बाद सुविधाओं में इजाफे की खूब बातें हुई वह बेमानी निकलीं। जरूरी और लंबी दूरी की गाड़ियों की 3-4 घण्टे की देरी से चलना आम तो 8 से 10 घण्टे भी लेट चलना हैरानी भरा नहीं होता। कोयले के खातिर मेन प्लेटफॉर्म तक कोल सायडिंग में तब्दील हो जाते हैं। बिलासपुर रेल जोन का अमलाई स्टेशन सबूत है जिसका मुख्य प्लेटफार्म सायडिंग की बलि चढ़ गया। फिलाहाल बालासोर से 22 किमी दूर घनी आबादी वाले इलाके के पास हुए इस हादसे ने ट्रेन और उससे ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवालों की झड़ी लगा ही दी है। दुर्घटना की शिकार कोरोमंडल एक्सप्रेस में कोई टक्कर रोधी यानी एंटी-कोलिजन उपकरण नहीं होने की बातें भी सामने आ रही जिससे एक ही ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें एक निश्चित दूरी पर रुकती हैं। सवाल

कई हैं और जांचे भी कई होंगी। लेकिन यह सच है कि शाम कुछ लोग सोने की तैयारी में थे तो कुछ रात का खाना खा रहे थे। कइयों के हाथों में खाने का निवाला ही कि वो खुद मौत का निवाला बन गए। काश आम भारतीयों की पहले समय से चलने वाली ट्रेनों व उनके सुरक्षित सफर के लिए भी कुछ सोचा जाता? राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं इसलिए पूरे देश के रेल यात्रियों में उम्मीद की किरण बांकी है।

★ **रेल हादसों की जांच पहले भी हुई :-** भारतीय रेल में होने वाले हादसे इशारा करते हैं कि रेलवे इतिहास के सबक नहीं लेता है। इसलिए रेलवे में हादसों का इतिहास बार-बार खुद को दोहराता है। रेलवे में हर हादसे के बाद मंत्रालय की तरफ से कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की जांच का आदेश होता है। रेलवे में जान या माल या दोनों के नुकसान का जो मामला सीआरएस की जांच के लायक पाया जाता है, उसकी जांच कराई जाती है। इसका मकसद रेल हादसों से सबक लेना और कार्रवाई करना होता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को टाला जा सके। अगर सीआरएस की जांच संभव न हो तो रेलवे में कई बार हादसों या किसी गंभीर घटना की जांच रेलवे के उच्च अधिकारियों की समिति से भी कराई जाती है।

★ **जांच रिपोर्ट की तस्वीर :-** सीआरएस रेलवे के ही अधिकारी होते हैं और उन्हें डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय में पोस्टिंग दी जाती है। बताया जाता है कि ऐसा सीआरएस की जांच को पक्षपात से बचाने के लिए किया जाता है। सीआरएस अपनी जांच में घटना स्थल का दौरा करता है और स्थानीय लोगों से बात भी की जाती है। जांच की प्रक्रिया में चश्मदीद, रेलवे कर्मचारी और मीडिया कवरेज को भी जरूरत के मुताबिक शामिल किया जाता है। दरअसल, हर हादसे के बाद घटना स्थल पर राहत कार्य को फौरन शुरू करना सबसे जरूरी होता है। ऐसे में कई बार क्षतिग्रस्त डिब्बे, पटरी और अन्य चीजों को घटना स्थल से हटाना पड़ता है। इस तरह से घटना स्थल की तस्वीर काफी बदल जाती है और पूरी जानकारी इकट्ठा कर पाना आसान नहीं होता है। लेकिन किसी हादसे की जांच रिपोर्ट और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो इसकी बहुत ही धुंधली जानकारी हमारे सामने होती है। हमने इसके लिए सीआरएस की वेबसाइट से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पाया कि इसके ज़्यादा कॉलम खाली पड़े हैं।

इस वेबसाइट से पता

चलता है कि कई साल पुराने मामलों पर अब भी रेल मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की है, या ऐसी कार्रवाई की जानकारी आम लोगों या मुसाफिरों से साझा नहीं की गई है। हमने हाल के वर्षों में भारत में हुए कुछ बड़े रेल हादसों और उसके बाद रेलवे के एक्शन के बारे में जानने की कोशिश की है।

★ **हादसे पर कार्रवाई :-**

☞ **19 अगस्त 2017 :-** इस दिन उत्तर प्रदेश राज्य के खतौली में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। यहां पुरी से हरिद्वार जा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डब्बे पटरी से उतर गए थे। खतौली में पटरी पर मरम्मत का काम चल रहा था और उसी दौरान ट्रेन को चलने के लिए सिग्नल दे दिया गया। इस हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हुई थी और कई मुसाफिर घायल हुए थे। इस हादसे के फौरन बाद रेलवे के कुछ बड़े अधिकारियों को जबरन छुट्टी पर भी भेजा गया था। पटरी की मरम्मत कर रहे रेलवे के ट्रैकमैन, लोहार और जूनियर इंजीनियर समेत 14 लोगों को फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बाद में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच में पाया गया कि हादसे के लिए केवल रेलवे का जूनियर इंजीनियर जिम्मेवार है, इसलिए बाकि लोगों को नौकरी में बहाल कर दिया गया। इसी हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा रेलवे के बड़े अधिकारी कुछ दिन बाद ही काम पर वापस आ गए थे।

☞ **22 जनवरी 2017 :-** आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के आठ डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में कघ्रीब 40 लोगों की मौत हुई थी। शुरू में इस हादसे को एक षडयंत्र बताया गया था और इसकी जांच में एनआईए को शामिल किया गया था। खबरों के मुताबिक सीआरएस ने तीन साल के बाद इसकी जांच में पाया कि यह हादसा रेल फ्रैक्चर यानी टूटी पटरी की वजह से हुआ था। इसके लिए सीधे तौर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के सिविल इंजिनियरिंग विभाग को जिम्मेवार बताया गया था।

☞ **20 नवंबर 2016 :-** कानपुर के पास पुखरायां में पटना- इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हाससे में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। मोदी सरकार के दौरान हुआ यह पहला बड़ा रेल हादसा था। इस हादसे के पीछे भी पहले किसी तरह के षडयंत्र जताया गया। खबरों के मुताबिक उसी के आधार पर एनआईए ने इसकी जांच भी शुरू की थी। शिव गोपाल मिश्रा बताते हैं कि बाद में इसमें कोई षडयंत्र नहीं पाया गया था। रेलवे की जांच में

पांच रेल कर्मियों को इसके लिए दोषी पाया गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इनमें दो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दो ट्रैकमैन और एक सीईटी शामिल थे।

☞ **20 मार्च 2015 :-** देहरादून-वाराणसी जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में करीब 35 लोग मारे गए थे। यह हादसा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। सीआरएस की जांच में इस हादसे के लिए रेलवे के एक सिग्नल मेंटेनर को जिम्मेवार पाया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।

☞ **10 जुलाई 2011 :-** कानपुर के पास मलवां में हावड़ा से दिल्ली की तरफ आ रही कालका मेल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना में करीब 70 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेलवे को सीसीआरएस की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया था। जुलाई 2011 में कोर्ट ने कहा था कि 2010 के बाद रेलवे ने ऐसे हर मामले पर क्या कार्रवाई की है उसकी जानकारी कोर्ट में सौपी जाए। यानी ऐसी कार्रवाई के बारे में जानकारी के लिए याचिकाकर्ता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था।

★ **छोटे कर्मचारियों पर एक्शन :-** शिव गोपाल मिश्रा हादसे के लिए छोटे कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई पर कहते हैं कि रेलवे में ढाई लाख पद खाली पड़े हैं और इनमें दो लाख सेफ्टी से जुड़े पद हैं जबकि काम हो रहा है स्टेशनों की रंगाई पुताई का। उनके मुताबिक, रेलवे के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने से आज तक कुछ नहीं बदला है। केवल बड़ी बातें करने से नहीं होता है। रेलवे में सिग्नलिंग और सेफ्टी को पुख्ता करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की जरूरत है जबकि पिछले दो बजट में दो सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर (ट्रैफिक) श्रीप्रकाश कहते हैं, रेलवे में जांच के बाद हमेशा कार्रवाई होती है। निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन के पीछे वजह यह है कि जमीनी स्तर पर ट्रेन का संचालन वही करते हैं और उन पर ट्रेनों को सही समय पर चलाने का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। इसी में उनसे गलती भी होती है। श्रीप्रकाश के मुताबिक अगर किसी सिग्नल में कोई खराबी आ जाए तो

मेंटेनेंस रूम जाना होता है और मेंटेनेंस रूम में सुरक्षा के लिहाज से दो ताले होते हैं, जिसकी चाबी दो लोगों के पास होती है। इसे कब खोला गया, कब बंद किया गया, क्या काम किया गया; इन सब बातों को लिखित तौर पर दर्ज करना होता है। इसमें लंबा समय लग सकता है और इस दौरान कोई ट्रेन नहीं चल सकती। इस दबाव में कई बार शॉर्ट-कट तरीका अपनाया जाता है, जिसमें गलती की भी संभावना होती है। भारत में बार-बार होने वाले रेल हादसों के लिए क्या निचले स्तर रेलकर्मी ही जिम्मेदार होते हैं या इसके पीछे कुछ अन्य वजह भी है। इसका जवाब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में मिलता है।

★ **हादसों की सबसे बड़ी वजह :-** सीएजी ने साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच रेलवे में सेफ्टी से जुड़े कई मुद्दों पर गौर कर पिछले साल एक रिपोर्ट सौपी थी। सीएजी ने पाया कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार से पटरी के कंडिशन के बारे में जानकारी जुटाने के मामले में 30 से 100 फीसदी तक की कमी रही है। पटरी के मरम्मत के लिए ब्लॉक (ताकि उस समय कोई ट्रेन न चले) न देने के 32 फीसदी मामले सामने आए जबकि 30 फीसदी मामलों में सबंधित डिविजन ने ब्लॉक लेने और पटरी के मरम्मत का प्लान ही तैयार नहीं किया था। सीएजी ने 1129 जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद रेल हादसे की 24 मुख्य वजहें पाई हैं। ट्रेन के पटरी से उतरने के 422 मामलों में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की गलती पाई गई। इसमें 171 मामले तो केवल ट्रैक के रखरखाव में कमी की वजह से हुए थे। ऐसे हादसों के पीछे दूसरी बड़ी गलती रेलवे के मैकेनिकल विभाग की पाई गई। सीएजी ने इसमें सबसे बड़ी वजह खघ्राब पहिए और कोच का इस्तेमाल होना बताया। ऐसे 154 हादसे ट्रेन के लोको पायलट की गलती से पाए गए। इसमें खराब ड्राइविंग या तय रफ्तार से ज्यादा गति से ट्रेन चलाने की वजह से हादसे हुए थे। ट्रेन हादसों के 275 मामलों में रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग की गलती भी पाई गई। इसमें पाइंट्स यानी आम जुबान में पटरी की गलत सेटिंग को एक बड़ी वजह पाया गया। यानि ट्रेन को जाना किसी और ट्रैक पर था लेकिन उसे किसी और ट्रैक पर भेज दिया गया। सीएजी ने पाया कि रेलवे हादसों से जुड़े 63 फीसदी जांच रिपोर्ट को समय सीमा के अंदर संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपा गया जबकि 49 फीसदी मामलों में संबंधित अधिकारी ने जांच रिपोर्ट लेने में देरी की। ●

80 प्रतिशत लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान कार्ड पुरे देश में बनाया जाना था, इसके लिए नहीं सम्बंधित अधिकारियों कि चिंता है। जबकि इस पर अरबों रुपया पानी के तरह बहाया जा रहा है। भाजपाइयों को नया नारा मिल गया है, 'नौ साल वे मिशाल' के नारा से मस्त है। 90 प्रतिशत लोग आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी तक नहीं है और नहीं बड़े-बड़े पद पर कार्यरत अधिकारियों को भी कोई चिंता है। जबकि सभी प्रदेश संगठन विधायक, सांसद और मंत्री को बूथ पर जाकर सभी योजनाओं के लाभार्थियों को सूची उपलब्ध करना चाहिए। मोदी जी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी संक्षिप्त सूची संक्षिप्त सूची हैं :-

- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज अभियान
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
- प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
- अटल पेंशन योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- मेक इन इंडिया
- स्वच्छ भारत अभियान
- किसान विकास पत्र
- हेल्थ कार्ड स्कीम
- डिजिटल इंडिया
- स्किल इंडिया
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- मिशन इंद्रधनुष
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
- स्वदेश दर्शन योजना
- उड़ान स्कीम
- नेशनल बाल स्वच्छता मिशन
- वन रैंक वन पेंशन स्कीम
- फॉर स्मार्ट सिटी मिशन
- गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम
- स्टार्टअप इंडिया डीजे लॉकर
- इंट्रीकेट पावर डेवलपमेंट स्कीम
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रन मिशन
- सागरमाला प्रोजेक्ट
- प्रकाश पथ
- उज्जवल डिस्कॉम
- विकल्प योजना स्कीम
- नेशनल सपोर्ट
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
- नागामी गंगे प्रोजेक्ट
- भारत प्रोजेक्ट

- रियल एस्टेट बिल
- क्लीन माय कॉच
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- उन्नत भारत अभियान
- टीवी मिशन
- धनलक्ष्मी
- नेशनल प्रमोशन स्कीम
- गंगाजल डिलीवरी स्कीम
- विद्यांजलि योजना
- स्टैंड अप इंडिया
- लोन स्कीम
- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
- सामाजिक अधिकारिता शिविर
- रेलवे यात्री बीमा योजना
- स्मार्ट सिटी मिशन
- भागीरथ
- विजयलक्ष्मी
- लोन स्कीम
- स्वयंप्रभा
- राइट टू लाइट स्कीम
- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव
- उड़ान पूरे देश का
- डिजिटल ग्राम
- ऊर्जा गंगा
- सौर उजाला योजना
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- शहरी हरित परिवहन योजना
- प्रधानमंत्री युवा योजना
- भारत नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम
- राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव प्रवासी
- कौशल विकास योजना
- गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना
- जनधन खाता धारकों के लिए बीमा योजना
- महिला उद्यमियों के लिए योजना
- मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना
- ग्रीन अर्बन स्कीम
- राष्ट्रीय श्री योजना
- प्रधानमंत्री आवास लोन स्कीम
- भारत के वीर पोर्टल
- व्यापारियों के लिए भीम आधार एप
- शत्रु संपत्ति कानून
- डिजीधन मेला
- राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल
- प्राइम मिनिस्टर इम्पलॉयमेंट प्रोग्राम
- प्राइम मिनिस्टर रिसर्च स्कीम
- सोलर चरखा स्कीम
- स्त्री स्वाभिमान
- गोबर धन स्कीम
- मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना
- संकल्प से सिद्धी
- राइज योजना
- कृषि में मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना
- राईट टू लाइट स्कीम
- भीम रेफरल बोनस स्कीम
- शत्रु सम्पत्ति कानून
- ट्रिपल तलाक कानून
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना आदि मौजूद है।

इन सभी योजनाओं को भौतिक सत्यापन करने कि आवश्यकता है। यह जानकारी भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने दिया। ●

इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम जारी किया था डाक टिकट

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कांग्रेसियों से कहा है कि आंखें खोलें? जिस वीर सावरकर का विरोध कर रहे हैं उन्हें इंदिरा गांधी उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की थी। उन्होंने कहा कि विनायक दामोदर वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर भारत को नई संसद मिल गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधि विधान के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही नई संसद को लेकर चल रही बहस भी बेमानी हो गई। भारत को नई संसद का मिलना भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास आजादी के बाद स्वयं का बनाया हुआ संसद भवन होगा। पुरानी संसद 1927 में बनकर तैयार हुई थी। उसे बने 96 वर्ष हो चुके हैं। हर नवसृजन नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार करता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इस मंदिर से भारतीयों को गुलामी की प्रतीक पुरानी संसद से आत्मनिर्भर भारत की नई संसद में पहुंचने का अवसर मिला है। पुरानी संसद बनाने में भी पैसा और श्रम भारत का ही लगा था। नई संसद अब राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक बन गई है। नई संसद इस बात की प्रतीक बन गई है कि देश का लोकतंत्र कितना ताकतवर है। नई इमारत को भारत की पहचान के तौर पर देखा जाएगा। नई इमारत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक भारत की छवि और चमकेगी।

पूर्व में इस बात पर बड़ी बहस होती रही है कि देश को नई संसद की जरूरत है या नहीं। नई संसद बनाने के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं और सैंट्रल विस्टा प्रोजैक्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा लेकिन तमाम बाधाओं के खत्म होने के बाद आज नई इमारत हमारे सामने है। नया संसद भवन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही थी कि संसद भवन अत्याधिक बोझ के नीचे काम कर रहा था। जरा सोचिये जिस इमारत को बने लगभग 100 साल होने को हों उसकी हालत जर्जर तो होगी ही। बैठने की व्यवस्था काफी तंग हो चुकी थी। भारत की राजनीति में समय-समय पर आजादी के नायकों पर विवाद होता रहा है इस वक्त इस विभाग के मुख्य केंद्र बिंदु में है वीर सावरकर। इंदिरा गांधी ने जारी किया था डाक टिकट। इंदिरा गांधी ने कहा था कि सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने की मत करना हमारी आजादी की लड़ाई में अपना अलग स्थान है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कांग्रेस और इंदिरा गांधी की विचारधाराएं अलग है? इंदिरा गांधी ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के योगदान

को पहचाना था उन्होंने साल 1970 में वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था इसके साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर टेस्ट में अपने निजी खाते से 11हजार रुपए डाल दिए थे। इतना ही नहीं इंदिरा गांधी ने साल 1983 में फिल्म डिवीजन को आदेश दिया था कि महान क्रांतिकारी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। वीर सावरकर की दी गई यातनाएं।

वीर सावरकर को 1910 में नासिक के कलेक्टर जैन की हत्या का आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। 1911 में उन्हें अंडमान की जेल में डाल दिया गया जिसे काला पानी से जाना जाता है। काला पानी के दौरान कैदियों को ऐसी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी जिसे सुनकर रुह कांप जाती थी। कोल्हू में बैल की जगह कैदियों का इस्तेमाल, बेड़ियों में जकड़े रहना, कोड़ों से पिटाई? दिल की कोठरियां बदबूदार थी, शौचालय जाने के लिए समय था। नया संसद भवन कुल 64500 मीटर में फैला हुआ है और इसके निर्माण पर करीब 12 सौ करो रुपए खर्च हुए हैं नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की जगह है जबकि राज्यसभा में 384 सांसदों की बैठने की जगह तैयार की गई है वही दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान 1280 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। मौजूदा समय के हिसाब से नए संसद भवन में सारी तैयारियां की गई है। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हाल है जो भवन के बीचोबीच बना हुआ है। इसी के ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है इस हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ,पंडित जवाहरलाल नेहरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के सभी प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई गई है। अब संसद का आगामी सत्र नई इमारत में होगा वहीं से कानून बनेंगे और यहीं से देश चलेगा नई संसद तैयार करने के पीछे यह तर्क था कि अब काफी बदल चुका है गुलामी के प्रतीकों को बदलने का दौर भी आ चुका है, देश की अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नई कहानी गढ़ने के लिए नया संसद भवन अगले शताब्दियों के लिए एक नया रूप गढ़ने को तैयार है। जनता के लिए नए फैसले अब इसी भवन से निकलकर जाएंगे। लोकतंत्र का प्रतीक नया संसद भवन केवल सत्ताधारी दल या विपक्षी दलों का नहीं है यह देश की धरोहर है और यह हर भारतीय का है बेहतर होता है यदि इसके उद्घाटन को लेकर सियासत नहीं होती तब पूरे विश्व में एक जुटता का संदेश जाता।●

फतुहा में स्वास्थ्य शिविर

तीसी कैंसर प्रतिरोधक तथा अनेक रोगों से रखती है दूर

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

माँ तारा उत्सव पैलेस गोविन्द पुर फतुहा पटना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसका अध्यक्षता भाजपा के जुझारू अनील कुमार शर्मा , मुख्य अतिथि डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल, शोभा देवी, रेशमी सिंह पटेल। उन्होंने कहा कि हमारे खाने पीने की आदतों से ही हमारा स्वास्थ्य निर्धारित होता है, हमारे घर में और आसपास ही कई ऐसी खाने की चीजें हैं जिनकी मदद से हम या तो रोगों को दूर कर सकते हैं या दूर रखने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार इन चीजों की मदद से ऐसी अवस्था में भी लाभ होता है जब रोग अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। किडनी डिजीज किडनी में काफी हद तक डैमेज हो जाती है। एलोपैथी में इस अवस्था में सिर्फ डायलिसिस की जा सकती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। जो काफी खर्चीला प्रक्रिया है। इसके अलावा डोनर का मिलना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ खास आहार को अपनाकर और कुछ चीजों में परहेज कर रोग को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

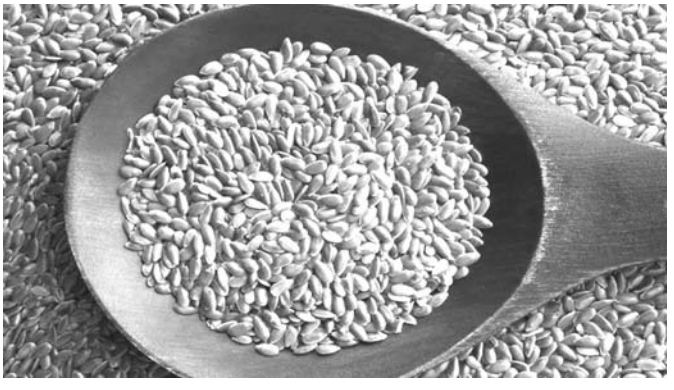

तीसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो दिल, दिमाग तथा खून की नलियों को ताकत एवं पूर्ण जीवन देता है। कैंसर प्रतिरोधक भी है। तीसी में प्रबल एंटीऑक्सीडेंट फाइटो केमिकल लिग्नस पाया जाता है जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर की रोकथाम में उपयोगी होता है। यह बैक्टीरियल तथा फंगल इंफेक्शन से लोहा लेने में सक्षम है।तीसी को पीसकर ही काम में लें। 35 ग्राम तीसी किसी को कूटकर 100 सी सी जल में उबालें ।फिर उसमें डेढ़ चम्मच शहद मिलाकर पींए। यह स्वास, दमा, खांसी में लाभ करता है तथा वीर्य दोष के लिए तीसी को घी तथा शहद में साथ खाएं ,इससे पतला वीर्य गाढ़ा होता है, कब्ज दूर होती है, शरीर शक्तिशाली बनता है। तीसी कुटकर पानी के साथ मिलाकर सूजन पर बांधने से आराम होता है। जल जाने पर तीसी का तेल चूने का साथ मिलाकर जले स्थान पर लगाएं , रक्त संचार को तेज करता है। किसी के प्रयोग से एस्ट्रोजन मेटाबॉलिस्म मे गुणात्मक परिवर्तन होने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना काफी कम हो जाती है किसी के प्रयोग के महान वैज्ञानिक जर्मनी के डॉक्टर योहाना बुडविज 30 सितंबर 1908 को जन्मे तथा 19 मई 2003 को मृत्यु प्रातः हुए। वे भौतिक विज्ञान, जीवन रसायन विज्ञान तथा औषधि विज्ञान में मास्टर डिग्री तथा प्राकृतिक विज्ञान में पीएचडी थे वे आजीवन शाकाहारी रहे। तीसी में मौजूद एसेंशियल फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड पर शोध, शरीर पर प्रभाव का अध्ययन ही उनके शोध का विषय था। सबसे गंभीर विषय है कि तीसी तेल बाजार से गायब है। इस अवसर पर अंकुश कुमार, आशीष कुमार,अमीषा, कुमारी, सीमा कुमारी, पूजा कुमारी जितेंद्र मिस्त्री, बब्लू शाह आदि मौजूद थे।●

मोदी के विरूद्ध शिकायत करने वाले राहुल शीशे में अपनी शक्ल देंखे

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

गुजरात के राजनीतिक फलक पर जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है तभी से देश के कथित लोगों को उनकी जनप्रियता से जलन होने लगी है। जो प्रधानमंत्री को दुनिया में डंका बज रहा है उनके विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर शिकायत करना (देश नीचे दिलाना), गांधी इन दिनों अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर है उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक सम्मेलन में कहा भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम समझते हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया की भलाई के लिए है।भारत कितना बड़ा है कि यदि भारत के लोकतंत्र में बिखराव पैदा होता है तो पुरी दुनिया पर असर पड़ेगा? राहुल जी को बताना चाहिए अपने दादा फिरोज खान को क्यों नहीं जन्म दिवस राहुल ने जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि मनाते हैं। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि मेरे दादा जी कौन हैं और क्यों नहीं जन्म दिवस और पुन्य तिथि मनाते हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने राहुल गांधी को कहा कि आप सार्वजनिक करें कि क्यों नहीं अपने ही दादा का जन्म दिवस और पुन्य तिथि मनाते हैं।●

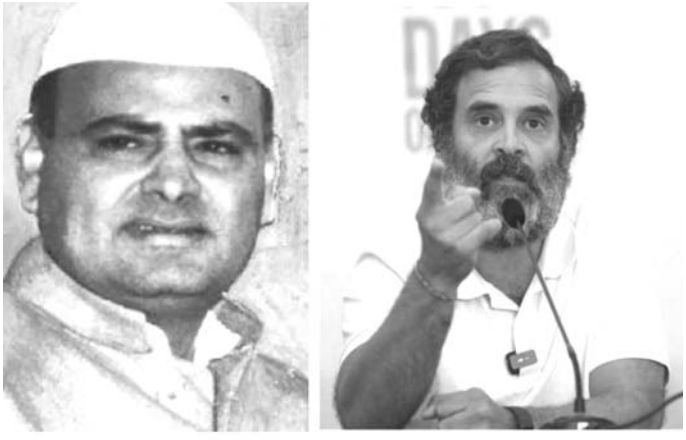

फिरोज खान राहुल गांधी

झाझा विधानसभा के प्रबल दावेदार डॉ.नीरज साह

● प्रो० रामजीवन साहु

डॉ. नीरज साह एक प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। नीरज नाम विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं। इस नाम में कुल तीन अक्षर और एक मात्रा है। जैसे न+ ई +र +ज=नीरज।यानी न से नम्रशीलता,ई से ईमानदारी, र से रक्त और ज से जनसेवा। अर्थात जिस व्यक्ति में नम्रशीलता और ईमानदारी के साथ-साथ रक्त में जनसेवा की भावना कूट-कूट कर भरा हो, वही नीरज कहलाता है।

डा0 नीरज साह का जन्म 26 मार्च 1973 में जमुई जिला केन्द्र से मात्र 25 किलोमीटर उत्तर लक्ष्मीपुर प्रखंड केन्द्र में हुआ है। इनके पिताश्री का नाम श्री देवनाराण साह और माताश्री का नाम पुष्पा देवी है। ये दोनों धर्मपरायणता के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये दोनों प्राणी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की थीं कम से कम मेरे एक पुत्र को डाक्टर बना देना। परमात्मा उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके चार पुत्रों में से एक पुत्र डाक्टर बन गये।इनकी पत्नी का नाम कविता कुमारी हैं, जो रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। इनको भी समाजसेवी में आनंद आता है।

डाक्टर साहब की प्रारंभिक शिक्षा लक्ष्मीपुर से ही सटा हुआ उच्च विद्यालय, बंगरडीह से प्रारम्भ हुई है। इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण के बाद इन्होने मैडिकल की तैयारी में लग गए। मैडिकल डिग्री प्राप्ति के पश्चात अर्थाजन हेतु ये जमुई नगर केन्द्र में अपना प्रैक्टिस प्रारम्भ कर दिये। मृदुभाषी और व्यवहार कुशल होने के कारण कुछ वर्षों के पश्चात ही ये जमुई के सबसे अच्छे डॉक्टरों में गिनती होने लगी। मृदुभाषी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ये वृद्ध महिला से पूछते हैं-चाची की भेल। बहु सेवा नै करै छ।

2006 में ये अपना नया अस्पताल तैयार किये। इस अस्पताल का नामकरण अपने माता -पिता के नाम पर किए 'देव-पुष्पा औरथोपेडिक्स एवं पोली किल्निक सेन्टर' किये

झाझा विधान -सभा में 2020 के अनुसार जातिगत मतदाता अग्रवत है :-		
यादव	-	84069
मुस्लिम	-	35397
सवर्ण	-	26546
अन्य	-	165330
कुल	-	311342

इस अस्पताल ने इनकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिया। आज वे किसी के परिचय का मोहताज नहीं हैं। आज वे सनातनी संस्कारों के अनुसार अपनी आय का दशांश समाज के अभावग्रस्त लोगों के बीच वितरित करते हैं। प्रत्येक रविवार को वे अपने अस्पताल में नहीं रहते हैं। उस दिन वे क्रमानुसार किसी गांव में जाते हैं और लाचार लोगों की सहायता करते हैं। शीतकाल में कम्बल, चादर, ग्रीष्मकाल में जगह-जगह शुद्ध नि:शुल्क पेय जल की उपलब्धता, विद्यार्थियों को पुस्तक, कापी, कलम, पेंसिल, रबर, गरीब लोगों के कन्या विवाह में आर्थिक सहयोग, नि:सहाय मरीजों के नि:शुल्क इलाज, धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर तात्कालीन आवश्यकतानुसार सहयोग करना इनका दिनचर्या बन गया है। इस सेवा का परमात्मा से इन्हें यह प्रतिफल मिला की छोटी लाडली पुत्री निष्का नीरज 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा 97.4% अंक लाकर जिला टापर बनी और बड़ी प्यारी पुत्री कनीका नीरज ने सम्मानजनक 12वीं कक्षा के बोर्ड में 92% अंक लाई।

आपके जानकारी में दूं कि डा0 नीरज साह तेली साहु समाज के जमुई जिला के अध्यक्ष भी हैं। अत:23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को जमुई के सुप्रसिद्ध जय शगुन वाटिका में भव्यता के साथ राष्ट्रभक्त महा दानवीर स्वाभिमानी भामाशाह का 477वां जयंती मनाया गया। इस पावन अवसर पर सांसद संगम लाल गुप्ता, विधायक रणविजय साहु, भामाशाह विचार मंच अध्यक्ष नरेश साहु, अखिल भारतीय तेली साहु समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश नंदन, भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय के सलाहकार रिपुसूदन साहु, अखिल भारतीय तेली साहु महासभा के संगठन सचिव सुभाष घाटे, जमुई जिला पार्षद अनिल साह, मुखिया मुन्ना साव एवं अन्य अनेक जाति पदाधिकारी सम्मलित हुए। सभा आरम्भ के पूर्व जमुई नगर में एक भव्य जातिय जुलूस निकाला गया। जुलूस में लगभग दस हजार व्यक्ति शामिल थे। मोटरसाइकिलों की संख्या 3500 थी। जुलूस और जयंती समारोह ने जनप्रिय, समाजसेवक, कार्यकुशल, मृदुभाषि, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, हमदर्दी, समदर्शी और विवेकशील डॉ० नीरज साह का स्वाभिमान जाग्रत हो उठा और उन्होने खुले मंच से और खुले मन से घोषणा कर दिये कि 2025 में झाझा विधान-सभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। इतना सुनते ही तालियों के गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा। ●

सिक्को से वजन कर सम्राट चौधरी को किया गया सम्मानित

● प्रो० रामजीवन साहु

2 जून 2023 को जमुई नगर स्थित शिल्पा विवाह भवन में बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बिहार परिषद् के सम्राट चौधरी को जमुई जिले के भाजपाईयों ने 107 किलोग्राम शिक्कों से वजन करके उनको सम्मानित किये।

आज श्री सम्राट चौधरी जमुई जिला के यात्रा पर आए। सड़क मार्ग से वे पटना से सर्वप्रथम जमुई जिला के धनराज सिंह महाविद्यालय, पिरिहिन्डा महाविद्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया, उसके बाद सिकन्दरा चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। वहाँ से निकलने के बाद महादेव सिमरिया में स्वागत हुआ। उसके बाद मेहसौरी चौक, अतिथि पैलेस के पास भी बढ़ चढ़ कर स्वागत किया गया।

अपराह्न सवा दो बजे शिल्पा विवाह भवन आये, जहाँ विशेष रूप से स्वागत की तैयारी की गई थी। यहाँ लगभग हजार की संख्या में उनको सुनने के लिए आतुर थे। यहाँ मंच का संचालन जमुई जिला भाजपा के महामंत्री विनय कुमार पांडेय कर रहे थे। वक्ताओं में मुख्य रूप से बेगूसराय लोक -सभा भाजपा के जिला प्रभारी श्री विकास कुमार सिंह ,जमुई भाजपा अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रकाश कुमार भगत, पूर्व जिला अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, जमुई लोक-सभा के प्रभारी रविन्द्र कुमार सिंह (कुल्ली), जमुई विधान-सभा के विधायिका गोल्डेन गर्ल श्रेयसी सिंह थे। अंत में सम्राट चौधरी अपना वक्तव्य दिये। उन्होने कहा कि बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार कहते हैं कि केन्द्र सरकार बिहार को कुछ सहायता नहीं करती है, जब कि बिहार का बजट केन्द्र सरकार के बदौलत ही चल रही है। बिहार के कुल बजट का 76% राशि केन्द्र सरकार देती है।

अंत में प्रखंड में अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पुष्प -हार पहनाकर सम्मानित किये गये। उनमें प्रमुख है:- श्री शैलेन्द्र कुमार तिहारी, शंभूराम चंद्रवशी, शालीग्राम पांडेय आदि। सभा समाप्ति के पश्चात सम्राट चौधरी जी अपने जत्था के साथ साईकिल पर सवार होकर जमुई नगर स्थित गांधी पुस्तकालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर खैरमा को प्रस्थान कर गये। ●

सरकार और पुलिस की लापरवाही का नतीजा है अपराध

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

अपराध रोकना सरकार का काम है ,पुलिस का काम नहीं ? यदि पुलिस अपनी कर्मठता दिखाती है तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अपराध सरकार समाप्त करना नहीं चाहेगी जनता को दिग्भ्रमित रखने के लिए जनता को आश्वासन का खिलौना थमाते ही रहेगी। अपराध में हथियार और कारतूस की आवश्यकता पड़ती है। हथियार भले ही नकली होती है किंतु कारतूस तो असली ही होती है। अभी कारतूस सरकार द्वारा ही सप्लाई की जाती है। जिस पुलिस को अपराध रोकना है उसे हथियार इस्तेमाल करने के लिए कई कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा इस्तेमाल किया गया कारतूस का खोल भी लौटाना पड़ता है। दूसरी ओर पब्लिक को हथियार इस्तेमाल करने के लिए किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस्तेमाल किया गया कारतूस भी वापस नहीं करना पड़ता है, इसमें कितना भी बड़ी। राज छिपा है।

अपराध पर पूर्ण नियंत्रण के लिए कानून बना हुआ है परंतु सरकार कानून का पालन पुलिस से नहीं करवाती है जिसमें राज छिपा हुआ है।कानून बना हुआ है अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करना है तथा कारतूस कहां से उपलब्ध हुआ है यह उद्भेदन करना है परंतु ऐसा नहीं किया जाता है। छापामारी में यदि हथियार बरामद हो जाता है वही अनुसंधान अंतिम है। यदि सरकार ऐसा कदम उठाती है तो अपराध में 90 से 95 प्रतिशत कमी आ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि अपराध नियंत्रण से पूर्व हथियार नियंत्रण जरूरी है। ●

सत्ता के मद में चूर हैं अहंकारी एमएलसी अशोक यादव

कौशल यादव के कुशल प्रबंधन से एमएलसी अशोक यादव के समर्थक की करारी हार

● **अरविंद मिश्रा**

25 मई 2022 को नवादा के नारदीगंज भाग 1 से जिला परिषद का उपचुनाव हुआ, वैसे तो इस चुनाव के मैदान में 9 प्रत्याशी थे, लेकिन मुख्य मुकाबला एमएलसी अशोक यादव गुट से समर्थित उम्मीदवार बाल्मीकि यादव, नवादा के पूर्व जदयू विधायक, और जनप्रिय नेता कौशल यादव के गुट से अति पिछड़ा समाज के देवनंदन चौहान उर्फ देवा चौहान मैदान में थे, इस चुनाव में जात पात, पार्टी ,दारु, मुर्गा और धनबल, बाहुबल का भी खूब प्रदर्शन हुआ, आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ती रही, स्वतंत्र, स्वच्छ, पारदर्शी चुनाव की बात करने वाले राज निर्वाचन आयोग टाय,टाय फीस हो गया, एमएलसी अशोक यादव के नेतृत्व में दो ढाई दर्जन गाड़ियों का काफिला जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी, सहित दर्जनों जिला परिषद सदस्य, यादव समाज के जिला से लेकर, कई समाज के नेता लोकलुभावन नारो और खरीद-फरोख्त में माहिर दर्जनों नेताओं ने गांव-गांव में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, एमएलसी अशोक यादव खुद भी एड़ी चोटी और पसीना बहा बहा कर अपने चहेते उम्मीदवार बाल्मीकि यादव को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जात की खूब दुहाई हुई, इसलिए की जिला परिषद चुनाव में मात्र एक ही यादव उम्मीदवार थे, जबकि भूमिहार समाज से दो उम्मीदवार,कुशवाहा समाज से 2 उम्मीदवार, चौहान समाज से दो उम्मीदवार, और एक ब्राह्मण समाज से, और एक कायस्थ समाज के भी उम्मीदवार थे, लेकिन आम जनता ने भी जाती पाती से ऊपर उठकर, जदयू समर्थित कौशल यादव पूर्व विधायक के नेतृत्व को स्वीकारते हुए पिछड़ा समाज के उम्मीदवार देवानंद चौहान को 8180 वोट देकर विजई बनाया, जबकि एमएलसी अशोक समर्थित उम्मीदवार बाल्मीकि यादव को मात्र 4119 वोट पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि यह बता दें यह जिला परिषद का सीट कई वर्षों से एमएलसी अशोक यादव के परिवार और उनके इर्द-गिर्द ही घूमता रहा, पहले यह सीट उनकी माता जो नवादा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी की धर्मपत्नी प्रमिला देवी जी की कब्जे में था, बाद में प्रमिला देवी जी एमएलसी भी बनी, उसके बाद अशोक यादव लगातार इस सीट पर जिला परिषद सदस्य बने रहे,इस वार अशोक यादव एमएलसी बन गए,और यह सीट रिक्त हो गया, जिस पर 25 मई को उपचुनाव हुआ, और एमएलसी और उनके परिवार का खानदानी गढ़ अहंकार का भेंट में ढह गया, आम जनता यह कहते है अशोक यादव एमएलसी जनता के सुख-दुख से मतलब नहीं रखते हैं, अहंकार में जीते हैं, और पिछले कई चुनाव में उनके द्वारा

कौशल यादव

अशोक यादव

कई झूठे आश्वासन भी दिया गया, इस झूठे आश्वासन से आम जनता अशोक यादव के व्यवहार से काफी क्षुब्ध था, इतना ही नहीं समर्पित राजद कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार कर कई वर्षों से, अशोक यादव अपना साम्राज्य चला रहे थे, जिसका परिणाम जनता ने दे दिया, और कौशल यादव पूर्व विधायक ने देवानंद चौहान को जीताकर दिखा दिया कि जात पात से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए हर वर्गों को सम्मान मिलना आवश्यक है, आज हर वर्गों में पूर्व विधायक कौशल यादव के इस उत्कृष्ट निर्णय का भूरी भूरी प्रशंसा हो रहा है, कौशल यादव एक नायक की भूमिका में, और जनप्रिय नेता के रूप में उनकी ख्याति बढ़ी है, क्योंकि पूर्व विधायक जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने अति पिछड़ा समाज को उठाने का प्रयास किया, यहां के बुद्धिजीवी पूर्व विधायक कौशल यादव को चाणक्य के रूप में उनकी भूमिका को मान रहे हैं,आपको बता दे की अति पिछड़ा समाज की आबादी नवादा में काफी है, और आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां राष्ट्रीय जनता दल कई खेमों में बटा हुआ है, जो नवादा के लिए शुभ संकेत नहीं है, किसी शायर ने ठीक ही कहा है।

'ऐ माना सदा जीत होती नहीं है, मगर समय की चुनौती यही है,
हुकूमत के मध्य में रहे याद इतना, सत्ता किसी की बपौती नहीं है।'

बस यह चुनाव ने दिखा दिया की सिर्फ जाति और लोकलुभावन नारों, वादों, और किसी को खरीद कर सिर्फ वोट नहीं लिया जा सकता है, सच्चा नेता वही है जो जनता के लिए समाज के लिए समर्पित हो, अब आने वाला समय बताएगा ब्लैक हाउस ,और वाइट हाउस का प्रभाव आम जनता के लिए और नवादा के विकास के लिए क्या होगा, नवादा की जनता तो यहां के

जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा रखता है की,

'करना है सो कर दिखलाओ, करो न केवल वादा, यही अपेक्षा आप सभी से करता, प्यारा जिला नवादा।'

आज नवादा में शिक्षा में स्वास्थ्य विभाग में, बिजली विभाग में और भारत सरकार बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें भारी भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, सरकारी कु व्यवस्था है, कई गांव में पानी का हाहाकार है, बिजली विभाग के अकर्मण्यता से आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, नवादा जिला में कई धरोहर है जिसे विकसित करने के लिए कोई योजना नहीं है, मिल डे मील योजना में भारी लूट है, यहां के डॉक्टर अस्पताल में अपनी सेवा नहीं देकर अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न शहरों में प्राइवेट क्लीनिक चला रहे हैं, बालू माफियाओं के आतंक से आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, मनरेगा योजना कामधेनु गाय बनकर रह चुकी है, कुर्सी पर बैठे हुए पदाधिकारी आम जनता के हितों के लिए चिंतित नहीं है, न्याय के लिए पीड़ित जनता आखिर जाए तो कहां,पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों की कटौती हो रही है, आखिर कौन जनप्रतिनिधि आकर नवादा के जनता के लिए सच्चा सेवक बनेंगे यह तो वक्त ही बताएगी, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, उनके नेता सिर्फ जात पात के नाम पर वोट लेकर सिर्फ अपना काम बनाते हैं, उनके विकास के सारी योजनाएं भ्रष्टाचारियों को भेंट चढ़ जाती हैं, चुनाव के बाद कोई भी नेता जल्दी कोई क्षेत्र गांव गलती से भी नहीं जाता है जिसका खामियाजा पार्टी को नेताओं को भुगतना पड़ता है,यह छोटा उपचुनाव, नवादा के नेताओं के लिए एक सबक दे गया है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

फोर लेन सड़क निर्माण कार्य पूरा किये बगैर ही

वाहनों से टोल टैक्स की हो रही बसूली

● मिथिलेश कुमार

बख्तियारपुर से लेकर रजौली तक बनने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ 31 जो निर्माण के बाद 20 हो जाएगी, अभी सड़क निर्माण कार्य पूरा भी नही हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रजौली के पास टोल प्लाजा पर टोल बसूली का कार्य प्रारम्भ हो गया है। जबकि सड़क निर्माण कार्य नवादा जिले के समीपवर्ती सीमा नालन्दा जिला तक भी कार्य पूर्ण नही हो पाया है। खराठ मोड़ से रजौली तक एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य पूर्ण है लेकिन कई ओवर ब्रिज के पास सर्विस रोड भी नही बनाई गई है। गिरियक से लेकर बिहार शरीफ एवं बख्तियारपुर तक अभी 30 फीसदी कार्य बाकी है। बन रहे ओवर ब्रिज के पास न तो सर्विस रोड निर्माण का कार्य पूरा हुआ है और न ही पूल निर्माण कार्य पूरा हुआ है। कई वाहनों के मालिकों ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ पर टोल लगने की स्थिति कमसे कम 50 किलोमीटर तक सड़क निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूरा हो जाय लेकिन नवादा जिले के बीच भी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नही हो सका है। रजौली प्रखण्ड क्षेत्र के करिगांव में टैक्स वसूली के खिलाफ स्थानीय लोगों समेत वाहन मालिक जमकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। रजौली-बख्तियारपुर फोरलेन एनएच 20 पर करिगांव में नवनिर्मित टोल प्लाजा पर 5 जून से टोल टैक्स की वसूली शुरू हुई है। जिसके दो दिन के बाद से ही विवाद गहराने लगा है। स्थानीय वाहन स्वामियों व ग्रामीणों के द्वारा अक्सर टोल प्लाजा के पास तू-तू व मैं-मैं होना शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन की सड़कें पूरी तरह से बनी नहीं हैं,लेकिन टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है,जो कि अवैध है। स्थानीय लोगों ने एनएचएआई के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा नियम है कि जब तक फोरलेन की शुरुआत नहीं होती, तबतक टोल टैक्स वसूली नहीं किया जा सकता। यहां अवैध तरीके से बिना सड़क का निर्माण किए टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं, जो अवैध है।इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक फोरलेन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाए तब तक टोल टैक्स को बंद रखा जाए या फिर स्थानीय लोगों के लिए टोल प्लाजा फ्री की जाए। इसके लिए लोगों ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर स्थानीय लोगों को सहूलियत प्रदान नहीं की जाएगी तो उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जन जागृती फाउंडेशन के लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण अधूरी है और लोगों से टोल टैक्स की वसूली की जाने लगी है, यह लूट नहीं तो और क्या है। अर्द्धनिर्मित सड़क के कारण लोग हिचकोले एवं धूल सनी हवा फांकते हुए सफर करने को मजबूर है। जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द के अलावे कई प्रकार के गम्भीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली करना सरासर लूट है। वहीं ग्रामीण पंकज कुमार, राहुल अठघरा, बीरेंद्र प्रसाद, राजेश यादव आदि ने कहा कि स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लेना बंद किया जाना चाहिए अन्यथा वे आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। प्रखंड क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोगों को अक्सर प्रखंड ऑफिस, अनुमंडल कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में जाना पड़ता है, ऐसे में उन्हें फिजूल में अपने निजी काम के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इसी प्रकार करीगांव में स्थित स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए जाने वाले अभिभावकों पर भी टोल टैक्स की मार पड़ रही है।हालात यह है कि स्थानीय लोग जब भी अपने वाहन लेकर गुजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स मांगा जाता है और झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है।

☞ **फोरलेन सड़क किनारे नहीं बनीं है सर्विस लेन :-** टोल प्लाजा से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित फोरलेन के किनारे गांव सिमरकोल में घनी आबादी के बावजूद सर्विस लेन का निर्माण निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। सम्राट होटल से लेकर धनार्जय नदी तक पुल तो बना दिया गया। लेकिन सर्विस लेन का निर्माण कार्य अधुरा है। जिससे दर्जनों गांव के लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाईयों का

सामना करना पड़ रहा। सिर्फ इतना हीं नहीं सड़क किनारे स्थित कपील देव पेट्रोल पंप भी बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि साइड लेन निर्माण नहीं होने से कोई वाहन पेट्रोल वाहन तेल लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी प्रकार फोरलेन सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों के मुहानो को नहीं बनाया गया है। डिवाइडरों को भी खुला हुआ छोड़ दिया गया है, जिसके कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं होनी आम बात हो गई है।

☞ **समाजसेवी ने डीएम व एसडीएम को दिया पत्र :-** समाजसेवी सुरेन्द्र राजवंशी ने जिलाधिकारी नवादा व एसडीएम रजौली को लिखित आवेदन देकर बताया कि अन्य जगहों पर टोल प्लाजा को पार करने के लिए कोई टैक्स आदि नहीं लिया जाता है। बल्कि टोल प्लाजा के किनारे अवस्थित लेन से नि:शुल्क आने-जाने की सुविधा होती है। समाजसेवी ने टोल प्लाजा पर वसूले जा रहे टैक्स को लेकर उत्पन्न लोगों की समस्याओं का समाधान करने व लोगों का हो रहा आर्थिक दोहन से बचाव हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है।

☞ **क्या कहते हैं टोल प्लाजा अधिकारी :-** टोल प्लाजा हेड कृष्ण मोहन मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के गजट के अनुसार टोल प्लाजा पर निर्धारित दर से टैक्स वसूली की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर तीन फेज पर टोल प्लाजा बनना है। रजौली के करीगांव स्थित टोल प्लाजा पहले फेज में आता है। जिसपर बीते 5 जून से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निजी वाहनों के लिए 330 रुपये प्रति माह पर पास निर्गत किया जाना सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा से 500 मीटर की दूरी तक के सड़क के लिए टोलकर्मी जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि पहले फेज के सड़क पर दुर्घटना होने पर लोगों के इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वहीं जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु रुट पेट्रोलिंग की जाती है एवं सड़क पर गिरे भारी मलवा आदि को उठाने के लिए बड़े हाइड्रा वाहन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एनएचएआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि स्थानीय लोगों को मासिक पास बनवा लेना चाहिए। ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।●

पान किसानों की बढ़ी परेशानी, लागत खर्च में हुआ इजाफा

● **मनीष कमलिया/राजेश प्रसाद**

पकरीबरावां की पहचान यहां के देसी पत्ता पान के लिए भी है। जो 'मगही पान' के नाम से विख्यात है। कभी 'मगही पान' का दबदबा संपूर्ण मगध क्षेत्र में था। लेकिन समुचित प्रोत्साहन के अभाव में यहां पान की खेती दम तोड़ने पर है। किसान धीरे-धीरे इसकी खेती छोड़ रहे हैं। अब तो 60 से 70 एकड़ से भी कम में इसकी खेती होती है। अब किसान इसके बदले पुन: धान, गेंहू, मक्का आदि कि खेती करने लगे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रही, तो यह पान इतिहास बनकर रह जाएगा। हलांकि अभी भी इसकी आपूर्ति बनारस, कलकत्ता से लेकर देश- विदेश तक होती है। यहां पानी का बहुत अभाव है सुखाड़ के कारण किसान पान की खेती से विमुख हो रहे हैं। किसानों के अनुसार पान की फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं मिलती है। अब मात्र 25 प्रतिशत पान की खेती हो रही है।

☞ **क्या कहते हैं पान किसान :-** पकरीबरावां प्रखंड के डोला गावं के पान किसान कुन्दन चौरसिया कहते हैं कि पान की खेती में अब पूंजी वापस होना भी कठिन हो गया है। सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। वहीं सतीश चौरसिया का कहना है कि पान की खेती में अधिक पूंजी और श्रम लगता है, लेकिन उस हिसाब से मुनाफा नहीं है। पाला या अत्यधिक गर्मी में पान की फसल बर्बाद हो जाती है। कहावत है- धान-पान नित्य स्नान। अर्थात पान की फसल को बराबर सिचाई की जरूरत पड़ती है। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। सिचाई की जरूरत बार-बार पड़ने लगी है। गुड्डू चौरासिया कहते हैं- पछिया हवा चलने पर रोज सिचाई चाहिए। सिचाई पत्ते की होती है। एक कट्ठा पान की सिचाई में एक घंटा लगता है। दो से ढाई सौ रुपये खर्च आते हैं। गर्मी से पान के पत्ते को नुकसान पहुंचने लगा है। खरही (पान की लत्ती इसके सहारे खड़ी रहती है) का रेट बढ़ गया है। एक रुपये पीस मिल रहा है। पहले 40 पैसे पीस था। खर्च बढ़ गया है। वहीं पान किसान नंदेलाल चौरसिया का कहना है कि गत सीजन में पाला के कारण संपूर्ण पान की फसल बर्बाद हो गई।

☞ **खो रही बाजार से मगही पान की चमक :-** इस बार झुलसा देने वाली गर्मी से पान की फसल बर्बाद होने लगी है। फसल की जड़ पकड़ते ही सड़ने लगा है। कहा कि ब्याज पर महाजन से रुपये लेकर पान की खेती करने वाले किसान तो बर्बाद होकर रह गए हैं। उनकी तो कमर ही टूट गई है। किसानों ने बताया कि केवीके कौआकोल से विज्ञानिक द्वारा हर सप्ताह देखरेख करने को लेकर आने की बात कही थी पर एक माह होने को है पर अबतक कोई नहीं पहुंचे। वहीं अन्य किसानों ने बताया कि बंगला मीठा पत्ता पान के समय में अब मगही पान की पूछ कम हो रही है। यदि ऐसा ही रहा तो मगही पान को मार्केट से बेदखल कर देगा। मगही पान की चमक बाजार में खोने लगी है। किसान भी अब इसकी खेती में रूचि नहीं ले रहे हैं। किसान अब किसी व्यापार व अन्य फसलों की खेती करने पर ज्यादा जोर दे रही है।●

बाजार की डगर पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा

● मनीष कमलिया/राजेश प्रसाद

पकरीबरावां बाजार की डगर पर अतिक्रमणकारियों का कहर थमने का नाम नही ले रहा है। दिन व दिन अतिक्रमण की समस्या घटने की वजाय बढ़ती ही जा रही है। अतिक्रमण के कारण कहीं सड़क 50 फीट से 15 फीट तो कहीं 30 फीट से 10 फीट पर सिमट गई है। इन सड़कों पर वाहन चलने की बात तो दूर लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी हो रही है। बाजार के मुख्य बाजार के वारिसलिगज चौक से सब्जी मार्केट, थाना रोड होते हुए मोहनविगह बस स्टेड तक मुख्य पथ पर स्थाई व अस्थायी दुकानदारों ने अपनी दुकान को विस्तार रूप देकर सड़क का अतिक्रमण कर लिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है।

पूर्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई थी पहल :- हाल के दिनों में ही अतिक्रमण को लेकर पकरीबरावां बाजार से लेकर गांव तक के लोगों ने शांति समिति की बैठक से लेकर अन्य बैठक में जोरदार आवाज उठाई थी। दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से लोगों की आवाज उठाई थी। खबर प्रकाशित होने के बाद स्थानीय प्रशासन की कुंभकर्णी निंद्रा टूटी और तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी उमेश कुमार भारती की अगुवाई में एसडीपीओ पकरीबरावां, अंचालाधिकारी, थाना की पुलिस के सहयोग से पकरीबरावां में नासूर बनी अतिक्रमण स बाजार की सड़क को मुक्त कराया था। अतिक्रमण हटने से मुख्य बाजार की सड़कें चौड़ी हो गई और इन सड़कों पर जहां लोग रेंगते हुए पैदल चलते थे, वहां चार पहिया वाहन भी सरपट दौड़ने लगी, लेकिन पुनः इन सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। पुनः 2023 में ही अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में पहल भी की, लेकिन सफल नही हो पाई।●

अतिक्रमण पर क्या कहते हैं स्थानीय लोगः-

☞ लंबे अरसे के बाद अतिक्रमण हटाया भी गया तो कोई फायदा नहीं हुआ दस दिन भी अतिक्रमणकारियों ने पुनः अपना पैर पसार चुका है, जिससे लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होती है। स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

पंकज यादव

☞ बाजार में बढ़ते अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर बैठक में कई बार मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अबतक कोई ठोस कारवाई नही हो सकी।

वचनदेव प्रसाद सिंह

☞ सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन जगह उपलब्ध कराए, तभी अतिक्रमण की समस्या से लोगों को निजात मिल सकता है।

मुन्ना साह

☞ अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इस दिशा में प्रशासन को ठोस पहल करनी चाहिए।

इंद्रदेव पंडित

☞ अतिक्रमण हटाने की दिशा में जल्द ही पहल किया जाएगा। सड़क पर दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को पहले प्रचार प्रसार कर सड़क अतिक्रमण मुक्त करने को कहा जाएगा। उसके बाद कारवाई की जाएगी।

नरेंद्र कुमार अंचालाधिकारी, पकरीबरवां, नवादा।

धूम-धाम से मनाया गया सम्पूर्ण क्रांति दिवस

बीते 05 जून 2023 को सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जे०पी० मूर्ति (गांधी मैदान) पर सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में सम्पूर्ण क्रांति दिवस धूम-धाम से मनाई गयीं। मोर्चा फुल माला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुरूआत किया गया। सम्पूर्ण क्रांति के अवसर पर जे०पी सेनानियों ने राजधानी के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला जुलूस मुसल्लहपुर हाट से ब्रह्मदेव पटेल के नेतृत्व में निकल कर भिखना पहाड़ी, मछुआ टोली, सब्जीबाग होते हुये गांधी मैदान जे.पी. मूर्ति पहुँच कर सभा में बदल गया। जुलुश में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल, राकेश राय, सत्य प्रकाश पटेल, ओम प्रकाश मेहता, स्वामी गगन सेन गुप्ता ने जे.पी. की मूर्ति पर फुल-माला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरूआत किया, जिसमें दर्जनों सार्थियों ने अपना विचार रखा। आम सभा में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया। सबसे पहले प्रस्ताव में केन्द्र और राज्य सरकार से महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारों को काम देने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग शिक्षा में सुधार की मांग। साथ ही भूमिगत जे०पी० सेनानी को पेंशन देने की मांग किया गया, पेंशन की राशि बढ़ाकर 25 हजार महीना किया जाय। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 हजार किया जाय। किसानों को गल्ले का उचित दाम तय करने का अधिकार दिया जाये, एम०एस०पी० पर कानून बनाओ। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि जे०पी० सेनानी राजनैतिक दल बनायेगा। मीटिंग में विचार रखने वाले प्रमुख लोगों में ब्रह्मदेव पटेल, रंजीत सिं स्वामी गगण सेन गुप्ता, ओमप्रकाश मेहता, सत्यप्रकाश पटेल, हुमायू अंसारी एवं अन्य लोगों ने विचार रखा। सभा की अध्यक्षता प्रशुराम ठाकुर और संचालन - दिलीप कुमार सिन्हा (एडवोकेट) ने किया। धन्यवाद ज्ञापन धर्मेन्द्र कुमार और मनिष कुमार ने किया। **रिपोर्ट :- अमित कुमार सिंह**

विद्यार्थियों का आंकलन ऑनलाइन नहीं करने पर 33 निजी विद्यालय का यू-डायस प्लस कोड हुआ रद्द

● **मनीष कमलिया/राजेश प्रसाद**

जिला शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई सामने आया है। वर्ष 2022-23 अंतर्गत यू-डायस प्लस पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने वाले 33 निजी विद्यालय का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। संबंधित विभागीय डायरेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा प्रियदर्शी सौरभ ने बताया कि विद्यार्थियों के नाम, उनका पता और आधार कार्ड भी यू-डायस प्लस पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इससे आरटीई का लाभ ले रहे बच्चों का सही आकलन हो सकेगा। इससे पारदर्शिता आएगी। आरटीई के तहत पहली में स्कूल की क्षमता के अनुसार नामांकन लेने का प्रावधान है। लेकिन कई स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और डाटा अपलोड नहीं किया। ऐसे स्कूलों की समीक्षा कर उनका रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया है। इसके बाद इन सभी स्कूलों को सूचना भी दिया जायेगा। इनके उपरांत स्कूल खोला जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नवादा जिले के 91 फीसदी स्कूलों ने यू-डायस प्लस पोर्टल पर आनलाइन के माध्यम से जमा कर दिया गया हैं। 30 अप्रैल तक आनलाइन की अंतिम व 10 तारीख तक सुथार की तिथि दी गई थी।

☞ **इन निजी स्कूलों का रद्द हुआ डायस कोड :-** गौरव इंटरनेशनल स्कूल फतेहपुर अकबरपुर, गायत्री कैरियर स्कूल अकबरपुर, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल अकबरपुर, सनग्लोरी नेशनल एकेडमी अकबरपुर, बाल भवन आवासीय पब्लिक स्कूल हिसुआ, दिव्य शिक्षा अकादमी हिसुआ, ज्ञान सागर आवासीय विद्यालय बड़ी बीघा हिसुआ, आधुनिक गुरुकुल आवासीय विद्यालय हिसुआ, सनराइज इंग्लिश एकेडमी हिसुआ, होली व्यू स्कूल परमा नारदीगंज, उन्नति विद्या मंदिर नारदीगंज, आदर्श पब्लिक स्कूल न्यू एरिया नवादा, आदित्य किड्स अकादमी नवादा, अदितिया पब्लिक स्कूल नवादा, अल रहमान पब्लिक स्कूल नवादा, अवासिया आदित्य पब्लिक स्कूल नवादा, बिहार मॉडर्न पब्लिक स्कूल नवादा, दयान पब्लिक स्कूल अफजल नगर नवादा, डिक्सन स्कूल लाइनपार मिर्जापुर नवादा, डी सलीम पब्लिक स्कूल, पार नवादा, एकरा अकादमी अंसार नगर नवादा, किशोर ज्ञानपीठ नवादा, नेशनल पब्लिक स्कूल नवादा, सरस्वती शिशु मंदिर मिर्जापुर नवादा, सनराइज पब्लिक स्कूल नवादा, विश्व भारती स्कूल नवादा, विवेकानंद पब्लिक स्कूल नवादा, राधिका पब्लिक स्कूल पकरीबरावां, रायबो विद्यालय पकरीबरावां, जेएसके बाल मेमोरियल स्कूल रजौली, आवासीय ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल रजौली, आवासीय ज्ञान ज्योति स्कूल राजौली, बाल संस्कार विद्यालय वारिसलीगंज का यू-डायस कोड रद्द कर दिया गया है।

☞ **जानें क्या है यू-डायस :-** यू-डायस भारत सरकार का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत अब सरकारी व रजिस्टर्ड निजी विद्यालय में पठन-पाठन करने वाले तमाम शिक्षकों व नामांकित छात्रों का नाम-पता के साथ पूरा विवरण केन्द्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड होता है। इसमें लोड होने के बाद सरकार विद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों के बारे में एक क्लिक करने के बाद पूरी जानकारी ले सकेंगे। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।